राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

गौरवशाली भारत

दिल्ली से प्रकाशित

R.N.I. NO. DELHIN/2011/38334 वर्ष- 11, अंक- 112 पृष्ठ - 08, नई दिल्ली, शुक्रवार ,29 अक्टूबर 2021, मूल्य रु. 1.50

भारत शांतिप्रिय देश लेकिन जरूरत पड़ी तो हर चुनौती का सामना करने को तैयारः राजनाथ सिंह

नई दिल्ली,एजेंसी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को कहा कि कोई भी संघर्ष शुरू करना शांतिप्रिय भारत के मूल्यों के विरुद्ध है लेकिन वह किसी भी चुनौती से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहता है. रक्षा मंत्री ने रामगढ़ में टर्मिनल बैलिस्टिक्स अनुसंधान प्रयोगशाला (टीबीआरएल) में यह बात कही जहां उन्होंने संवर्द्धित पर्यावरण परीक्षण केंद्र का उद्घाटन भी किया.

उन्होंने अपने संबोधन में कहा, ''मित्रो, आप जानते हैं कि भारत हमेशा शांतिप्रिय देश रहा है और आज भी है. हमारी तरफ से किसी भी प्रकार के संघर्ष को शुरू करना हमारे मूल्यों के खिलाफ है. लेकिन यह भी उतना ही सही है कि अगर जरूरत पड़ी तो हमारा देश हर चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है.''रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें बुधवार को सैन्य कमांडरों के सम्मेलन में देश के शीर्ष रक्षा अधिकारियों को संबोधित करने का अवसर मिला. उन्होंने कहा, ''इस बारे में विचार-विमर्श हुआ कि समय कितनी तेजी से बदल रहा है. दुनिया के देशों के बीच परस्पर संबंधों, व्यापार, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक और सुरक्षा संबंधी मामलों में यह बदलाव स्पष्ट देखा जा सकता है.'' उन्होंने कहा, ''वैज्ञानिक क्षमताओं और नये अविष्कारों में वृद्धि ने भी सुरक्षा पर बड़ा असर डाला है.''

पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम को याद करते हुए सिंह ने कहा कि वह कहते थे, ''इस दुनिया में डर के लिए कोई जगह नहीं है. केवल एक महाशक्ति दूसरी का सम्मान करती है.'' सिंह ने कहा, ''हम भारत को ऐसा मजबूत भारत बनाना चाहते हैं जो बड़ी से बड़ी महाशक्ति की आंखों में आंखें डालकर देख सके.''रक्षा मंत्री ने कहा कि टीआरबीएल रेंज के दौरे पर उन्हें यहां विकसित किये जा रहे शस्त्रों के बारे में तथा परीक्षण और मूल्यांकन सुविधाओं के बारे में भी जानकारी दी गयी.

सिंह ने कहा कि इस वर्ष अगस्त में उन्होंने एक मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड (एमएमएचजी) भारतीय सेना को सौंपा था जिसकी डिजाइन टीआरबीएल में तैयार की गयी। यह सशस्त्र बलों के लिए निजी क्षेत्र द्वारा निर्मित पहला हथियार है.

रक्षा मंत्री के अनुसार उन्हें बताया गया कि इस ग्रेनेड ने उत्पादन में 99.5 प्रतिशत से अधिक की कार्यात्मक विश्वसनीयता हासिल की. रक्षा मंत्री ने मल्टी-मोड हैंड ग्रेनेड को विश्व स्तरीय करार दिया, जो टीबीआरएल और वैज्ञानिकों की क्षमताओं को दर्शाता है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि निजी उद्योगों को समर्थन दिया जाना चाहिए. राजनाथ सिंह ने टीबीआरएल की अन्य उपलब्धियों को भी सूचीबद्ध किया, जिसमें चौथी पीढ़ी के इलेक्ट्रॉनिक फ्यूज के विकास के उन्नत स्तर तक पहुंचना भी शामिल है, जो समकालीन होने के साथ-साथ सुरक्षित और अधिक विश्वसनीय है.

कुछ का पेगासस जांच के लिए बनी समिति का हिस्सा बनने से इंकार

नई दिल्ली,एजेंसी।

पेगासस जांच समिति में शामिल होने से कई लोगों के इनकार से व्यथित हूं: चिदंबरम

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम ने बृहस्पतिवार को कहा कि वह इस बात को लेकर व्यथित हैं कि कई लोगों ने पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय की ओर से गठित समिति का हिस्सा बनने से विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया।उन्होंने ट्वीट किया, मैं इस बात से व्यथित हूं कि कई लोगों से जब पेगासस मामले की जांच के लिए उच्चतम न्यायालय के आदेश पर बनी समिति का हिस्सा बनने के लिए आग्रह किया गया तो उन्होंने विनम्रतापूर्वक इनकार कर दिया।

पूर्व गृह मंत्री ने सवाल किया कि क्या कोई भी ईमानदार नागरिक राष्ट्रीय हित से जुड़े मामले में सेवा करने संबंधी उच्चतम न्यायालय के आग्रह को ठुकरा सकता है?उन्होंने कहा कि यह घटनाक्रम इस बात का द्योतक है कि यहां लोग महात्मा गांधी के इस कथन से कितने दूर जा चुके हैं कि भारतीय नागरिकों को अपने शासकों से डरना नहीं चाहिए।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने इज़राइली स्पाईवेयर पेगासस के जरिए भारत में कुछ लोगों की कथित जासूसी किए जाने के आरोपों की जांच के लिए बुधवार को विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया। शीर्ष अदालत ने कहा कि प्रत्एक नागरिक को निजता के उल्लघंन से सुरक्षा प्रदान करना जरूरी है और सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा की दुहाई देने मात्र से न्यायालय मूक दर्शक बना नहीं रह सकता।

बेंगलुरू से प्राप्त समाचार के अनुसार उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश आर. वी. रवींद्रन ने बृहस्पतिवार को कहा कि पेगासस जासूसी जांच की निगरानी के बारे में उन्हें अभी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वह इस पर टिप्पणी नहीं कर सकते। शीर्ष अदालत ने उन्हें भारत में चुनिंदा हस्तियों की जासूसी के लिए इजराइली स्पाइवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल की जांच की निगरानी का काम सौंपा है।

75 वर्षीय सेवानिवृत्त न्यायाधीश ने कहा, जब तक मुझे आदेश और संदेश नहीं मिलता है मुझे कुछ पता नहीं होगा। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण की अध्यक्षता वाली पीठ ने बुधवार को कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए आरोपों की जांच के लिए साइबर विशेषज्ञों की तीन सदस्यीय समिति का गठन किया और राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले की जांच की निगरानी का काम न्यायमूर्ति रवींद्रन को सौंपा।

उच्चतम न्यायालय के संदेश की प्रतीक्षा करूंगा : पेगासस जांच की निगरानी पर न्यायमूर्ति रवींद्रन ने कहा

बेंगलुरू। उच्चतम न्यायालय केपूर्व न्यायाधीश आर. वी. रवींद्रन ने बृहस्पतिवार को कहा कि पेगासस जासूसी जांच की निगरानी के बारे में उन्हें अभी आदेश प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए वह इस पर टिप्पणी नही कर सक्ते। शीर्ष अदालत ने उन्हें भारत में चुनिंदा हस्तियों की जासूसी के लिए इजराइली स्पाइवेयर पेगासस के कथित इस्तेमाल की जांच की निगरानी का काम सौंपा है। जांच के बारे में पीटीआई-भाषा के एक सवाल पर न्यायमूर्ति रवींद्रन ने कहा, मुझे आदेश प्राप्त नही हुआ है, इसलिए मुझे पता नही है।

भारत की कड़ी आपत्ति के बाद आई चीन की सफाई, कहा- 'मौजूदा संधियों पर नहीं होगा प्रभाव'

बीजिंग,एजेंसी।

चीन के लैंड बार्डर लॉ पर भारत की कड़ी आपत्ति के बाद अब ड्रैगन की सफाई आई है। चीन ने कहा है कि इसका नया भूमि सीमा कानून मौजूदा सीमा संधियों को प्रभावित नहीं करेगा या सीमा संबंधी सवालों पर देश की स्थिति को नहीं बदलेगा। चीनी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि देशों को चीन के घरेलू कानूनों के बारे में अटकलों से बचना चाहिए। चीन की ये प्रतिक्रिया नई दिल्ली द्वारा कानून के बारे में कड़ा रुख अख्तियार करने के एक दिन बाद आई है। चीन की संसद ने पिछले दिनों एक कानून पारित किया, जिसमें ये बताया गया कि सैन्य और स्थानीय अधिकारी भारत समेत 14 देशों के साथ साझा की गई देश की 22,000 किमी भूमि सीमा को कैसे गवर्न करेंगे और उसकी रक्षा करेंगे।

चीन का नया कानून एक जनवरी से लागू किया जाएगा। इसे भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर जारी लंबे सैन्य गतिरोध के बीच लाया गया है। कानून में देश की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को विशेष जोर दिया गया है। कानून में यह भी कहा गया है कि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने, आर्थिक एवं सामाजिक विकास में मदद देने, सीमावती क्षेत्रों को खोलने, ऐसे क्षेत्रों में जनसेवा और बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने, उसे बढ़ावा देने और वहां के लोगों के जीवन एवं कार्य में मदद देने के लिए देश कदम उठा सकता है। कानून चीन की भूमि सीमाओं की सैन्य रक्षा के साथ जोड़ता है।

भारत द्वारा आपत्ति जताने के बाद गुरुवार को चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि हमें उम्मीद है कि संबंधित देश चीन में कानून के बारे में अनुचित अटकलें लगाने से बच सकते हैं। इस कानून में अपने पड़ोसी देशों के साथ चीन के सहयोग और भूमि सीमा मुद्दों से निपटने पर स्पष्ट शर्तें हैं। ये चीन के मौजूदा सीमा संधियों के कार्यान्वयन को प्रभावित नहीं करेगा। साथ ही ये कानून पड़ोसी देशों के साथ हमारे सहयोग में मौजूदा अभ्यास को भी नहीं बदलेगा। हालांकि, चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कानून सीमा मुद्दों पर चीन की स्थिति को नहीं बदलेगा।

भारत के विदेश मंत्रालय ने चीनी सीमा कानून के बारे में अपनी चिंताओं को व्यक्त करते हुए एक बयान दिया। मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा था, चीन का एकतरफा फैसला एक ऐसा कानून लाने का है, जो सीमा प्रबंधन के साथ-साथ सीमा के सवाल पर हमारी मौजूदा द्विपक्षीय व्यवस्था पर प्रभाव डाल सकता है। इसके बाद सरकार ने बुधवार को कहा कि यह चिंता का विषय है क्योंकि चीन का सीमा प्रबंधन पर वर्तमान द्विपक्षीय समझौतों और सीमा से जुड़े सम्पूर्ण प्रश्नों पर प्रभाव पड़ सकता है।

समझ नहीं आता कि फैबइंडिया के नए संग्रह के नाम में लोगों को गलत क्या लगाः जावेद अख्तर

मुंबई,एजेंसी।

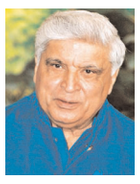

जाने माने पटकथा लेखक जावेद अख्तर ने बृहस्पतिवार को कहा कि उन्हें यह समझ नहीं आता कि लोगों के एक समूह को फैशन ब्रांड फैबइंडिया के नए संग्रह के नाम जश्न-ए-रिवाज में क्या बात गलत लगी जिसका अर्थ केवल परंपरा का जश्न होता है। कुछ लोगों ने ब्रांड पर आरोप लगाया था कि इस संग्रह का नाम जश्न-ए-रिवाज रख कर उसने हिंदू त्योहार दीपावली को विकृत किया। कंपनी ने दक्षिण पंथी समूहों की आलोचना के बाद अपना प्रोमो वापस ले लिया था। 76 वर्षीय अख्तर ने कहा, मुझे यह समझ नहीं आता कि कुछ लोगों को फैबइंडिया के जश्न-ए-रिवाज से समस्या क्यों थी। इसका अंग्रेजी में अर्थ केवल ए सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन (परंपरा का जश्न) है। किसी को कैसे और क्यों इससे दिक्कत हो सकती है? यह पागलपन है। जश्न-ए-रिवाज को लेकर फैबइंडिया को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया था, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि कंपनी हिंदू त्योहार में अनावश्यक रूप से धर्मनिरपेक्षता और मुस्लिम विचारधारा को थोप रही है और इससे उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं।

भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या उन लोगों में शामिल हैं, जिन्होंने ट्विटर पर एक पोस्ट के जरिए इस विज्ञापन की आलोचना की थी।उल्लेखनीय है कि टायर कंपनी सीएट लिमिटेड के विज्ञापन पर भी कुछ लोगों ने आपत्ति जताई थी जिसमें अभिनेता आमिर खान लोगों को सड़कों पर पटाखे न चलाने की सलाह देते नजर आए थे। भाजपा सांसद अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि कंपनी को नमाज के नाम पर सड़कों को अवरुद्ध किए जाने और अजान के दौरान मस्जिदों से निकलने वाले शोर से संबंधित समस्या का समाधान भी करना चाहिए।

आरएसएस की कार्यकारी समिति की बैठक शुरू

धारवाड़। आरएसएस की अखिल भारतीय कार्यकारी समिति ने यहां राष्ट्रोत्थान विद्या केंद्र में अपनी तीन दिवसीय बैठक शुरु की। संघ के एक वरिष्ठ पदाधिकारी ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के विषय पर इस बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया जाएगा।वैदिक मंत्रोच्चार के बीच यहां सत्र आरंभ हुआ।सरसंघ चालक मोहन भागवत और सर कार्यवाह दत्तात्रय होसबाले समेत देश भर से 350 से अधिक लोग शामिल हो रहे हैं।सह प्रचार प्रमुख नरेंद्र ठाकुर ने बैठक से पहले संवाददाताओं से कहा, आज यहां संघ की कार्यकारी समिति की बैठक शुरू हुई।

पीएम मोदी ने आसियान-भारत समिट में की शिरकत, दक्षिण चीन सागर-आतंकवाद समेत कई मुद्दों पर रखी अपनी बात

नई दिल्ली,एजेंसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को वर्चुअली तरीके से 18वें आसियान-भारत शिखर सम्मेलन में भाग लिया. प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत की हिंद-प्रशांत महासागर पहल (आईपीओआई) और हिंद प्रशांत के लिए आसियान का दृष्टिकोण इस क्षेत्र में उनके साझे नजरिए एवं आपसी सहयोग की रूपरेखा हैं. उन्होंने कहा कि आसियान की एकता और केंद्रीयता भारत के लिए सदैव एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता रही है. आसियान की ये विशेष भूमिका भारत की एक्ट ईस्ट नीति का हिस्सा है जो 'सागर' (क्षेत्र में सभी की सुरक्षा और विकास) नीति में निहित है.

बाद में विदेश मंत्रालय ने बताया कि आज 18वें भारत-आसियान शिखर सम्मेलन में दक्षिण चीन सागर, आतंकवाद समेत सामान्य हित और चिंता के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को भी शामिल किया गया. विदेश मंत्रालय ने आगे कहा कि इस दौरान नेताओं ने दक्षिण चीन सागर में शांति, स्थिरता, सुरक्षा और सुरक्षा को बनाए रखने और बढ़ावा देने और नेविगेशन और ओवरफ्लाइट की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के महत्व की पुष्टि की. डिजिटल तरीके से होने वाले इस सम्मेलन में आसियान देशों के राष्ट्राध्यक्ष/शासनाध्यक्ष ने भाग लिया. ये सम्मेलन हर साल आयोजित किया जाता है, जो आसियान और भारत को शीर्ष स्तर पर संवाद का मौका प्रदान करता है.

कारोबार एवं निवेश पर प्रधानमंत्री मोदी ने कोविड महामारी के बाद आर्थिक सुधार के लिये ठोस एवं विविधतापूर्ण आपूर्ति श्रृंखला के महत्व को रेखांकित किया और इस संदर्भ में भारत आसियान मुक्त कारोबार समझौते का उल्लेख किया. प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की हिंद-प्रशांत समुद्री पहल और आसियान का हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए दृष्टिकोण इस क्षेत्र में ''हमारे साझा दृष्टिकोण और आपसी सहयोग'' का ढांचा है. उन्होंने कहा कि 2022 में भारत और आसियान की साझेदारी को 30 साल पूरे हो जाएंगे और इस महत्वपूर्ण उपलब्धि को 'आसियान-भारत मित्रता वर्ष' के रूप में मनाया जाएगा.

मंत्रालय के बयान के अनुसार आसियान देशों के नेताओं ने क्षेत्र में भरोसेमंद सहयोगी के रूप में भारत की भूमिका की सराहना की, खासतौर पर कोविड-19 महामारी के दौरान टीके की आपूर्ति के संबंध में.

ड्रग्स मामले में जमानत मिलने के बाद आर्यन खान की लीगल टीम ने कहा - सत्यमेव जयते

मुंबई । मुंबई क्रूज ड्रग्स केस में अभिनेता शाह रुख खान के बेटे आर्यन खान को बांबे हाईकोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। जमानत का औपचारिक आदेश शुक्रवार को आने की उम्मीद है। उसके बाद ही उनके वकील उन्हें मुंबई की आर्थर रोड जेल से रिहा करवा सकेंगे। नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने मुंबई से गोवा जा रहे क्रूज पर छापा मारकर आर्यन खान को दो अक्टूबर को हिरासत में लिया था। आज इस मामले में उन्हें जमानत मिली है। इस बीच आर्यन खान की लीगल टीम का बयान सामने आया है।

मामले में आर्यन खान का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील सतीश मानेशिंदे और उनकी टीम ने कहा कि आर्यन खान को अंततः बांबे हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा

कर दिया है। के बाद से ही आर्यन के पास कोई ड्रग्स,कोई सेवन,कोई साजिश का सबूत नहीं मिला। सत्यमेव जयते। बता दें कि आर्यन की लीगल टीम ने एक फोटो शेयर की है। इसमें उनके पिता शाह रुख खान भी हैं। आर्यन को जमानत मिलने के बाद सतीश मानेशिंदे और उनकी टीम से शाह रुख ने मुलाकात की।

बता दें कि आर्यन के साथ-साथ इस मामले के दो सहआरोपित अरबाज मर्चेंट एवं मुनमुन धमेचा को भी जमानत मिल गई है। इन तीनों को जमानत मिलने के बाद आर्यन के वकील पूर्व महाधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि अदालत ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट एवं मुनमुन धमेचा को जमानत दे दी है। जमानत का विस्तृत आदेश कल प्राप्त होगा। मैजिस्ट्रेट कोर्ट में एवं विशेष एनडीपीएस कोर्ट में आर्यन का पक्ष रखनेवाले वरिष्ठ वकील सतीश मानेशिंदे ने ईश्वर महान है कहकर अपनी खुशी जाहिर की। अरबाज मर्चेंट के पिता पेशे से वकील असलम मर्चेंट ने कहा कि हम अपने बच्चों के लिए 34,560 मिनट से इंतजार कर रहे थे। बच्चे जेल में परेशान हो रहे हैं।

अदालत ने आर्यन, अरबाज एवं मुनमुन को सशर्त जमानत देते हुए उनपर सात शर्तें लगाई हैं। इन शर्तों के अनुसार उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा। बिना अनुमति के विदेश नहीं जाएंगे। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तथा मीडिया से बात नहीं करेंगे। बता दें कि आर्यन के वकील मुकुल रोहतगी ने उनकी जमानत के पक्ष में तर्क देते हुए इस बात पर जोर दिया था कि आर्यन के पास से न तो ड्रग बरामद हुआ, न ही उनका मेडिकल टेस्ट करवाया गया। उन्हें बहुत ही सतरी सबूतों के आधार पर गिरफ्तार किया गया था।

अफ्रीकी देशों को प्रतिनिधित्व ना मिलना सुरक्षा परिषद की सामूहिक प्रामाणिकता पर धब्बाः एस जयशंकर

नई दिल्ली,एजेंसी। भारत ने गुरुवार को कहा कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता में अफ्रीकी देशों का प्रतिनिधित्व से लगातार इनकार करना परिषद की सामूहिक प्रामाणिकता पर 'धब्बा' है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ` 'संयुक्त राष्ट्र और उप-क्षेत्रीय संगठनों (अफ्रीका संघ) के बीच सहयोग' विषय पर सुरक्षा परिषद की खुली चर्चा को वीडियो लिंक के माध्यम से संबोधित कर रहे थे.

उन्होंने कहा कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को अफ्रीकी आवाज और सोच पर ध्यान देने की जरूरत है. अफ्रीका को अफ्रीकियों से बेहतर कोई नहीं जान सकता. हमने इतिहास में देखा है कि अफ्रीका को शामिल किए बिना अफ्रीकी समस्याओं का बाहरी समाधान पेश करने से अफ्रीकी जनता के हित नहीं सधे हैं. इस संकीर्ण सोच को बदलने की जरूरत है.

विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि सुरक्षा परिषद में ही बदलाव शुरू होना चाहिए.

उन्होंने अफ्रीकी देशों के आतंकवाद निरोधक अभियानों में समर्थन की जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा कि अफ्रीका में आतंकवाद फैलना बहुत चिंता की बात है जैसा कि साहेल, सोमालिया और मध्य तथा पूर्वी अफ्रीका की चुनौतियों से जाहिर है. जयशंकर ने कहा कि सोमालिया में अफ्रीकी संघ के मिशन (एमीसोम), जी-5 साहेल संयुक्त बल और बहुराष्ट्रीय संयुक्त कार्य बल (एमएनजेटीएफ) की पहलों को सुरक्षा परिषद तथा अंतरराष्ट्रीय समुदाय से और अधिक समर्थन की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि अफ्रीका के आतंकवाद निरोधक अभियानों को सहयोग देने के संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस के आह्वान का भारत समर्थन करता है. जयशंकर ने कहा कि भारत अपने खुद के अनुभव से मानता है कि अफ्रीका में संघर्षों की मूल वजह उसके औपनिवेशिक इतिहास में है. साथ ही कहा कि भारत और अफ्रीका एक अद्वितीय और ऐतिहासिक संबंध साझा करते हैं. इस साझेदारी के लिए हमारा दृष्टिकोण 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दस मार्गदर्शक सिद्धांतों के माध्यम से प्रतिपादित किया गया था.

कोरोना महामारी के दौर में मीडिया की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हुईः ओम बिरला

नई दिल्ली । जनसंचार के शिक्षण, प्रशिक्षण तथा शोध के क्षेत्र में गौरवपूर्ण स्थान रखने वाले भारतीय जन संचार संस्थान (आईआईएमसी) में इन दिनों सत्रारंभ समारोह का आयोजन किया जा रहा है। पांच दिवसीय सत्रारंभ समारोह 25 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। कोरोना के कारण इस वर्ष यह कार्यक्रम ऑनलाइन आयोजित किया जा रहा है। समारोह का शुभारंभ 25 अक्टूबर को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया।

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ने पत्रकारिता एवं जनसंचार के विद्यार्थियों को सलाह दी कि वे तथ्यों के आधार पर खबर बनाएं और अपनी रिपोर्टिंग से सकारात्मक और रचनात्मक संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मीडिया लोकतंत्र को सशक्त बनाता है। लोकसभा अध्यक्ष के अनुसार कोरोना महामारी के इस दौर में मीडिया की भूमिका और अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों की जिंदगी बचाने में भी हम कामयाब हुए हैं, लेकिन हमें मीडिया और इंटरनेट मीडिया (सोशल मीडिया) के बीच के अंतर को समझना होगा। उन्होंने कहा कि इंटरनेट मीडिया को भी जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है। बिरला ने आईआईएमसी के सभी विद्यार्थियों को संसद की कार्यवाही देखने के लिए आमंत्रित भी किया।

नवागत विद्यार्थियों का मार्गदर्शन करते हुए आईआईएमसी के महानिदेशक प्रो. संजय द्विवेदी ने कहा कि भारत में मीडिया का प्रभाव पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ा है। मीडिया का इस्तेमाल और उपयोग करने वाले लोग भी बढ़े हैं। तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था के साथ चलते हुए मीडिया आज एक बड़े उद्योग में बदल गया है। प्रो. द्विवेदी के अनुसार सफलता और असफलता से हमारा वर्तमान और भविष्य तय नहीं होता है। जब तक भारत के युवाओं में नया करने का, रिस्क लेने का और आगे बढ़ने का जज्बा है, तब तक हमारे देश के भविष्य की चिंता करने की किसी को जरुरत नहीं है।

कार्यक्रम के प्रथम दिन प्रख्यात लोक गायिका मालिनी अवस्थी ने 1लोक संस्कृति और मीडिया विषय पर अपनी बात रखते हुए कहा कि लोक संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि अखबारों ने लोक संस्कृति को बचाने के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए हैं। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता अनंत महादेवन ने भारत में टीवी और सिनेमा का बदलता स्वरूप और एनडीटीवी की पत्रकार नगमा सहर ने टीवी न्यूज का भविष्य विषय पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया।

समारोह के दूसरे दिन केरल के रायपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि समाज को सूचना देना, सामाजिक सौहार्द बनाए रखना और लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना प्रत्येक पत्रकार का धर्म है। पत्रकारिता के क्षेत्र में लंबे समय तक बने रहने के लिए धैर्य, परिश्रम और प्रतिभा के साथ-साथ तथ्य और सत्य का होना बहुत जरूरी है। खान के मुताबिक मीडिया की आजादी लोकतंत्र का महत्वपूर्ण आयाम है। इसे संभालकर रखना है, लेकिन यह आजादी जिम्मेदारी के साथ आती है। इसलिए हम सभी को जिम्मेदार भी होना है।

रायपाल के अलावा खेती विरासत मिशन, पंजाब के कार्यकारी निदेशक उमेंद्र दत्त ने कृषि संस्कृति और भारत और दूरदर्शन के महानिदेशक मयंक अग्रवाल ने सरकारी सूचना तंत्र विषय पर विद्यार्थियों का मार्गदर्शन किया। इस अवसर पर पैरालंपिक मैडल विजेता सुहास यथिराज ने आईआईएमसी के विद्यार्थियों के साथ अपनी जीत का रहस्य भी साझा किया।

कार्यक्रम के तीसरे दिन देश के प्रख्यात पत्रकार और शिक्षाविद् विद्यार्थियों से रूबरू हुए। इस दौरान भारत का आर्थिक भविष्य विषय पर चर्चा करते हुए गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय, नोएडा के पूर्व कुलपति प्रो. भगवती प्रकाश शर्मा ने कहा कि अगर भारत को आत्मनिर्भर बनना है, तो अपनी उत्पादन क्षमता और आयात की तुलना में निर्यात को बढ़ाना होगा। तकनीकी क्षेत्रों में भारतीय मानव संसाधन पूरी दुनिया में काम कर रहा है, लेकिन इन लोगों के द्वारा तैयार किए गए तकनीकी उत्पाद का फायदा मल्टीनेशनल कंपनियां उठाती हैं। इससे भारतीय ज्ञान और प्रतिभा से प्राप्त मुनाफा विदेशी कंपनियों को प्राप्त होता है। इसे रोकने के लिए भारत को स्वदेशी तकनीक की ओर जाना होगा। उन्होंने कहा कि अगर हम स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे, तो उससे न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ मिलेगा, बल्कि तकनीक के विकास में भी सहयोग होगा।

प्रो. शर्मा के अलावा भारतीय विश्वविद्यालय संघ की महासचिव प्रो. पंकज मित्तल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों से विद्यार्थियों को अवगत कराया। प्रो. मित्तल ने कहा कि भारत की शिक्षा नीति अपनी शिक्षा प्रणाली को छात्रों के लिए सबसे आधुनिक और बेहतर बनाने का काम कर रही है। इस अवसर पर विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय, हरियाणा के कुलपति प्रो. राज नेहरू ने कहा कि जो कौशल हमने सीखा है उसे समाज के प्रयोग में किस तरह लाना है, इस पर कार्य करने की आवश्यकता है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए विद्यार्थियों को नई-नई स्किल सीखनी चाहिए।

सार समाचार

सिंगापुर में कोविड-19 का प्रकोप जारी, रिकॉर्ड 5,324 नए मामले सामने आए

सिंगापुर। सिंगापुर में बुधवार को कोविड-19 के रिकॉर्ड 5,324 नए मामले सामने आए। जिसके बाद देश के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि मामलों में बढ़ोतरी की वजह का पता लगाया जा रहा है। मंत्रालय ने कहा कि संक्रमितों में 661 लोग प्रवासी कामगारों के लिए बने सामूहिक आवास में रहने वाले हैं और 12 लोग विदेशों से देश आए। उसने बताया कि संक्रमण के कारण 10 लोगों की मौत भी हुई है। मंत्रालय ने कहा कि बहुत ही कम समय में संक्रमण के मामलों में हुई असामान्य बढ़ोतरी की वजह पता लगाई जा रही है और अगले कुछ दिन संक्रमण का प्रकोप कैसा रहता है इस पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। सिंगापुर में संक्रमण के कारण अब तक कुल 349 लोगों की मौत हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि बुधवार दोपहर तक कोरोना वायरस से पीड़ित 1777 लोगों का विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा था। यहां अब संक्रमण के कुल 1,84,419 मामले हैं।

इजराइल ने बाहरी समारोहों पर हटाया प्रतिबंध

तेल अवीव। अधिकारियों ने कहा कि इजरायल के मंत्रियों ने शुक्रवार से शुरू होने वाले बाहरी समारोहों के आकार पर कोविड से संबंधित प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। समाचार एजेंसी ने एक आधिकारिक बयान के हवाले से कहा कि प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट और स्वास्थ्य मंत्री नित्जन होरोविट्ज़ ने सभाओं पर प्रतिबंध को रद्द करने पर सहमति व्यक्त की है। कार्यालय ने कहा, शुक्रवार से शुरू होकर, खुले स्थानों पर सभाएं उपस्थिति की सीमा के बिना आयोजित की जा सकती हैं। बाहरी आयोजनों को अभी भी ग्रीन पास के तहत संचालित करने की आवश्यकता होगी, एक एक उपाय था जिसे इजराइल ने 17 अक्टूबर को लागू करना शुरू किया था। ग्रीन पास प्रतिबंध रेस्तरां, सिनेमा, सम्मेलन और होटलों सहित विभिन्न सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश को सीमित करता है। रविवार को, बेनेट ने इजराइल की साप्ताहिक कैबिनेट बैठक में कहा कि देश वर्तमान में डेल्टा लहर से बाहर निकल रहा है।

ताइवान में 2 नवंबर से कोविड प्रतिबंधों में दी जाएगी ढील

ताइपे। ताइवान के कार्यकारी प्राधिकरण ने गुरुवार को कहा कि कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए लगाए गए प्रतिबंधों में 2 नवंबर से ढील दी जाएगी। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट, प्राधिकरण के अनुसार, कराओके बार में फेस मास्क की आवश्यकता नहीं होगी, और सिनेमाघरों या ट्रेनों में खाने-पीने की अनुमति होगी। सभाओं में लोगों की संख्या पर प्रतिबंध भी हटा लिया जाएगा। ताइवान में मई और जून में एक बड़े कोविड -19 के संक्रमण के बाद, दैनिक संक्रमणों की संख्या घट गई है, हाल ही में केवल इम्पोर्ट मामले सामने आए हैं। द्वीप की महामारी निगरानी एजेंसी ने धीरे-धीरे प्रतिबंधों को हटा दिया है, जिसमें ट्रेनों के अंदर खाने की अनुमति, मूवी थिएटरों और बाहरी एथलेटिक्स के लिए मास्क को खत्म करना शामिल है। पिछले साल महामारी की शुरूआत के बाद ताइवान में कुल संक्रमित 16,394 हुए, जिसमें 847 मौतें हुई हैं।

सुपर हाई-राइज बिल्डिंग पर चीन की कार्रवाई

नई दिल्ली। चीन ने देश के छोटे शहरों को सुपर हाई-राइज बिल्डिंग बनाने से प्रतिबंधित किया है। 30 लाख से कम आबादी वाले शहरों में 150 मीटर (492 फीट) से अधिक सुपर हाई-राइज बिल्डिंग बनाने पर प्रतिबंध रहेगा। इससे अधिक आबादी वाले लोगों को 250 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों से प्रतिबंधित किया जाएगा। 500 मीटर से अधिक ऊंची इमारतों पर पहले से ही प्रतिबंध है। बीबीसी की रिपोर्ट, चीन दुनिया की कुछ सबसे ऊंची इमारतों का शहर है, जिसमें 632 मीटर शंघाई टॉवर और 599.1 मीटर पिंग एन फाइनेंस सेंटर शामिल हैं। स्थानीय रिपोर्ट में कहा गया है कि शंघाई और शेनझेन जैसे भीड़-भाड़ वाले शहरों में सुपर हाई-राइज बिल्डिंग की जरूरत हो सकती है, लेकिन अन्य शहरों में जमीन की कोई कमी नहीं है। आकर्षक इमारतों के निर्माण के लिए स्थानीय डेवलपर्स की आलोचना करते हुए, चीन महंगी वैनिटी परियोजनाओं पर नकेल कस रही है।

दक्षिण अफ्रीका नवंबर में राष्ट्रीय उद्यानों तक मुफ्त सुविधाएं कराएगा उपलब्ध

जोहान्सबर्ग। साउथ अफ्रीकन नेशनल पार्क्स (सैनपाक्स) के प्रबंध निकाय ने घोषणा की है कि वार्षिक राष्ट्रीय उद्यान वीक 22-28 नवंबर को आयोजित किया जाएगा, ताकि नागरिकों को इसके ज्यादातर पार्कों तक मुफ्त में पहुंचाया जा सके। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, दक्षिण अफ्रीका की प्राकृतिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत में गर्व की भावना पैदा करने और जैव विविधता की सराहना करने के लिए सैनपार्क्स ने पारंपरिक रूप से सितंबर में एक सप्ताह तक चलने वाले कार्यक्रम की मेजबानी की थी। हालांकि, इन्होंने कोविड-19 महामारी पर चिंताओं के कारण सितंबर में स्थगित करने की घोषणा की थी। दक्षिण अफ्रीका में 19 राष्ट्रीय उद्यान हैं। सैनपाक्स के अनुसार, 2006 में फ्री एक्सेस वीक शुरू होने के बाद से, 5,91,000 से अधिक दक्षिण अफ्रीकियों को राष्ट्रीय उद्यानों में आने का मौका दिया गया है।

ब्रिटेन: मछली पकड़ने पर फ्रांस का नियोजित प्रतिबंध निराशाजनक

लंदन, 28 अक्टूबर (आईएएनएस)। ब्रिटेन सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि फ्रांस की धमकियां निराशाजनक है, क्योंकि फ्रांस ब्रेक्जिट के बाद मछली पकड़ने के अधिकारों को लेकर ब्रिटेन के खिलाफ प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रहा है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, मीडिया रिपोटरें में कहा गया है कि कुछ फ्रांसीसी प्रतिबंध 2 नवंबर से लागू हो सकते हैं, जब तक कि ब्रिटेन के साथ ब्रेक्जिट के बाद मछली पकड़ने के मामले में प्रगति नहीं हो जाती। फ्रांस ने शिकायत की है कि केवल आधे लाइसेंस फ्रांसीसी मछली पकड़ने वाली नौकाओं को ब्रिटिश क्षेत्रीय जल में संचालित करने के लिए दिए गए थे। ब्रिटिश सरकार के प्रवक्ता ने एक बयान में कहा, फ्रांस की धमकियां निराशाजनक है, हम एक करीबी सहयोगी और साथी से यह उम्मीद नहीं करेंगे।

पाकिस्तान में प्रधानमंत्री इमरान खान और सेना प्रमुख बाजवा के बीच क्यों छिड़ा है शीत युद्ध? ये हैं 5 मुख्य कारण

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

एक समय था जब पाकिस्तान के इमरान खान और सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा के बीच दोस्ती हुआ करती थी। जनरल कमर जावेद बाजवा के सेना में कार्यकाल को बढ़वाने के लिए इमरान खान ने कानून बदल दिया था और बाजवा का कार्यकाल बढ़वा दिया था लेकिन अभी कुछ ही साल बीते हैं कि दोनों के बीच तनाव की खबरें आनी शुरू हो गयी। समय-समय में पाकिस्तान में सरकार और सेना के बीच आपसी तनाव देखने को मिला। डीजी आईएसआई चीफ को लेकर यह पूरा बवाल मचा हुआ है लेकिन इस शीत युद्ध में जनरल कमर जावेद बाजवा का पलड़ा भारी रहा और इमरान खान के हाथ कुछ नहीं लगा। चलिए चानते हैं कि कैसे शुरू हुआ बाजवा और इमरान खान के बीच विवाद।

इमरान खान और बाजवा के बीच तनाव की वजह

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने उम्मीदवार लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को पाकिस्तान की जासूसी एजेंसी आईएसआई के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री इमरान खान नहीं चाहते थे कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को इस समय आईएसआई का प्रमुख बनाया जाए। दरअसल इस समय पाकिस्तान और तालिबान के बीच नये सिरे से संबंध बन रहे हैं ऐसे में इमरान खान चाहते थे कि मौजूदा समय में जो वर्तमान प्रमुख है वह ही अपने स्थान पर बना रहे लेकिन जनरल बाजवा चाहते थे कि आईएसआई के प्रमुख को बदलने का यह सही समय है इस लिए नये व्यक्ति को आना चाहिए। दोनों के बीच इसी मुद्दे को लेकर कई बार हाई लेवल की मीटिंग्स भी हो चुकी है लेकिन नतीजे बेअसर हुए। अब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने अपने सैन्य दबदबे और राजनीतिक दोनों को दिखाते हुए लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम को नया आईएसआई

प्रमुख नियुक्त किया और बाजवा के फैसले के आगे इमरान खान की एक नहीं चली।

अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के बीच आई दरार? पोल नंबर्स में गिरावट के बाद कमला हैरिस ने बाइडेन से बनाई दूरी

वाशिंगटन (एजेंसी)।

अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की जोड़ी वहां बहुत पसंद की जाती है। ये जोड़ी अक्सर साथ देखी भी जाती है। लेकिन अब जो बाइडेन और कमला हैरिस साथ नजर नहीं आते हैं। अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने के बाद शुरुआती दिनों में कमला हैरिस ज्यादातर जो बाइडेन के साथ ही नजर आती थीं। लेकिन अब वो मुश्किल से ही किसी कार्यक्रम में बाइडेन के साथ स्टेज शेयर करती हैं। इस वजह से अमेरिका के राजनीतिक गलियारे में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं कि गिरते पोल नंबर्स के बीच क्या कमला हैरिस जो बाइडेन से दूरी बना रही हैं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि दोनों के बीच दरार आ चुकी है।

वैसे ये अटकलें पहली बार अमेरिका के दक्षिणपंथी मीडिया में प्रसारित की गई थी। इन कहानियों को हवा इसलिए मिली क्योंकि सार्वजनिक मंचों पर दोनों कम ही नजर आते हैं। जबकि शुरुआती दिनों में बाइडेन ने नए प्रशासन को बाइडेन-हैरिस प्रशासन कहकर संबोधित किया था। फरवरी में दोनों 38 बार साथ में नजर आए थे। जबकि इस महीने बाइडेन और कमला को सिर्फ सात बार एक साथ देखा गया है।

क्या कहते हैं आंकड़े

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनवरी में दोनों 20

बार एक साथ नजर आए थे। इसके बाद फरवरी में 38 बार दोनों एकसाथ देखा गया। अगस्त में सिर्फ 16 बार दोनों एक मंच पर दिखे और यह आंकड़ा सितंबर में घटकर आधा रह गया। अक्टूबर में अभी तक सिर्फ एक बार बाइडन और हैरिस प्रेस के सामने नजर आए और छह बार डेली ब्रीफिंग और लंच जैसे अवसरों पर एक-दूसरे से मिले।

व्हाइट हाउस ने अटकलों को किया खारिज

हालांकि व्हाइट हाउस ने इन अटकलों को खारिज किया है। अधिकारियों का कहना है कि दोनों के बीच मुलाकात साप्ताहिक लंच पर होती है। इस दौरान राष्ट्रपति की तरफ से उन्हें दिए गए सभी कामों में मदद की जाती है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता इस महीने की शुरुआत में वाइट हाउस ब्रीफिंग में कहा था कि कमला हैरिस बिडेन की पार्टनर हैं। वह उनकी पहली और आखिरी सहयोगी हैं और दोनों एक साथ काम करना जारी रखेंगे। लेकिन आंकड़े दोनों के बीच दूरियों की ओर इशारा करते हैं।

गरीबी की कगार में आए पाकिस्तान की मदद करेगा सऊदी अरब, तीन अरब डॉलर की देगा मदद

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को सुरक्षित जमाओं के रूप में तीन अरब डॉलर और 1.2 अरब डॉलर तथा 1.5 अरब डॉलर मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हो गया है। समाचार पत्र डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक इस हफ्ते पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की सऊदी यात्रा के दौरान हुए समझौते के बारे में औपचारिक घोषणा उनके सलाहकार (वित्त और राजस्व) शौकत तारिन और ऊर्जा मंत्री हम्माद अजहर करेंगे। सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने सऊदी अरब सरकार द्वारा दी जाने वाली सहायता के बारे में ट्विटर बताया।

उन्होंने ट्वीट किया, ''सऊदी अरब ने पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में जमा के रूप में तीन अरब अमेरिकी डॉलर देने पर सहमत होकर पाकिस्तान का समर्थन किया है, और साथ ही वह वर्ष के

दौरान 1.2 अरब अमेरिकी डॉलर के पेट्रोलियम उत्पाद का खर्च भी उठाएगा।'' रिपोर्ट में एक अधिकारी के हवाले से कहा गया कि सऊदी सरकार तत्काल एक साल के लिए पाकिस्तान के खाते में तीन अरब अमेरिकी डॉलर जमा करेगी और कम से कम अक्टूबर 2023 में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) कार्यक्रम के पूरा होने तक इसे जारी रखा जाएगा। इसके अलावा सऊदी सरकार हर साल 1.5 अरब अमेरिकी डॉलर तक का तेल उधार देगी।

सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री ने अमेरिकी नौसेना प्रमुख के साथ की बातचीत

सियोल। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री सुह वूक ने गुरुवार को अमेरिकी नौसेना सचिव कार्लोस डेल टोरो के साथ बातचीत की। इस वार्ता के दौरान उन्होंने कोरियाई प्रायद्वीप की सुरक्षा, द्विपक्षीय गठबंधन और अन्य मुद्दों पर चर्चा की। योनहाप समाचार एजेंसी की रिपोर्ट, रक्षा मंत्रालय के अनुसार, उत्तर कोरियाई मिसाइल लॉन्च की एक हालिया श्रृंखला के बाद, और प्योंगयांग के साथ बातचीत को फिर से शुरू करने के लिए संयुक्त प्रयासों को आगे बढ़ाने के बाद, सियोल और वाशिंगटन ने अपनी रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए रक्षा मंत्री सुह और नौसेना सचिव डेल टोरो के बीच बातचीत हुई। मंत्रालय ने कहा, बैठक के दौरान, डेल टोरो ने उम्मीद व्यक्त की कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया पूर्वोत्तर एशिया में स्थिरता और समृद्धि सुनिश्चित करने और भारत-प्रशांत क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था बनाए रखने के लिए मिलकर काम करेंगे। सचिव ने यह भी कहा कि दोनों देशों की नौसेनाओं और मरीन कोर के बीच घनिष्ठ सहयोग से गठबंधन को और विकसित करने में मदद मिलेगी।

नेपाल ने सरप्लस बिजली के अधिक उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दरों में की कटौती

काठमांडू (एजेंसी)।

नेपाली अधिकारी बिजली दरों में औसतन 2.84 फीसदी की कटौती करके अधिक बिजली की खपत को प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि दक्षिण एशियाई देश जलविद्युत का सरप्लस (अधिशेष) पैदा कर रहा है। समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार, बिजली नियामक आयोग ने उन घरों के लिए ऊर्जा शुल्क माफ कर दिया है जो प्रति माह 20 यूनिट से कम खपत करते हैं, हालांकि उन्हें हर महीने न्यूनतम 30 नेपाली रूपये (24 डॉलर) का सेवा शुल्क देना पड़ेगा है। 150 से 250 यूनिट प्रति माह की खपत करने वाले परिवारों के लिए, दर को आधा रुपया प्रति यूनिट घटाकर 9.5 नेपाली रूपये किया गया है। बिजली नियामक आयोग ने कहा कि अधिक बिजली का उपयोग करने वाले उद्योगों के लिए भी कम दर (टैरिफ) की पेशकश की गई है और नई दरें 17 नवंबर से एक साल के लिए लागू होंगी। आयोग के अध्यक्ष दिल्ली बहादुर सिंह ने प्रेस को बताया, हमने घरों में इलेक्ट्रिक ओवन के उपयोग को बढ़ावा देने, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने और खेतों की सिंचाई के लिए बिजली की सुविधाओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए दरों को कम किया है। उन्होंने यह भी कहा कि सिंचाई सुविधाओं के लिए बिजली की दरों में 40.69 प्रतिशत की कटौती की जानी है। नेपाल के शहरी इलाकों में ज्यादातर घर खाना बनाने के लिए गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं। नेपाल विद्युत प्राधिकरण (एनईए) के अनुसार, देश में वर्तमान में लगभग 2,000 मेगावाट (एमडब्ल्यू) की स्थापित क्षमता है, लेकिन बुधवार को

देश भर में पीक-आवर की मांग 1,500 मेगावाट से कुछ अधिक थी। वहीं अन्य समय में, बिजली की मांग 1,300 मेगावाट से कम हो जाती है। एनईए के प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टाराई ने कहा कि भारत को सरप्लस ऊर्जा बेचने के नेपाल के प्रस्ताव को अभी तक स्वीकार नहीं किया गया है।

अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति को लेकर भारत चिंतित, पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी का बयान

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन के एक शीर्ष अधिकारी ने अमेरिकी सांसदों से कहा कि अफगानिस्तान की वर्तमान स्थिति को लेकर भारत चिंतित है। नीतिगत मामलों के लिए अवर रक्षा सचिव कॉलिन एच कहल ने अफगानिस्तान, दक्षिण एवं मध्य एशिया सुरक्षा पर सुनवाई के दौरान सीनेट की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्यों से कहा, ''मुझे यकीन है कि आप इस बात से अवगत हैं कि वे (भारतीय) अफगानिस्तान की स्थिति को लेकर चिंतित हैं। वे वहां की अस्थिरता और आतंकवाद विरोधी अपनी चिंताओं को लेकर परेशान हैं। कहल ने कहा, '' वे (भारतीय) इन मुद्दों पर हमारे साथ काम करना चाहते हैं, खुफिया जानकारी साझा करने समेत जहां भी हम उन्हें सहयोग कर सकते हैं। यह हमें न केवल अफगानिस्तान

के संबंध में और आतंकवाद के खिलाफ, बल्कि हिंद महासागर और हिंद-प्रशांत में व्यापक क्षेत्रीय सुरक्षा विषयों पर भारत के साथ सहयोग के अवसर प्रदान करता है।'' कहल ने यह बयान सीनेटर गैरी पीटर्स के एक सवाल के जवाब में दिया। उन्होंने कहा, '' अफगानिस्तान के प्रति भारत की नीतियों की कल्पना बड़े पैमाने पर पाकिस्तान के साथ प्रतिस्पर्धा और छद्म संघर्ष को ध्यान में रखकर की जाती है। यह भी एक कारण है कि भारत को इस आशंका को लेकर कम चिंतित नहीं होना चाहिए कि तालिबान सरकार, भारत विरोधी आतंकवादी संगठनों को फायदा पहुंचा सकती है, खासकर जो कश्मीर के आसपास हैं। उन्होंने कहा, '' इस महत्वपूर्ण भागीदार के साथ संयुक्त सहयोग तथा मिलकर काम करने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता और यह तथ्य कि भारत, अमेरिका का एकमात्र नामित प्रमुख रक्षा भागीदार है,....मेरा मानना है कि हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि अफगानिस्तान के प्रति उसका दृष्टिकोण कैसा है और आगे कैसा रहेगा। सीनेटर जैक रीड के एक अन्य सवाल के जवाब में कहल ने कहा कि पाकिस्तान एक चुनौतीपूर्ण भूमिका पेश करता है, लेकिन वह नहीं चाहता कि अफगानिस्तान आतंकवादी हमलों या बाहरी हमलों के लिए सुरक्षित पनाहगाह बने।

अमेरिका की पूर्व राजनयिक हेली और सांसद वाल्ट्ज ने भारत के साथ गठबंधन करने की अपील की

वाशिंगटन। (एजेंसी)।

संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका की पूर्व राजदूत निकी हेली और सांसद माइक वाल्ट्ज ने भारत एवं अमेरिका के बीच गठबंधन का आह्वान करते हुए कहा कि इससे दोनों देशों को क्षेत्र में चीन के आक्रामक रुख के बीच अपनी वैश्विक ताकत को बरकरार रखने और विस्तार देने में मदद मिलेगी। वाल्ट्ज प्रतिनिधि सभा की सशस्त्र सेवा समिति के सदस्य हैं और 'इंडिया कॉकस' के रिपब्लिकन उपाध्यक्ष हैं। हेली और वाल्ट्स ने प्रतिष्ठित 'फोरेन पॉलिसी' पत्रिका के ताजा संस्करण में लिखा, ''10 लाख से अधिक सैन्यबलों वाली एक परमाणु शक्ति के रूप में, मजबूत होती नौसेना और एक शीर्ष स्तरीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के साथ और अमेरिका के एक पुराने आर्थिक एवं सैन्य सहयोगी के रूप में भारत एक मजबूत साझेदार बनेगा।''

उन्होंने कहा, ''भारत के साथ गठबंधन से दोनों देशों को अपनी वैश्विक ताकत को बरकरार रखने और विस्तार देने में मदद मिलेगी तथा अमेरिका जापान एवं ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर अफगानिस्तान में संभावित आतंकवादी खतरों और चीन के लिए एक वास्तविक अवरोधक बनेगा।''

हेली और वाल्ट्स ने लिखा कि अफगानिस्तान से अमेरिकी बलों की वापसी के बाद केवल भारत ही वहां प्रभावी ढंग से सतर्कता से नजर रख सकता है और केवल वही चीन की गतिविधियों पर नजर रख सकता है। दोनों रिपब्लिकन नेताओं ने कहा कि अमेरिका और भारत के बीच गठबंधन चीन को मध्य एवं दक्षिणी एशिया में और विस्तार देने से रोकेगा। उन्होंने कहा, ''यह गठबंधन क्षेत्र की बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं को भी पहचानेगा। भारत के प्रति चीन का हालिया आक्रामक रुख कोई संयोग से नहीं है। यह एक व्यापक योजना का हिस्सा है। भारत के लंबे समय से शत्रु रहे पाकिस्तान से समर्थन मिलने के बाद 'चीन की कम्युनिस्ट पार्टी' (सीसीपी) का हौसला बढ़ा है।

म्यांमार में तख्ता पलट के बाद सेना का दिखा निर्दयी रूप, बिजली के झटके, पिटाई और दी जा रही यातनाएं

इस्लामाबाद। (एजेंसी)।

जकार्ता। एक भिक्षु को शर्मिंदा करते हुए उन्हें एक मेंढक की तरह चलने पर मजबूर किया, एक लेखा अधिकारी को बिजली के झटके दिए गए और एक कलाकार के सिर पर तब तक चोट की गई जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। म्यांमार में इस साल फरवरी में तख्तापलट किए जाने के बाद से सेना उन लोगों को यातनाएं दे रही है जिन्हें उसने देशभर से बड़े ही सुनियोजित तरीके से हिरासत में लिया था। एपी की जांच में यह पता चला है। म्यांमार में सेना ने युवाओं और लड़कों समेत हजारों लोगों को अगवा किया, शवों और घायलों का इस्तेमाल आतंक फैलाने के लिए किया और वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के दौरान चिकित्साकर्मियों पर जानबूझकर हमले किए।

फरवरी से अब तक सुरक्षा बलों ने 1,200 से अधिक लोगों की हत्या की जिनमें से अनुमानतः करीब 131 लोगों को यातनाएं देकर मार डाला। सेना द्वारा प्रताड़ित किए गए कुछ लोगों की कहानियांः सेना की पकड़ से भागते समय 31 वर्षीय भिक्षु को गोली मारी गई, उन्हें हथकड़ी लगाई गई और डंडों तथा राइफलों से पीटा गया। सुरक्षा बलों ने उनके सिर, छाती और पीठ में लात मारी। उन्होंने आपराधिक इरादे के सबूत बनाने के लिए भिक्षु और अन्य प्रदर्शनकारियों की गैसोलीन की बोतलों के साथ फोटो खिंचवाई। सैनिकों ने भिक्षु को आम लोगों जैसे कपड़े पहनने को मजबूर किया और उन्हें मांडले पैलेस में बनाए गए उत्पीड़न केंद्र भेज दिया। भिक्षु कहते हैं, ''वह पूछताछ केंद्र किसी नर्क की तरह था।'' भिक्षु को मेंढ़क की तरह चलने पर मजबूर किया गया, उन्हें ऐसे बंदीगृह में रखा गया जहां शौचालय नहीं था। कैदियों को एक कोने में पेशाब करना पड़ता था और प्लास्टिक की थैलियों में मल त्याग करना होता था। छह दिन बाद भिक्षु को पुलिस थाने भेजा गया जहां उन्हें 50 अन्य कैदियों के साथ एक काल कोठरी में रखा गया। वहीं भी यातनाएं जारी रहीं। पुलिस थाने में 21 साल के लेखापाल की पूछताछ शुरू हुई, उसे लात घूंसों से पीटा गया उसके सिर पर मारा गया। फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांधकर उसे यंगून के पूछताछ केंद्र ले जाया गया। एक सैनिक ने उससे पूछा कि श्रृंखलाबद्ध बम विस्फोटों से उसका क्या संबंध है। जब उसने किसी भी संबंध से इनकार किया तो उसे फिर बुरी तरह से पीटा गया।

सैनिकों ने पीवीसी पाइप से उसकी पीठ पर मार की और छाती पर लात मारी। वह उसे शरीर के केवल उन्हीं हिस्सों पर मारते थे जिन्हें कपड़ों से छिपाया जा सके। वह बेहोश हो चुका था। उसके सिर पर बर्फ का पानी डालकर उसे जगाया गया। इसके बाद उसे बिजली के झटके दिए गए। उसे पूछताछ केंद्र से तब जाकर छोड़ा जब उसके परिजनों ने अधिकारियों को पैसे दिए। लेकिन इसके तुरंत बाद सैनिक उसे एक अन्य पूछताछ केंद्र ले गए। जहां उसे बुरी तरह से फिर मारा पीटा गया और गहरे काले अंधेरे कमरे में रखा गया। आखिरकार उसे उस बयान पर हस्ताक्षर करने पड़े जो पहले से तैयार किया जा चुका था। लेखापाल के पिता ने फिर से पैसे दिए जिसके बाद उसे छोड़ा गया। एक युवा कलाकार के अनुभव भी कुछ ऐसे ही रहे। सुरक्षा बलों ने एक प्रदर्शन के दौरान 21 साल के कलाकार को गिरफ्तार किया और उसके सिर पर तब तक मार की जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। जब वह जागा तो उसने सुना की एक सैनिक कह रहा था, ''तीन लड़कों को मौत के घाट उतार चुका हूं।'' कलाकार बताता है, ''वह हमें जान से मारने वाले थे।'' लेकिन तभी स्थानीय पुलिस वहां आ गई और उसने सैनिकों से कहा कि वह इस युवक की हत्या नहीं कर सकते हैं। इसके बाद कलाकार को पुलिस थाने और उसके बार यंगून के पूछताछ केंद्र ले जाया गया जहां उसे चार दिन रखा गया। उसने कहा, ''पूछताछ केंद्र जाने के बाद मैंने कोशिश की कि कोई उम्मीद न रखूं।''

लिंगानुपात में आया सकारात्मक बदलाव : सिसोदिया

सामाजिक जागरूकता को दर्शाती है लिंगानुपात दर में हुई यह वृद्धि

राजधानी में 2020 में लिंगानुपात बढ़कर हुआ 933

नई दिल्ली, प्रफुल्ल राय(शिवालिक)।

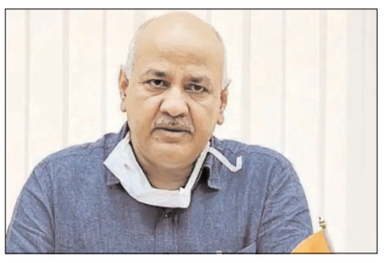

दिल्ली में 2020 के दौरान जन्म के दौरान लिंगानुपात दर बढ़कर 933 हो गई है। 2019 में ये आंकड़ा 920 था। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली सरकार के वार्षिक रिपोर्ट में बताया गया कि दिल्ली में वर्ष 2019 की तुलना में 2020 में लिंगानुपात दर में सकारात्मक वृद्धि हुई है। इस मौके पर उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि लिंगानुपात दर में हुई ये वृद्धि सामाजिक जागरूकता को दर्शाती है। ये बेहद खुशी की बात है कि हमारा समाज शिक्षित हो रहा है और बच्चियों के महत्व को समझ रहा है। अर्थशास्त्र और सांख्यिकी निदेशालय, दिल्ली सरकार के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में शिशु मृत्यु दर में भी 2019 की तुलना में गिरावट देखने को मिली है। 2019 में शिशु मृत्यु दर प्रति हजार 24.19 थी जबकि 2020 में ये घटकर 20.37 रह गई। उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने शिशु मृत्यु दर में आई इस गिरावट को हेल्थ-वर्कर्स के प्रयासों का नतीजा बताया। उन्होंने कहा कि शिशु मृत्यु दर में आई ये गिरावट दिल्ली के सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के बेहतर होने का नतीजा है। सिसोदिया ने आगे बताया कि दिल्ली में मातृ मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिली है। 2019 में मातृ मृत्यु दर 0.55 थी जो 2020 में घटकर 0.54 प्रति हजार जन्म रह गई। दिल्ली में पब्लिक अवर्नेस कैंपेन के भी सकारात्मक परिणाम देखने को मिले हैं।

दिल्ली में जन्म दर 2019 की तुलना में 18.35 प्रति हजार की तुलना में घटकर वर्ष 2020 में 14.85 प्रति हजार रह गई। वर्ष 2020 के दौरान, कुल 3,01,645 जन्म दर्ज किए गए, जबकि 2019 में यह 3,65,868 था। दिल्ली के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हुए शानदार बदलाव और सभी नागरिकों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच से दिल्ली में मृत्यु दर में भी कमी देखने को मिली है। आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2019 में मृत्यु दर 7.29 के मुकाबले 2020 के दौरान घटकर 7.03 प्रति हजार रह गई है।

पेरेंट्स संवाद कार्यक्रम दुनिया में अपनी तरह का अनूठा कार्यक्रम : सिसोदिया

दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पेरेंट्स संवाद कार्यक्रम शुरू

नई दिल्ली। पेरेंट्स को स्कूलों से जोड़कर अपने बच्चों की शिक्षा में उनकी भागीदारी को बढ़ाने और बेहतर पेरेंटिंग के गुर सिखाने के लिए गुरुवार को दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पैरेंटल आउटरीच प्रोग्राम के तहत 'पेरेंट्स संवाद' कार्यक्रम को लांच किया गया। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य पेरेंट्स व स्कूलों को आपस में जोड़ना ताकि दोनों के समावेश के साथ बच्चों को बेहतर शिक्षा के साथ-साथ बेहतर पेरेंटिंग भी मिल सके। स्कूल मित्रों की सहायता से पेरेंट्स को उनके बच्चों के साथ संवाद करना और एक बेहतर कम्युनिकेशन स्थापित कर पेरेंट्स को उनके बच्चों की पढ़ाई और वेल-बींग के प्रति जागरूक करना है। इस कार्यक्रम के तहत 35000 से ज्यादा स्कूल मित्र और स्कूल मैनेजमेंट कमिटी मेंबर्स स्कूल और पैरेंट्स को जोड़ने को काम करेंगे जिससे दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 18 लाख से ज्यादा बच्चे लाभान्वित होंगे। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि 'पेरेंट्स संवाद' कार्यक्रम दुनिया में अपनी तरह का अनूठा और सबसे बड़ा पैरेंट आउटरीच प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम से 18 लाख बच्चों के पेरेंट्स स्कूल से सीधे वन- टू-वन मोड में जुड़ेंगे। आज देश में पैरेंटिंग के पैटर्न पर काम करने की जरूरत है।

आज तीन तरह की पैरेंटिंग हमारे बीच प्रचलित जीरो पैरेंटिंग, ओवर पैरेंटिंग और मित्रवत पैरेंटिंग। तीनों ही केस में बच्चे का नेचुलरल ग्रोथ नहीं होता है। 'पेरेंट्स संवाद' कार्यक्रम पेरेंट्स व स्कूल के बीच संवाद को बढ़ाएगा, साथ ही पैरेंट्स को बच्चों के लिए उचित राह भी सुझाएगा। कोरोना महामारी के दौरान ये सवाल उठकर आया कि बच्चों की शिक्षा सही तरीके से कैसे हो पाएगी व ऑनलाइन शिक्षा में आने वाली बाधा को कैसे दूर किया जा सकता है? कैसे बच्चों को तनाव की स्थिति में सहयोग दिया जा सकता है व पैरेंट का सहयोग बच्चो की शिक्षा में किस तरह से बढ़ाया जा सकता है।

हाईकोर्ट का सवाल- नाबालिगों को नहीं होगी शराब की होम डिलीवरी, इसे कैसे सुनिश्चित करेगी दिल्ली सरकार

नई दिल्ली,(एजेंसी)। उच्च न्यायालय ने बुधवार को दिल्ली सरकार से यह बताने के लिए कहा है कि 'यह कैसे सुनिश्चित होगा कि होम डिलीवरी योजना के तहत कम उम्र के लोगों को शराब मुहैया नहीं कराई जाएगी। न्यायालय ने सरकार से यह भी स्पष्ट करने के लिए कहा है कि इस योजना में यह कैसे पता चलेगा कि जो व्यक्ति शराब खरीदने का ऑर्डर कर रहा है, उसकी उम्र क्या है।

नई अबकारी नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी करने की सरकार की योजना के खिलाफ दाखिल जनहित याचिका पर विचार करते हुए न्यायालय ने यह सवाल किया है। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने सरकार से यह भी बताने के लिए कहा है कि शराब की होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर करने वाले व्यक्ति की उम्र सत्यापित करने की प्रक्रिया क्या होगी।

न्यायालय ने सरकार से कहा कि आप शराब खरीदने वाले की उम्र का सत्यापन कैसे करेंगे, आपको इन सवालों का जवाब देना होगा। न्यायालय ने सरकार से कहा कि आप यह नहीं कह सकते कि इसका जवाब नहीं देंगे। इस पर दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राहुल मेहरा ने पीठ को बताया कि फिलहाल यह सिर्फ मौजूदा नियम में संशोधन है और यह अभी प्रभाव में नहीं आया है। मेहरा ने कहा कि जब भी यह संशोधन अस्तित्व में आएगा, शराब की होम डिलीवरी करने के लिए ऑर्डर करने वाले ग्राहकों के आधार संख्या या कोई अन्य आयु प्रमाण देने का प्रावधान किया जाएगा। नई नीति के तहत राजधानी में शराब पीने की वैधानिक उम्र 21 साल है।

उच्च न्यायालय भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई कर रहा है। वर्मा ने नई अबकारी नीति के तहत शराब की होम डिलीवरी करने की सरकार की योजना को न्यायालय में चुनौती दी है। उन्होंने कहा है कि शराब की होम डिलीवरी की योजना में उम्र की निगरानी की कोई प्रक्रिया नहीं तय की गई है। इससे कम उम्र के लोगों को भी शराब मुहैया कराई जा सकती है। याचिकाकर्ता की इस दलील का विरोध करते हुए दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि शराब की होम डिलीवरी से घर के बच्चों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि होम डिलीवरी की व्यवस्था पिछले 25 से 30 सालों से है, लेकिन अभी इसके तौर-तरीके बदल गए हैं। सिंघवी ने कहा कि पहले शराब की होम डिलीवरी के लिए ऑर्डर ई-मेल या फैक्स के जरिए होता था। अब इसे किसी मोबाइल एप के जरिए करना होगा। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी।

संक्षिप्त खबर

जलजनित रोगों के खिलाफ आयोजित

नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविन्द केजरीवाल के निदेशनुसार दिल्ली में डेंगू मुक्त अभियान चलाया गया। वार्ड-22 ई अनारकली की निगम पार्षद रेखा दीक्षित के नेतृत्व में वार्ड 22-ई में डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के खिलाफ बड़ी फीफा मशीन के द्वारा फोगिंग करवाई गई। जिसमे आम आदमी पार्टी के विधायक एस.के.बग्गा, आम आदमी पार्टी के नेता श्रवण दीक्षित व वार्ड 22ई के अध्यक्ष अजय मघोक जी उपस्थित रहे। इस दौरान क्षेत्रीय निगम पार्षद रेखा दीक्षित ने उपस्थित सभी लोगों को डेंगू, मलेरिया चिकनगुनिया से बचाव के लिए जानकारी दी व समस्त आरडब्ल्यूए के पदाधिकरियों व क्षेत्रीय जनता से विभाग के कर्मचारियों को पूर्ण सहयोग देने की अपील की व कहा कि बचाव से ही इन घातक बिमारियों से बचा जा सकता है इसी के साथ डेंगू, मलेरिया से बचाव कैसे हो प्रचार सामग्री वितरित की गई। निगम पार्षद रेखा दीक्षित का कहना था कि इस मौसम में प्रत्येक नागरिक को जागरूक रहने की आवश्यकता है। रेखा दीक्षित जी ने कहा कि छत पर पानी की टंकी के ढक्कनों को ढककर रखें व गमलों इत्यादि में पानी जमा न होने दें व छत पर रखे पुराने बर्तनों, टायरों कंटेनरों आदि में पानी जमा न होने दें।

दिल्ली वासियों में यात्रा करने की इच्छा तेजी से बढ़ी : रोमिल पंत

नई दिल्ली। भारत की प्रमुख एकीकृत ट्रैवल सर्विसेज कंपनी थॉमस कुक इंडिया के लिए दिल्ली सबसे ज्यादा स्रोत देने वाले बाजार जैसा है। लॉकडाउन की थकान और बढ़ती मांग के कारण दिल्ली वासियों में यात्रा करने की इच्छा तेजी से बढ़ी है। थॉमस कुक इंडिया ने जून 2021 में दोबारा खुलने के बाद प्रति महीने 60 प्रतिशत की मजबूत दर से बढ़ी है। आगामी त्योहारी और विंटर सीजन, एक्सपो 2020 दुबई और उत्तर में शादियों के कारण हनीमून संबंधी यात्रा के मामलों में उछाल से दिल्ली में यात्रा की वृद्धि हो रही है। थॉमस कुक इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कुल मिलाकर कोरोना महामारी से पहले की तुलना में 65 प्रतिशत तक मांग हो गई है। घरेलू यात्रा में 290 प्रतिशत की प्रभावशाली वृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं में 55 प्रतिशत, सितंबर 2021 और सितंबर 2019 के आंकड़ों की तुलना करने पर वृद्धि हुई है।

उत्तर भारत तक हुआ कंकटाला-क्वीन ऑफ साड़ी का विस्तार

नई दिल्ली। दक्षिण भारत के प्रमुख ब्रांड कंकटाला साड़ी ने दिल्ली में अपने पहले और देश में कुल 13वें रिटेल आउटलेट को लॉन्च किया। इसे क्वीन ऑफ साड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस स्टोर पर भारत के 50 प्रमुख बुनाई समूहों द्वारा बुने गए हैं डलूम उत्पाद मिलेंगे। दिल्ली में स्टोर का उद्घाटन बॉलीवुड अभिनेत्री करिश्मा कपूर ने किया। वे यहां कंकटाला की कांचीपुरम सिल्क फेब्रिक की साड़ी में आई हुई थीं और हमेशा की तरह खूबसूरत लग रही थीं। स्टोर का उद्घाटन कंकटाला साड़ी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक मल्लिकार्जुन राव कंकटाला के साथ-साथ संपूर्ण कंकटाला परिवार की गरिमामयी उपस्थिति में हुआ। इनमें नई पीढ़ी के निदेशक अरविंद भरत और अनिरुद्ध कंकटाला आदि थे। कंकटाला सबसे पुराना साड़ी ब्रांड है जो विशाखापत्तनम, हैदराबाद, बेंगलुरु, राजहमुंद्री, विजयवाड़ा में पहले से ही मौजूद है और 78 सालों से इस सदियों पुरानी तकनीकों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। ब्रांड को अपने मार्केट में हमेशा से नए ट्रेंड लाने वाले के तौर पर जाना गया है और इसने तेजी से प्रगति की है।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कुछ आरोपितों के मोबाइल से निकली अश्लील वीडियो, जो नहीं दिए जा सकते

नई दिल्ली। दिल्ली दंगे की साजिश के मामले में सुनवाई के दौरान बृहस्पतिवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने कहा कि कई आरोपितों के मोबाइल से जुटाई गई सामग्री में उनकी निजी तस्वीरें और कुछ अश्लील वीडियो हैं। जो इस मामले से जुड़े अन्य आरोपितों को मुहैया नहीं कराए जा सके। उनकी निजता का ख्याल रखते हुए ऐसा करना जरूरी है।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने इस मामले में मुख्य आरोपित एवं आप के पार्षद रहे ताहिर हुसैन, जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद, जेएनयू छात्र शरजील इमाम, पूर्व पार्षद इशरत जहां समेत 13 आरोपितों की न्यायिक हिरासत बढ़ाते हुए सुनवाई की अगली तारीख 23 नवंबर तय की है। वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिये हुई सुनवाई में कोर्ट ने कहा कि आरोपित दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 207 के तहत केस से जुड़े दस्तावेज, तस्वीरें, वीडियो मांगने के लिए आवेदन करते वक्त ख्याल रखें कि उससे किसी सह आरोपित की निजता प्रभावित न हो रही हो।

यह भी कहा कि कुछ आरोपितों की तरफ से ऐसे आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिस पर अभियोजन पक्ष ने आपत्ति जताई है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष ने उन्हें कुछ तस्वीरें और विवरण दिखाए जो आरोपितों के मोबाइल फोन में मिली सामग्री का एक नमूना है। उनमें कुछ अश्लील वीडियो हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपितों ने ये खुद बनाए हैं। हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि सब कुछ अश्लील नहीं है।

आरोपितों की कुछ व्यक्तिगत तस्वीरें भी हैं। बता दें कि दंगे में नाम आने के बाद ताहिर हुसैन को आप ने निलंबित कर दिया था। इस मामले में आरोपित पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य देवांगना कलीता, नताशा नरवाल, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा समेत पांच आरोपित जमानत पर भी हैं। सुनवाई से पहले इशारों में बात- इस मामले में सुनवाई शुरू होने से पहले वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े आरोपितों ने मौखिक रूप से तो नहीं, लेकिन इशारों में एक-दूसरे से बात की। कुछ आरोपितों के स्वजन ने उनको देखा। एक बच्चे ने तो अपने पिता के लिए हाथ से हृदय बनाकर दिल की भावना जाहिर की। कुछ के तो आंसू तक निकल आए।

डीएसजीएमसी में फाइनेंशियल रिसीवर नियुक्त करने की मांग

नई दिल्ली। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (डीएसजीएमसी) चुनाव परिणाम घोषित होने के दो माह बाद भी कार्यकारिणी का गठन नहीं हुआ है। अभी भी पुराने प्रबंधक कमेटी का कामकाज संभाल रहे हैं जिसका विरोध शुरू हो गया है। डीएसजीएमसी में फाइनेंसियल रिसीवर नियुक्त करने की मांग उठने लगी है। डीएसजीएमसी के पूर्व अध्यक्ष और शिरोमणि अकाली दल दिल्ली (सरना) के अध्यक्ष परमजीत सिंह सरना ने इसे लेकर उपराज्यपाल अनिल बैजल को पत्र लिखा है जिससे कि इसके कामकाज में पारदर्शिता आ सके।

गुरु घर के फंड का हो रहा है दुरुपयोग

सरना का कहना है कि पंजाबी का ज्ञान नहीं होने के कारण कई निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता खतरे में है। इससे संबंधित मामले अदालत में लंबित हैं। उन्होंने अपनी पार्टी के सदस्यों व सहयोगी पार्टी जग आसरा गुरु ओट (जागो) और अकाली लहर के नेताओं के साथ बैठक की। सरना के साथ ही डीएसजीएमसी के पूर्व अध्यक्ष हरविंदर सिंह सरना और मंजीत सिंह जीके ने कहा कि इस मामले में वह उपराज्यपाल से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि डीएसजीएमसी के निवर्तमान अध्यक्ष मनजिंदर सिरसा चुनाव हार चुके हैं। पंजाबी का ज्ञान नहीं होने के कारण उन्हें कमेटी के सदस्य के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है बावजूद वह अध्यक्ष बने हुए हैं। कमेटी में फंड का दुरुपयोग हो रहा है। गुरु घर के फंड का पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए दुरुपयोग हो रहा है। इसे तुरंत रोकने की जरूरत है।

आइपीएल क्रिकेट मैच के सट्टे में गंवा दिए थे 4.50 लाख, भरपाई करने के लिए चश्मा व्यवसायी के 12.50 लाख रुपये चोरी

नई दिल्ली। उत्तरी जिला के लाहौरी गेट थाना पुलिस ने चश्मा व्यवसायी के 12.50 लाख रुपये चोरी करने के मामले में राजस्थान के रहने वाले दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपितों में एक व्यवसायी का कर्मचारी विक्रम सिंह है। आइपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने पर वह 4.50 लाख रुपये गंवा बैठा था, जिसकी भरपाई के लिए उसने दो दोस्तों के साथ मिलकर मालिक के पैसे गायब कर दिए थे। मालिक को उसने चोरी हो जाने की झूठी कहानी बताई थी।

हालांकि, पुलिस की पूछताछ में सच्चाई सामने आ गई और विक्रम व उसके दोस्तों से गायब किए गए 11.20 लाख रुपये भी बरामद कर लिए गए हैं। डीसीपी सागर सिंह कलसी के मुताबिक राजीव अग्रवाल ने 23 अक्टूबर को लाहौरी गेट थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें बताया कि उनका चश्मे का कारोबार है। राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले अपने कर्मचारी विक्रम सिंह को उन्होंने बाजार से नकदी लाने के लिए भेजा था। शाम को दुकान में आकर उसने बताया कि किसी ने उसके 12.50 लाख रुपये चोरी कर लिए हैं। एसएचओ विजेंद्र राणा के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पहले विक्रम से पूछताछ की। उसके बार-बार बयान बदलने पर पुलिस को संदेह पैदा हुआ। सख्ती से पूछताछ करने पर वह टूट गया और उसने असली कहानी बता दी।

उसके बाद विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने बताया कि आइपीएल के सट्टे में वह 4.50 लाख रुपये हार गया था। इसकी भरपाई के लिए उसने दो दोस्तों बीकानेर निवासी तोलाराम गोदारा और वीरू के साथ मिलकर चोरी का षड्यंत्र रचा था। इसके बाद उसने घटना से एक सप्ताह पहले दोनों को दिल्ली बुलाकर रोहिणी स्थित अपने घर में ठहरा लिया।

23 अक्टूबर को दोनों को लाहौरी गेट इलाके में बुलाकर उसने रकम सौंप दी और रकम चोरी की कहानी गढ़ डाली। विक्रम से पूछताछ के बाद बीकानेर से तोलाराम को गिरफ्तार कर लिया गया। तोलाराम पर राजस्थान के विभिन्न थानों में हत्या के प्रयास, अपहरण, साधारण दुर्घटना, चोरी, शस्त्र अधिनियम व एनडीपीएस के आठ आपराधिक मामले दर्ज हैं। वीरू की तलाश जारी है।

विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र पहुंची भाजपा की झुग्गी सम्मान यात्रा

नई दिल्ली,(रविशंकर तिवारी)। दिल्ली भाजपा के अध्यक्ष आदेश गुप्ता की झुग्गी सम्मान यात्रा गुरुवार को पश्चिम दिल्ली के विकासपुरी विधानसभा क्षेत्र में पहुंची जहां उन्होंने इन्दिरा झुग्गी कैम्प न. 5 एवं 3, कृष्णा काली बस्ती और झंडा चौक बस्ती में झुग्गीवासियों के बीच सघन जनसम्पर्क किया। इस दौरान आदेश गुप्ता ने कहा कि झुग्गीवासी असल में दिल्ली के विकास के नायक हैं वह खुद आभावों में रहकर भी न सिर्फ दिल्ली के विकास में बल्कि हर मध्यमवर्गीय परिवार के विकास में योगदान देते हैं। भाजपा नजफगढ़ जिला मीडिया प्रभारी रोहित भाटिया ने बताया कि भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और सांसद लॉकेट चैटर्जी भी आज यात्रा में सम्मिलित हुए और उन्होंने झुग्गीवासियों की बैठकों को सम्बोधित किया। भाजपा नजफगढ़ जिला अध्यक्ष विजय सोलंकी के नेतृत्व में अनेक स्थानों पर झुग्गीवासियों ने प्रदेश अध्यक्ष एवं अन्य नेताओं का अभिनंदन कर अपनी समस्याओं पर चर्चा की। उन्होंने बताया कि आज की यात्रा में दक्षिण दिल्ली नगर निगम के महापौर मुकेश सूर्यान, दिल्ली प्रदेश भाजपा महामंत्री दिनेश प्रताप सिंह, उपाध्यक्ष राजीव बब्बर, नजफगढ़ जिलाध्यक्ष विजय सोलंकी, महामंत्री मुकेश मिश्रा एवं निगम पार्षद सरिता जिंदल, रवि त्यागी सहित सभी आपेक्षित पार्टी कार्यकर्ता सम्मिलित हुए। यात्रा के दौरान भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हमने सभी भाजपा पार्षदों को निर्देश दिए हैं की जहां संभव हो वहां झुग्गी बस्तियों के आसपास बच्चों के खेलने एवं पढ़ने के लिए सामुदायिक स्थान विकसित करें।

लखबीर सिंह की आत्मा की शांति के लिए किया जाएगा हवन, चौकी के सामने कुंड तैयार

नई दिल्ली। लखबीर सिंह की आत्मा की शांति के लिए नरेला बी4 चौकी पर हवन किया जाएगा, इसके लिए यहां पर एक कुंड तैयार किया गया है। हालांकि पीड़ित परिवार को मुआवजा, सरकारी नौकरी और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर धरना जारी रहेगा। फिलहाल हिंद मजदूर किसान समिति के अध्यक्ष चंद्रमोहन, लखबीर की बेटी, पत्नी, पिताजी समेत करीब एक दर्जन लोग गृहमंत्री अमित शाह से मिलने गए हैं। समिति के सदस्यों के अनुसार वो गृहमंत्री अमित शाह के सामने अपनी मांगे रखेंगे। दरअसल बुधवार को कुंडली बार्डर पर निहंगों की बर्बरता का शिकार हुए दलित व्यक्ति लखबीर सिंह की आत्मा की शांति के लिए हवन करने जा रहे थे, इस दौरान उनके स्वजन और समर्थकों को बुधवार शाम को दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर नरेला में ही रोक दिया। मगर फिर भी वे लोग बैरिकेड तोड़कर जाने लगे तो उनपर लाठीचार्ज कर दिल्ली पुलिस ने स्थिति को काबू में किया। जिसके बाद समर्थकों ने दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की व सड़क पर ही धरना शुरू कर दिया था।

समर्थकों में ज्यादातर उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड के लोग थे। ये लोग कुंडली बार्डर पर उसी जगह हवन करने जा रहे थे, जहां पर लखबीर की हत्या की गई थी। निहंगों की महापंचायत के चलते वहां पर भारी संख्या में निहंग मौजूद हैं।

दरअसल जिस जगह पर लखबीर सिंह की नृशंस हत्या की गई थी, उस जगह पर निहंगों का कब्जा है। बुधवार को पंजाब समेत कई राज्य से काफी संख्या में निहंग महापंचायत के लिए इकट्ठे हुए थे। अगर इस दौरान लखबीर के स्वजन कुंडली बार्डर पर जाते तो निहंग व लखबीर के समर्थकों के बीच टकराव की स्थिति पैदा हो जाती। इसी संभावना के चलते पुलिस ने सिंघु बार्डर से करीब ढाई किलोमीटर पहले ही उन्हें रोक लिया।

मेरठ निवासी लखबीर के समर्थकों में से एक सुरेश ने बताया कि कृषि कानून विरोधियों ने पहले 26 जनवरी को लाल किले पर देश को शर्मसार किया था और अब एक गरीब की हत्या कर दी। इसके बाद भी पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है और उसके हत्यारों को सजा नहीं दे रही है। इसलिए लखबीर की आत्मा की शांति के लिए वह उसी जगह हवन करना चाहते हैं, जहां उसकी हत्या की गई थी। जब तक वह हवन नहीं कर लेते धरना जारी रहेगा।

पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों में टकराव न हो इसलिए नरेला में उन्हें रोक लिया गया। इस दौरान कुछ लोगों को चोट भी आई है। दशहरे के दिन पंजाब के तरनतारन के चीमा कलां गांव के लखबीर सिंह की नृशंस हत्या कर दी गई थी। लखबीर सिंह के हाथ काटकर और पैर तोड़कर बैरिकेड पर मरने के लिए लटका दिया था। हत्या के बाद कार्रवाई न होने से आहत लखबीर की बहन व बेटियां उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के लगभग 700 समर्थकों के साथ घटना स्थल पर हवन करने के लिए करनाल बाइपास के रास्ते सिंघु बार्डर की तरफ रवाना हुए।

दिवाली के अवसर पर निर्बाध पूजा के लिए विशेष पूजा किट

नई दिल्ली,(एजेंसी)। साइकिल प्योर अगरबत्ती ने इस वर्ष दिवाली के लिए समयानुकूल वैदिक परम्परा सम्पूर्ण लक्ष्मी पूजा किट प्रस्तुत किया है। भक्तों के लिए यह पूजा किट विशेष रूप से शुभ लक्ष्मी पूजा के त्यौहार को सुविधाजनक ढंग से मनाने के लिए तैयार की गई है। इस पर्यावरण-हितैषी किट में पूजा करने के लिए अगम शास्त्र में वर्णित सभी आवश्यक सामग्रियां शामिल हैं। इस किट को बहुत ध्यान के साथ विद्वान पुरोहितों के मार्गदर्शन और हमारी पवित्र ग्रंथों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसमें उपयोगकर्ता द्वारा आसानी से पूजा करने और मंत्रों का उच्चार करने के लिए चरणबद्ध तरीके से निर्देश सम्मिलित हैं। सम्पूर्ण किट के बारे में साइकिल प्योर अगरबत्ती के प्रबंध निदेशक अर्जुन रंगा ने कहा कि हम लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि हमारे प्राचीन रीति-रिवाजों और अनुष्ठानों का पालन किया जाए और उन्हें चिरस्थाई बनाया जाए।

इसलिए, हमने सम्पूर्ण लक्ष्मी पूजा किट तैयार की है। यह किट सभी उम्र के भक्तों को आसान चरण-दर-चरण निर्देशों के साथ आराम से पूजा करने में मददगार है। इस पूजा किट के माध्यम से हम अपने उपभोक्ताओं के लिए पूजा करने का आनंद बढ़ाना चाहते हैं।

अब दिल्ली जल बोर्ड देगा घरेलू पानी कनेक्शन, बिचौलियों से मिलेगी निजात, आपको देना होगा इतना शुल्क

नई दिल्ली,(एजेंसी)। राजधानी में अब दिल्ली जल बोर्ड द्वारा ही घरेलू पानी का कनेक्शन लगाया जाएगा। इससे बिचौलियों से निजात मिलेगी और दूषित पानी की समस्या भी दूर की जा सकेगी। जलमंत्री और दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष सत्येंद्र जैन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बोर्ड बैठक में इसका फैसला लिया गया। दिल्ली में अभी तक पानी के सप्लाई पाइप से कनेक्शन लेने का काम बिचौलियों के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा खुद कराया जाता रहा है। इसके चलते पाइपलाइन के जोड़ों से पानी के रिसाव और पानी के दूषित होने तक की समस्या आने की बात कही जाती रही है।

दिल्ली जल बोर्ड की मंगलवार को हुई बैठक में इस समस्या को दूर करने के लिए बिचौलियों को हटाने का फैसला लिया गया। अब दिल्ली जल बोर्ड सभी उपभोक्ताओं को घरेलू पानी का कनेक्शन उपलब्ध कराएगा।

इसमें पानी की पाइप लाइन बिछाना और उपभोक्ता के घर पर मीटर लगाना शामिल है। जल मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि इससे दूषित पानी की समस्या से निजात मिलेगी और अनाधिकृत कनेक्शन की संख्या कम होंगे। इसकी वजह से दिल्ली जल बोर्ड के नेटवर्क में काम करने वाले मीटरों की संख्या में वृद्धि होगी। नई नीति के मुताबिक दिल्ली जल बोर्ड मौजूदा कॉलोनियों में पुरानी पाइप लाइनों को ठीक करने के साथ-साथ आने वाली कॉलोनियों में मीटर के साथ पानी के नए कनेक्शन लगाएगा।

नए कनेक्शन के लिए शुल्क भी निर्धारित- बोर्ड बैठक में ए, बी व सी श्रेणी के तहत आने वाली कॉलोनियों के लिए चार हजार रुपये की लागत को मंजूरी दी है। जबकि, डी और ई श्रेणी के लिए दो हजार रुपये और एफ, जी व एच श्रेणी की कॉलोनियों और गांवों के लिए एक हजार रुपये की दर को मंजूरी दी गई है। जबकि, व्यावसायिक कनेक्शनों के लिए दर घरेलू श्रेणी से दोगुनी अर्थात आठ हजार, चार हजार और दो हजार रुपये होगी।

ओखला में लगेगा बीस एमजीडी क्षमता का आरओ प्लांट-बैठक में जल मंत्री ने ओखला में 20 एमजीडी (मिलियन गैलन प्रति दिन) की क्षमता के आरओ प्लांट लगाने की परियोजना को मंजूरी दे दी है। योजना के तहत रोजाना 20 एमजीडी पीने योग्य पानी का वितरण किया जाएगा जो कि पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों में पहुंचाया जाएगा। इस आरओ प्लांट में पानी की आपूर्ति झीलों और भूजल से की जाएगी। जमीन से पानी सिर्फ उन इलाकों से निकाला जाएगा जहां पानी का स्तर ऊपर है। परियोजना को मई 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली की आठ से दस विधानसभा क्षेत्र के लोगों को इस परियोजना से राहत मिलेगा। बोर्ड बैठक में नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों को मिलाकर वार्ड और जोन स्तर पर जल एवं सीवेज समिति के गठन को मंजूरी दी गई है। यह समिति दो स्तर पर होगी। वार्ड स्तरीय समिति में सात सदस्य होंगे जबकि, जोनल समिति में 12 सदस्य होंगे। आम लोगों को सरकारी सुविधाओं का पूर्ण लाभ पहुंचाने, लोगों की शिकायतों को दूर करने और संचार केंद्र की भूमिका निभाने में इनका योगदान होगा।

तीन साल में सभी रिहायशी कॉलोनियों में सीवर लाइन- बैठक में तीन साल की अवधि में सभी रिहायशी कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने पर प्रतिबद्धता जताई गई। संगम विहार में सीवर लाइन बिछाने के काम को मंजूरी मिल गई है। जबकि, शाहबाद की कॉलोनियों, सारंगपुर, गालिबपुर, काजीपुर और खेरा डाबर की कॉलोनियों में सीवर लाइन बिछाने और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इस कार्य को दो साल के अंदर पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिल्ली सरकार 153 करोड़ रुपये की लागत से दिल्ली के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांटों को नए तरीके से विकसित करेगी।

वर्षा जल संचयन में दो स्लैब

वर्षा जल संचयन सिस्टम लगाने के लिए दिए जाने वाली वित्तीय सहायता के स्लैब में भी बदलाव किया गया है। अब केवल दो श्रेणियों को रखा गया है। 500 वर्ग मीटर से कम क्षेत्रफल वाले घरों के लिए 25 हजार रुपये और 500 मीटर से ज्यादा क्षेत्रफल वाले मकानों के लिए 50 हजार रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। इसके अलावा, यमुना नदी में प्रदूषण को कम करने के लिए 14 सीवेट ट्रीटमेंट प्लांट में ऐसे उपकरण (एरेशन तंत्र) लगाए जाएंगे जिनसे पानी गुणवत्ता में सुधार होगा।

संपादकीय

भूसे से एथेनॉल

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लगातार बढ़ते कच्चे तेल के दाम और उसके हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ते दबाव को देखते हुए सरकार नवीकरणीय ऊर्जा को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल कर रही है। पहले सरकार ने 2030 तक पेट्रोल में बीस फीसदी एथेनॉल मिश्रण का लक्ष्य रखा था। पिछले दिनों विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री ने अब इसे घटाकर 2025 कर दिया है। सरकार की मंशा है कि आत्मनिर्भर भारत की पहल के अंतर्गत इसे कालांतर में सौ फीसदी एथेनॉल से चलने वाले वाहनों के रूप में लक्ष्य हासिल किया जाये। दरअसल, सरकार की सोच रही है कि अपनी आर्थिक संप्रभुता के लिये हमें नवीकरणीय ऊर्जा पर निर्भरता बढ़ानी होगी। इसमें बैटरी से जुड़ी प्रौद्योगिकियां भी शामिल हैं। नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य जहां वर्ष 2022 तक 175 गीगावॉट है, वहीं वर्ष 2030 तक इसे 450 गीगावॉट किया जायेगा। सरकारी की प्राथमिकताओं का प्रतिफल यह है कि वर्ष 2014 में जहां 38 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदा जाता था, वह अब 320 करोड़ लीटर खरीदा जा रहा है। बीते साल तेल बाजार की कंपनियों ने 21 हजार करोड़ रुपये का एथेनॉल खरीदा। केंद्र का दावा है कि पिछले सात सालों में हमारी अक्षय ऊर्जा की क्षमता में 250 फीसदी वृद्धि हुई है। फलतः आज भारत अक्षय ऊर्जा के मामले में शीर्ष पांच देशों में शामिल है। निस्संदेह, 21वीं सदी में ग्लोबल वार्मिंग के खतरों को देखते हुए नवीकरणीय ऊर्जा अपरिहार्य बन गई है। यही वजह है कि वर्ष 2014 तक पेट्रोल में जहां 1.5 फीसदी एथेनॉल मिलाया जाता था, वह अब 8.5 फीसदी हो गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसका एक बड़ा हिस्सा किसानों की जेब में गया है। विशेष रूप से गन्ना किसानों के खाते में। इसी कड़ी में एथेनॉल के उत्पादन और वितरण से जुड़ा महत्वाकांक्षी ई-100 पायलट प्रोजेक्ट पुणे में लॉन्च किया गया है। वहीं दूसरी ओर सौर ऊर्जा में पिछले छह साल में 15 गुना वृद्धि की बात सरकार कर रही है।

वक्त की मांग है कि एथेनॉल उत्पादन इकाइयों को चीनी उत्पादक राज्यों के इतर अन्य राज्यों में भी विस्तार दिया जाये। तभी देश के विभिन्न राज्यों में सड़े अनाज व खेती से निकले कचरे आधारित संयंत्रों की स्थापना की जा रही है। इसी कड़ी में करनाल जनपद में एथेनॉल संयंत्र में धान की पराली का उपयोग किया जायेगा, जो पराली प्रबंधन की समस्या के समाधान की दिशा में एक बड़ा कदम है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नियामक ने जीवाश्म ईंधन के उपयोग में कमी करके पेट्रोल में 'हरित ईंधन' एथेनॉल के मिश्रण के लक्ष्य निर्धारित किये हैं, जिसमें धान के भूसे के इस्तेमाल को प्राथमिकता दी गई है, जिससे भविष्य में इसकी मांग व उपयोग में वृद्धि की उम्मीदें जगी हैं। फिलहाल करनाल में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एथेनॉल प्लांट में धान की भूसी का उपयोग होगा। हालांकि, इसके लिये खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन प्रसंस्करण अप्रैल, 2022 में आरंभ होगा, जिसमें किसानों की पराली प्रबंधन में होने वाले खर्च को बचाने में मदद की जायेगी। दरअसल, रबी की फसल के लिये सीमित समय होने के कारण किसान इसे खेतों में जला देते हैं। अब पराली प्रबंधन में इस नई पहल से मदद मिलेगी। अच्छी बात यह है कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के अनुसार पंजाब, हरियाणा व उ.प्र. में पराली जलाने में इस साल कमी देखी गई है। सर्दियां शुरू होने के साथ ही दिल्ली व एनसीआर क्षेत्र में वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आती थी। फिर उसे दुरुस्त करने के उपाय किये जाते थे। कोविड महामारी, जिसने हमारे श्वसनतंत्र को ज्यादा नुकसान पहुंचाया, ने हमें स्वच्छ वातावरण की जरूरत को बताया है। वहीं दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश के ऊना में भी एक एथेनॉल संयंत्र स्थापित करने की योजना है, जिसके लिये आसपास के राज्यों से पराली खरीदी जा सकेगी। वहीं मुक्तसर के रहरियांवाली गांव में ग्रामीणों ने बिना किसी सरकारी मदद के धान की भूसी को गांठों में बदलने, गौशालाओं में इस्तेमाल करने तथा उन्हें राजस्थान व गुजरात को आपूर्ति करने की प्रेरक पहल की है। निस्संदेह, व्यक्तिगत जागरूकता भी महत्वपूर्ण है।

प्रवीण कुमार सिंह

भारत को झटका

इंड़िया विश्व कप मुकाबलों में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अजेय सिलसिले को बनाए नहीं रख सकी। बाबर आजम की अगुआई वाली पाकिस्तान टीम ने जिस एकतरफा अंदाज में उसे 10 विकेट से हराया, वह कष्ट देने वाला है। यह सही है कि एक हार से अभियान खत्म नहीं होता। अब भी भारतीय टीम आगे शानदार प्रदर्शन करके खिताब जीत ले तो इस समय हो रहीं आलोचनाओं की जगह तारीफें ले लेंगी। यह सही है कि प्रशस्ति हमेशा उगते सूरज की ही की जाती है। मैच से पहले पाकिस्तान के पूर्व कप्तान इंजमामुल हक द्वारा कही बात किसी हद तक सही साबित हो गई। उन्होंने कहा था कि विश्व कप में भारतीय टीम पाकिस्तान से कभी हारी नहीं है इसलिए इस सिलसिले को बनाए रखने का दवाब भारत पर होगा। हमारी टीम लगातार हारती रही है, इसलिए खुलकर खेल सकती है। हुआ भी यही, हम दवाब में अपना बेस्ट देने में सफल नहीं हो सके। इसके अलावा विराट पर अपनी कप्तानी में अब तक कोई आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीतने का दवाब भी रहा होगा। पाकिस्तान का प्रदर्शन तो इस जीत का हकदार था साथ में हमारी कुछ गलतियों ने भी उनका काम थोड़ा आसान जरूर कर दिया। पहले तो हार्दिक पांड्या को एक ऑलराउंडर के बजाय सिर्फ एक बल्लेबाज के तौर पर खिलाने से भारत को पांच गेंदबाजों के साथ खेलने को मजबूर होना पड़ा। इससे किसी गेंदबाज के पिटने पर हमारे पास उसको बदलने का विकल्प ही नहीं था। टीम प्रबंधन ने इस मैच में वरुण की जगह रविचंद्रन अश्विन को खिलाया होता तो कहीं बेहतर प्रदर्शन हो सकता था। इस मैच में हार्दिक या भुवनेश्वर की जगह शार्दुल ठाकुर का होना बेहद जरूरी था। अब भारत के लिए पाकिस्तान से हारने के बाद 31 अक्टूबर को न्यूजीलैंड़ से होने वाले मुकाबले को जीतना बेहद जरूरी हो गया है ऐसा करने से ही उसे ग्रुप में पहली दो टीमों में स्थान बनाने में आसानी होगी। पर दिक्कत यह है कि वह विश्व कप में न्यूजीलैंड़ से कभी जीता नहीं है। पर इस तरह का रिकॉर्ड़ पाकिस्तान के बाद तोड़ने की उनकी बारी है। ग्रुप की बाकी टीमों अफगानिस्तान, स्कॉटलैंड़ और नामीबिया को फतह करना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। हां यह जरूर है कि पाकिस्तान से हार ने भारत की मुश्किलों को थोड़ा बढ़ा दिया है।

टू दि प्वाइंट/ आलोक पुराणिक

हार से कैसे निपटें

उफ्फ, हाय, ओ माय गाड, इन सबसे बाहर आइये, सचाई यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने इंडिया की टीम को सिर्फ पीटा ही नहीं है, बल्कि पटक-पटककर धोया है। उफ्फ हाय एक होती है हार और दूसरी होती है पाकिस्तान से हार। हार में दिल टूटता है, पाकिस्तान से हार में बंदा ही टूट लेता है। उफ्फ हाय! किसी ने सुझाया कि हार से कैसे निपटें-इस विषय पर बात करने के लिए कांग्रेसजन बहुत ही उपयुक्त हैं हार से निपटने का अब सुदीर्घ अनुभव है इन्हें। कांग्रेसजन से पूछा तो बोला-राहुलजी सब सही कर देंगे। यह बात वह कई सालों से बोल रहा है। पाकिस्तान से मिली हार में राहुल (केएल राहुल) का बड़ा हाथ है, राहुल ने यहां भी मरवा दिया, यह बात बोलनेवाला था, पर नहीं बोला। हार से निपटने का एक तरीका तो यह है कि विश्व नागरिक बन जाइए, क्या पाकिस्तान, क्या हिंदुस्तान, पूरी दुनिया हमारी। पर नहीं नहीं, पाकिस्तान को अपना मान लिया तो वहां के आतंकी हाफिज सईद भी अपने हो जाएंग, नहीं नहीं। वसुधैव कुटुंबकम, में भी पाकिस्तान, अफगानिस्तान के तालिबान को बाहर निकालना पड़ेगा, ये आततायी अगर कुटुंब में रहे, तो कुटुंबनाश तय है। तो क्या करें, उफ्फ ऐसी पिटाई, हमारे बॉलर पाकिस्तान के एक बैट्समैन को भी आऊट ना कर पाये, हाय हाय, क्या करें ऐसे पराक्रमी गेंदबाजों का, क्या करें। कुछ ना करें, बॉलर अपने दूसरे काम तो सही कर रहे हैं, हमारे बॉलर बुमराह वनप्लस मोबाइल सही बेच रहे हैं, वहां कोई कमी हो तो बताना। बॉलर की समग्र परफारमेंस देखनी चाहिए ना। वनप्लस सही काम करे, तो समझिये बुमराह कामयाबा। मैच वैच पर क्या ध्यान देना। उफ्फ, अगली बार यह करें धोनी, सचिन तेंदुलकर, सहवाग को टीम में शामिल करके पाकिस्तान भेजा जाए। पर ये तो क्रिकेट के सीनियर सिटीजन हैं, इन्हे कैसे भेज सकते हैं टीम में। इन्हें भेजने का फायदा यह है कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान से हार भी जाए, तो कहने को होगा कि बुजुर्गों को हरा दिया, बड़े बदतमीज बेअदब हैं पाकिस्तानी। ओके यह सही है, आइए मांग करें कि टीम में धोनी सचिन और सहवाग को शामिल किया जाए।

पाकिस्तानी साजिश का पर्दाफाश आवश्यक

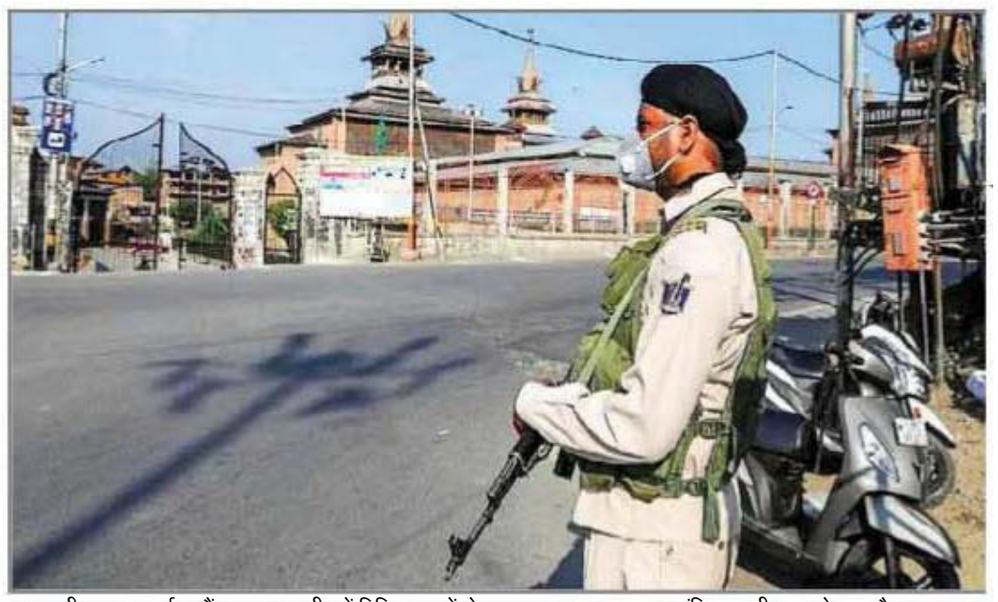

कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा ताबड़तोड़ हत्याएं कर जिस तरीके से आतंक का माहौल पैदा किया जा रहा है, बेहद शर्मनाक है। हाल ही में जो यहां हत्याएं की गई हैं, उसमें प्रवासी मजदूरों अथवा अन्य प्रदेश से आए लोगों को टारगेट किया गया है। आतंकवादियों का इसके पीछे मुख्य उद्देश्य बाहरी लोगों में खौफ पैदा करना और विकास की धारा को बेपटरी करना है।

निस्संदेह, यह पाकिस्तान की बौखलाहट का नतीजा है। चूंकि जम्मू-कश्मीर में धारा 370 समाप्त करने के बाद जिस तरीके वहां अमन चैन बहाल हो रहा है, वह पाकिस्तान को रास नहीं आ रहा। हत्याओं के पीछे लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट-जम्मू कश्मीर जैसे आतंकी संगठनों का हाथ रहा है। स्पष्ट तौर पर इनको पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है।

जैसा कि विदित है कि 5 अगस्त, 2019 जम्मू-कश्मीर के लिए ऐतिहासिक दिन सिद्ध हुआ। इसी दिन जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 और धारा 35-ए को समाप्त कर दिया गया था। इसी के साथ जम्मू-कश्मीर को जो वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के अंतर्गत विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था, उसका अंत हो गया और यह एक देश, एक विधान और एक संविधान के दायरे में आ गया था। उसके पश्चात भारत सरकार ने स्थानीय लोगों को विकास की मुख्यधारा में शामिल करने के लिए विकास संबंधी कार्यों की रणनीति बनाई थी।

लेकिन पाकिस्तान को भारत का यह निर्णय शुरू से ही नहीं पच रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत के खिलाफ जमकर दुष्प्रचार किया था। उन्होंने कहा था कि अनुच्छेद 370 समाप्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन होगा और वहां नरसंहार शुरू हो जाएगा। लेकिन जम्मू-कश्मीर का विशेष दर्जा समाप्त होने के बाद सुरक्षा बलों ने जिस तरीके से आतंकियों का सफाया और दिशा विहीन हुए लोगों को मुख्यधारा में शामिल करने के लिए अभियान चलाया, वह काबिले तारीफ है। लेकिन पाकिस्तान जम्मू-कश्मीर में शांति की बहाली बिलकुल नहीं चाहता। यही कारण है कि उसने वहां अशांति फैलाने की रणनीति बदल दी है। अब उसने प्रवासी मजदूरों और अन्य प्रदेशों के प्रवासियों को टारगेट करना शुरू कर दिया है। अनेक प्रवासी मजदूर डर कर यहां से पलायन कर रहे हैं।

गौरतलब है कि जम्मू-कश्मीर में वर्तमान में चल रही अनेक विकास परियोजनाओं में 90 फीसदी से अधिक प्रवासी मजदूर निर्माण कार्यों में लगे हुए हैं। अकेले कश्मीर घाटी पांच लाख प्रवासी मजदूर कार्यरत हैं। जम्मू-कश्मीर में विभिन्न राज्यों से तीन-से चार लाख मजदूर प्रत्येक वर्ष काम के लिए घाटी जाते हैं। उनमें से अधिकांश सर्दियों की शुरुआत से पहले चले जाते हैं, जबकि कुछ साल भर वहीं रहकर काम करते हैं। उनमें बिहार और उत्तर प्रदेश से आए मजदूरों की संख्या सर्वाधिक होती है।

पाकिस्तान की बौखलाहट का एक प्रमुख कारण यह है कि जम्मू कश्मीर को जो पहले विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था, समाप्त हो चुका है। पहले वहां लोगों के पास दोहरी नागरिकता-जम्मू कश्मीर और भारत की थी, लेकिन अब देश के बाकी लोगों की तरह वहां भी एक ही नागरिकता है। इसके अलावा पहले यह प्रावधान था कि जम्मू कश्मीर की कोई युवती भारत के किसी राज्य के युवक से शादी करती है तो उसका उसके परिवार की संपति में अधिकार खत्म हो जाता था और उसके बच्चों की भी जम्मू-कश्मीर की नागरिकता खत्म हो जाती थी, पर अब ऐसा नहीं है।

यही नहीं, जम्मू-कश्मीर का अलग झंडा था, लेकिन अब तिरंगा ही पूरे जम्मू-कश्मीर का भी राष्ट्रीय ध्वज है। पहले जम्मू-कश्मीर में न अनुच्छेद 356 लागू था यानी वहां सरकार भंग होने पर राष्ट्रपति शासन नहीं लग सकता था और न ही वह अनुच्छेद 360 के दायरे में आता था, जिसके तहत राष्ट्रपति आर्थिक आपातकाल लागू करते हैं। लेकिन अब यहां पर अब भारत का संविधान पूरी तरह से लागू है।

दिलचस्प बात यह है कि पहले दूसरे राज्य के लोग जम्मू-कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे, लेकिन अब ये कानून नहीं है। अब यहां पर आरटीआई कानून लागू है और जहां पहले जम्मू-कश्मीर में सरकार का कार्यकाल 6 साल का होता था, अब वहां भी 5 साल के बाद चुनाव कराने का प्रावधान है। इसके अलावा पहले लद्दाख जम्मू-कश्मीर का हिस्सा था, लेकिन अब लद्दाख अलग से केंद्र शासित प्रदेश है। यह सब ऐसे बदलाव हैं जिनको पाकिस्तान और उसके द्वारा समर्थित आतंकी संगठन पचा नहीं पा रहे हैं। सुरक्षा बलों की अत्यंत सख्ती के चलते उन्होंने अपनी रणनीति में बदलाव करते हुए प्रवासी मजदूरों अथवा बाहरी प्रदेशों से आए निर्दोष लोगों का नरसंहार कर उनके अंदर खौफ पैदा करने की घिनौनी साजिश चल रही है। पाकिस्तान का उद्देश्य है कि जम्मू-कश्मीर एक बार पुनः अंतरराष्ट्रीय मुद्दा बन जाए। ऐसे में हर राजनैतिक दल और समाज के हर समुदाय को अपने निहितार्थों को त्यागकर देश और समाज हित में पाकिस्तान और आतंकियों के दुष्चक्र का पर्दाफाश करना चाहिए। इसके लिए न केवल हर नागरिक में सजगता जरूरी है, बल्कि आवश्यकता पड़ने पर अपना यथोचित योगदान कर पाकिस्तान और आतंकियों के मंसूबों को विफल करना चाहिये।

> अगर हम एकबार इस दिशा में कायदे से पूँजी निवेश कर देंगे तो हमें बहुत लाभ होगा। सबसे बड़ा लाभ तो ये होगा कि स्थानीय नवयुवकों के रोजगार के अवसर बहुत बढ़ जाएंगे।

न्याय की आस

खत्म हो तारीख-पे-तारीख का भय

हमारी न्यायपालिका भले ही नागरिकों को उनके संवैधानिक अधिकारों और कार्यपालिका की कार्रवाई के खिलाफ उनकी वैयक्तिक स्वतंत्रता और हितों की रक्षा के बारे में बार-बार आश्वासन देती है लेकिन इसके बावजूद आज भी आम नागरिक अदालत के नाम से डरता है। आम नागरिकों में एक धारणा गहरे तक पैठ किये है कि एक बार विवाद अदालत में पहुंचा तो न्याय कब मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जरूरी है कि त्वरित व सस्ता तथा सुगम न्याय प्रदान करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जाएं।

त्वरित और सुगमता से न्याय दिलाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि देश में न्यायिक अधिकारियों की संख्या बढ़ाने के साथ ही बेहतर सुविधाओं के साथ अदालती कक्षों की संख्या भी बढ़ाई जाए। यह भी सुनिश्चित हो कि अनावश्यक रूप से मुकदमों की सुनवाई स्थगित नहीं हो। नागरिकों के मन में जल्दी न्याय नहीं मिलने की आशंका तेजी से घर कर रही है। इसकी वजह दीवानी और फौजदारी मुकदमों का सालों तक लंबित रहना भी है। एक साधारण व्यक्ति के मन में अदालत में 'तारीख पे तारीख' की दहशत है।

त्वरित न्याय नहीं मिलने की एक बानगी हाल में उच्चतम न्यायालय द्वारा खारिज की गयी एक याचिका है। इस मामले में पश्चिम बंगाल की एक महिला द्वारा 1971 में 3000 हजार रुपये की वसूली के लिए दायर मुकदमा करीब 50 साल चला। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे 'कभी न थकने वाला विक्रमादित्य' बताया। रमा देवी नाम की इस महिला ने 1974 में मुकदमा जीत लिया था लेकिन इसके बाद भी विवाद खत्म नहीं हुआ, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने इस साल अक्तूबर में खत्म किया है। साथ ही न्यायालय ने इस प्रकरण को कानून के छात्रों के लिए विधि पाठ्यक्रम में भी शामिल करने का सुझाव दिया है।

इस तरह के कई उदाहरण मौजूद हैं, जिसमें वादकारी आम नागरिक को न्याय मिलने में 20 साल से लेकर 45 साल का वक्त लगा। प्रधान न्यायाधीश एन. वी. रमण भी इस तथ्य से अवगत हैं और यही वजह है कि उन्होंने पिछले सप्ताह एक कार्यक्रम में इस बात पर जोर भी दिया कि आम आदमी को अदालतों में आने के लिए संकोच नहीं करना चाहिए क्योंकि न्यायपालिका के प्रति जनता की आस्था लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। निःसंदेह न्यायपालिका के प्रति जनता का विश्वास लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन अगर हम राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड के आंकड़ों पर नजर डालें तो वह खुद ही आम नागरिक के मन की शंका बयां करती है। मसलन, राष्ट्रीय न्यायिक ग्रिड के आंकड़ों के अनुसार इस समय देश की अदालतों में कम से कम 32,57,580 मुकदमे दस साल से भी ज्यादा समय से लंबित हैं। इनमें आपराधिक मामलों की संख्या 25,63,616 और दीवानी मामलों की संख्या 6,93,964 है। इन आंकड़ों में 36,214 दीवानी मुकदमे और 63,509 आपराधिक मुकदमे 30 साल से भी ज्यादा समय से न्याय की बाट जोह रहे हैं। इनमें से अनेक वादकारियों या प्रतिवादियों का अब तक शायद निधन भी हो गया होगा। इसी प्रकार 20 साल से ज्यादा समय से लंबित दीवानी मामलों की संख्या भी 1,13,998 और आपराधिक मुकदमों की संख्या 3,61,714 है।

यही नहीं, उच्चतम न्यायालय में पांच, सात और नौ सदस्यीय संविधान पीठ के विचारार्थ भी इस समय 421 मामले लंबित हैं। इनमें नौ सदस्यीय संविधान पीठ के 135 और सात सदस्यीय संविधान पीठ के विचारार्थ 15 मामले हैं जबकि पांच सदस्यीय संविधान पीठ के विचारार्थ 271 मुकदमे लंबित हैं। इस तरह के डराने वाले आंकड़ों के मद्देनजर कोई भी आम आदमी अपने किसी विवाद के लिये अदालत का दरवाजा खटखटाने से पहले दस बार सोचता है कि इसके समाधान के लिये कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना कितना उचित होगा।

इस स्थिति के लिए काफी हद तक कार्यपालिका भी जिम्मेदार है जो मुकदमों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त संख्या में न्यायिक अधिकारियों की नियुक्तियां नहीं करती और अदालती कक्षों के निर्माण का सवाल उठने पर पैसे का रोना रोने लगती है। प्रधान न्यायाधीश ने अपने हालिया भाषण में इस तथ्य को इंगित करते हुए कहा है कि देश में न्यायिक अधिकारियों की कुल संख्या 24, 280 और किराये के 623 परिसरों सहित अदालती कक्षों की संख्या 20,140 है।

उन्होंने यह भी कहा कि देश में अदालतों के लिए बेहतर न्यायिक सुविधाओं के बारे में सबसे अंत में सोचा जाता है। न्यायमूर्ति रमण ने कहा कि न्याय प्रदान करने की प्रभावी व्यवस्था के लिए न्यायपालिका को बेहतर बनाना जरूरी है क्योंकि प्रभावशाली न्यायपालिका अर्थव्यवस्था के विकास में मददगार हो सकती है जबकि न्याय प्रदान करने में विफलता देश को प्रभावित करती है।

विवादों के शीघ्र समाधान में लोक अदालतें काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में नियमित रूप से लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद करोड़ों लंबित मुकदमे अभी भी एक बड़ी समस्या बने हुए हैं। जिला स्तर पर मुकदमों का निपटारा तभी संभव हो सकेगा जब राज्य स्तर पर न्यायपालिका के मुखिया अर्थात? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश निचली अदालतों में लंबित मुकदमों की तेजी से सुनवाई सुनिश्चित करने और अनावश्यक कारणों से सुनवाई के स्थगन पर अंकुश लगाने के लिए ठोस दिशा निर्देश बनायें।

अर्थव्यवस्था

प्रगति के हाइवे पर

पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दाम सभी के लिये चिन्ता का सबब हैं। सरकार इसका संज्ञान ले रही है। वैश्विक स्तर पर भी भारत दबाव डाल रहा है कि तेल का दाम कम किया जाए और उसका उत्पादन बढवया जाए। प्रधानमंत्री का प्रयास है कि हम अक्षय ऊर्जा की खपत बढवएं चाहे वह सौर हो या पवन ऊर्जा। अब नेशनल हाइड्रोजन मिशन की भी स्थापना की गई है। तेल उत्पादों पर केन्द्र एक्साइज और प्रदेश सरकार वैट लगाती है। जहां तक केन्द्र सरकार की बात है तो सभी जनकल्याणकारी योजनाओं का खर्च केन्द्र सरकार ही वहन करती है।

कोविड की त्रासदी के बाद लगभग तीस लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की गई थी, उसका सारा खर्च केन्द्र ही वहन कर रहा है। जीएसटी और डाइरेक्ट टैक्स के अंतर्गत जो राशि जमा हो रही है, उसमें कमी आने के बावजूद केन्द्र प्रदेशों को पूरी राशि मुहैया करा रहा है। कर आपूर्ति में कमी होने के कारण केन्द्र के संसाधनो में कमी आई है और केन्द्र के खचा बढ़े हैं। इसे देखते हुए प्रदेश सरकारों को अपना वैट कर कम करना चाहिए। जहां तक अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने की बात है तो कोरोना के बाद सरकार के सभी प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। हम जो देख रहे हैं वह एक मजबूत 'वी' आकार की रिकवरी है। भारतीय अर्थव्यवस्था इस वर्ष दो अंकों की विकास दर हासिल करने की राह पर है तथा आने वाले वर्षों में भी यह दर अच्छी रहेगी। यह केंद्र की मोदी सरकार द्वारा उठाये गए सुधारात्मक कदमों का परिणाम है।

कोरोना संकट के बाद मानो एक बार लग रहा था कि भारत अपनी विकास की गति में पिछड़ न जाए। परंतु जिस प्रकार कोरोना के बाद पिछले एक साल में विकास हुआ है वह सराहनीय है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक लॉकडाउन के कारण भारत की अर्थव्यवस्था आपूर्ति और मांग की दिक्कतों का सामना कर रही थी। परंतु आज जब हम देखते हैं तो भारत का हर क्षेत्र अपने पूर्ववर्ती विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा है। कई नए सुधार और आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज की मदद से न केवल आर्थिक मंदी को भारत ने पीछे छोड़ा बल्कि आत्मनिर्भर बनकर आगे के लिए एक नई नींव भी तैयार कर रहा है। इस नए आत्मविश्वास और प्रगति के कई महत्वपूर्ण प्रमाण है।

कृषि क्षेत्र में जनवरी से दिसम्बर 2019 तक किए गए सवाक्षण से पता चलता है कि किसानों की आय में 59 फीसद की वृद्धि हुई है। 2012-13 में प्रति परिवार आय प्रति माह 6426 रु. से बढ़ कर 10218 रु. प्रति माह हो गई है। एक प्रमुख कंसल्टेंसी फर्म की 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, भारत विश्व स्तर पर दूसरा सबसे अधिक मांग वाला विनिर्माण गंतव्य बनने के साथ ही संयुक्त राज्य अमेरिका से भी आगे निकल गया है। प्रत्यक्ष कर संग्रह 16 सितम्बर, 21 तक 5.66 लाख करोड़ रुपये रहा जो पिछले साल इसी अवधि में 3.28 लाख करोड़ था। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि चालू वित्त वर्ष में संग्रह 2019-2020 (पूर्व-कोविड) की इसी अवधि की तुलना में 28 प्रतिशत अधिक है। जीएसटी संग्रह, लगातार नौ माह से 1 लाख करोड़ का आंकड़ा पार करने के पश्चात जून 2021 में, कोविड की दूसरी लहर के कारण 1 लाख करोड से कुछ नीचे चला गया था लेकिन अर्थव्यवस्था की मजबूती को दिखाते हुए जुलाई और अगस्त 2021 का जीएसटी संग्रह फिर 1 लाख करोड़ को पार कर गया है।

विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (डब्ल्यूआईपीओ) द्वारा तैयार किए गए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स (जीआईआई) 2021 में भारत दो रैंक चढ़कर 46वें स्थान पर पहुंच गया है। अगस्त 2021 में भारत का व्यापारिक निर्यात 33.14 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जो अगस्त 2020 में 22.83 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 45.17 अधिक था और अगस्त 2019 (पूर्व कोविड) में 25.99 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 27.5 अधिक था।

टीकाकरण अभियान में भारत ने 100 करोड़ टीकाकरण का प्रभावशाली लक्ष्य हासिल कर लिया है, यह मजबूत सकारात्मक भावनाओं और सेवाओं, पर्यटन जैसे क्षेत्रों में मदद करेगा। यह स्वीकार करने में कोई भी संकोच नहीं है कि अर्थव्यवस्था के कुछ हिस्सों में अभी भी समस्याएं हैं। केंद्र की नरेन्द्र मोदी सरकार और भाजपा देश के कुछ क्षेत्रो में आर्थिक चिंताओं के प्रति सजग है। भाजपा बाजार आधारित अर्थव्यवस्था पर विश्वास करती है एवं दूसरी पीढ़ी के आर्थिक सुधारों और कुशल एवं पारदर्शी बाजारों पर लगातार काम कर रही है।

गौरवशाली भारत के स्वामी प्रकाशक एवं मुद्रक प्रवीण कुमार सिंह द्वारा आला प्रिंटिंग प्रेस 3636 कटारा दिना बेग लाल कुआं, दिल्ली.... से मुद्रित एवं, ब्लॉक नं. 23 मकान नं. 399 त्रिलोकपुरी दिल्ली....91
से प्रकाशित संपादक -प्रवीण कुमार सिंह, टेलीफोन नं. 011.22786172 फैक्स नं. 011.22786172
RNI, No. DELHIN383334, E-mail: gauravashalibarat@gmail.com इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के पीआरबी एट के तहत

संक्षिप्त खबर

सासाराम में पुनरीक्षण के बाद भी मतदाता सूची में दर्ज हैं 62 हजार मृतकों के नाम, वर्षों पूर्व मृत हुए लोग अब भी बने हुए हैं वोटर

सासाराम । रोहतास। संशोधन कार्य चलने के बाद भी मतदाता सूची में एक- दो नहीं बल्कि हजारों मृतकों का नाम अब भी दर्ज हैं। मरने के वर्षों बाद भी वे मतदाता सूची में बने हुए हैं। निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मी व अधिकारी मतदाता सूची से उनके नाम पूरी तरह विलोपित नहीं कर पाए हैं। इसका खुलासा कोरोना टीकाकरण को ले जिले में चले सर्वे से हुआ है। सर्वे कर्मियों ने सिर्फ ग्रामीण इलाके में 62 हजार वैसे लोगों को चिह्नित किया है, जिनकी मृत्यु एक-दो माह पूर्व नहीं, बल्कि वर्षों पहले हो गई है। ऐसे में प्रत्येक वर्ष निर्वाचन आयोग के निर्देश पर होने वाले मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पर सवाल उठने लगा है। बीएलओ की गलती या फिर तकनीकी त्रुटि से एक ही परिवार के कई सदस्यों को दूसरे वार्ड का वोटर बना दिया गया है। 61,940 मृत व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज-सर्वे के दौरान बीएलओ को भी निर्देश दिया गया था कि वे मतदाता सूची पुनरीक्षण से संबंधित आवश्यक प्रक्रिया को पूरा करेंगे। तीन दिवसीय सर्वे के दौरान मतदाता सूची के माध्यम से कर्मियों ने ग्रामीण इलाके के 3,278 वार्ड का डोर टू डोर पहचान कार्य चलाया। 18 वर्ष से ऊपर के 20,14,648 लोगों का नाम मतदाता सूची से मिलान कर उसमें से कोरोना टीका लेने से वंचित रहने वालों की पहचान की गई। जिसमें कर्मियों ने पाया कि 2,47,833 ऐसे लोग हैं जो दूसरे जगह शिफ्ट कर गए हैं। वहीं 61,940 मृत व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज है।

मतगणना के बाद फिर से एक साथ ही नजर आएगी राजद व कांग्रेस, शिक्षा मंत्री ने लालू के लिए कही बड़ी बात

समस्तीपुर । शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि लालू जी के आने से परिवर्तन तो दिख रहा है। पहले जो एनडीए के पक्ष में हवा थी, वह और बेहतर हो रही है। आरंभिक दौर में हमलोगों को उनकी हुकूमत को याद दिलाने में परेशानी हो रही थी। नई पीढ़ी के लोगों को यह भरोसा भी नहीं हो रहा था कि कभी ऐसा भी बिहार था। वे खुद आए और जैसी-जैसी भाषा का प्रयोग किया। उससे हमारा काम और आसान हो गया। लोगों के दिमाग में वहीं पुरानी बातें आ गई। जिस ढंग से अमर्यादित, अशोभनीय भाषा का प्रयोग उन्होंने किया, पुराने दिनों के कुशासन की याद ताजा कर दी। इसके बाद स्वभाविक रूप से एनडीए के पक्ष में हवा चलने लगी। मुख्यमंत्री के संबंध में लालू प्रसाद के विसर्जन संबंधी बयान पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि इससे मुख्यमंत्री जी को बहुत सदमा लगा। लालू जी ने आते ही अपने पुराने शासन का ट्रेलर दिखा दिया। दोनों उपचुनाव में उनके अमर्यादित वक्तव्यों ने एनडीए की जीत को और आसान बना दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद द्वारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विसर्जन संबंधी बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे अशोभनीय और अमर्यादित टिप्पणी क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि इस बात से नीतीश कुमार जी को गहरा सदमा लगा है। लेकिन इसका जबाव विधानसभा उपचुनाव में वहां की जनता दोनों सीटों पर एनडीए प्रत्याशी को फिर से भारी जीत दिलाकर देने जा रही है। उपचुनाव में कांग्रेस और आरजेडी के बीच जारी मतभेद और एक दूसरे पर किये जा रहे बयानबाजी पर शिक्षा मंत्री ने कहा कि दोनों दल एक दूसरे का कंधा पकड़ कर चल रहे थे। जब दोनों दल को लगा कि अब दोनों ही डूब जाएंगे तो अलग-अलग दिखने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों एनडीए विरोध की ही भाषा बोल रहे हैं। लेकिन दो तारीख के बाद जब नतीजे आएंगे तो फिर से दोनों साथ-साथ ही नजर आएंगे। शिक्षा मंत्री कुशेश्वर स्थान और तारापुर में लगातार चुनावी दौरे के बाद समस्तीपुर परिसदन में मीडिया से बात कर रहे थे। मौके पर जदयू के प्रदेश महासचिव डा. दुर्गेश राय, पूर्व विधायक दुर्गा प्रसाद सिंह, अनिल सिंह बाबा समेत दर्जनों लोग उपस्थित रहे।

झारखंड में बरपा हंगामा...सांसद निशिकांत दूबे और आईएस मंजूनाथ में आर-पार की लड़ाई

रांची। गोड्डा के सांसद निशिकांत दूबे के खिलाफ देवघर में पांच प्राथमिकी दर्ज होने संबंधी विवाद से मंत्रिमंडल निर्वाचन आयोग ने पल्ला झाड़ लिया है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रविकुमार ने कहा कि इस मामले को भारत निर्वाचन आयोग स्वयं अपने स्तर से देख रहा है। जो भी कार्रवाई होगी आयोग के स्तर से होगी। इसमें राज्य के मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग की कोई भूमिका नहीं है। उधर इस विवाद ने मंगलवार को तूल पकड़ लिया। भाजपा जहां निशिकांत दूबे के समर्थन में शिकायत करने मंत्रिमंडल निर्वाचन आयोग के दफ्तर पहुंची, वहीं जामताड़ा के विधायक और प्रदेश कांग्रेस के पूर्व कार्यकारी अध्यक्ष डा. डाक्टर इरफान अंसारी देवघर के उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के पक्ष में खड़े हो गए। उन्होंने कहा है कि देवघर के उपायुक्त कानून के तहत कार्रवाई कर रहे हैं।

उन्होंने सांसद को हल्का आदमी बताते हुए नसीहत दी कि वे कानून का सम्मान करें और प्रशासनिक अधिकारियों पर अनावश्यक दबाव बनाना बंद करें। उन्हें कानूनी कार्रवाई में बाधा पैदा नहीं करना चाहिए। यह भी कहा कि उन्हें सांसद पद की मर्यादा का ख्याल नहीं है। जनता उन्हें नकार चुकी है। यही वजह है कि वे गोड्डा की बजाय देवघर में अधिक समय देते हैं। सांसद निशिकांत दुबे पर देवघर के नगर, मधुपुर, देवीपुर और चितरा थाने में पांच अलग-अलग मामले दर्ज हुए हैं। ये सभी मामले बीडीओ, जिला संपर्क अधिकारी के बयान पर दर्ज किए गए हैं। उधर प्रदेश भाजपा के पांच सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को राज्य निर्वाचन पदाधिकारी के. रवि कुमार से मुलाकात कर देवघर जिला प्रशासन की शिकायत की। प्रतिनिधिमंडल ने सांसद निशिकांत दुबे पर एक दिन में दर्ज कराई गई पांच प्राथमिकी का विरोध किया और राज्य निर्वाचन पदाधिकारी से आग्रह किया कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रतिनिधिमंडल ने आरोप लगाया कि देवघर जिला प्रशासन सत्ताधारी गठबंधन दलों के फ्रंटलाइन वर्कर की तरह काम कर रहा है। सांसद के खिलाफ की गई कार्रवाई दुर्भावना से प्रेरित है। आज न कोई आचार संहिता लागू है और न हीं कोई चुनाव हो रहा, फिर भी महीनों पुराने ट्वीट को आधार बनाकर प्राथमिकी दर्ज कराना एक चुने हुए जन प्रतिनिधि को जानबूझकर परेशान व अपमानित करने की मानसिकता को दर्शाता है। प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व प्रदेश महामंत्री डा. प्रदीप वर्मा ने किया।

रेलवे कर्मचारियों के लिए जाता है पी होगी दिवाली इस महीने तनख्वाह के साथ 3 महीने बकाया एरियर समय महंगाई भत्ता भी

धनबाद । रेलवे कर्मचारियों की जेब में दुर्गापूजा से पहले बोनस की रकम पहुंच गई थी। अब दिवाली से पहले उनकी जेब में तनख्वाह के साथ बढ़े महंगाई भत्ते के पैसे भी पहुंच जाएगे। पहले जहां महंगाई भत्ता 28 फीसद था, अब 31 फीसद मिलेगा। केंद्र सरकार ने जुलाई से महंगाई भत्ता देने की स्वीकृति दे दी है। ऐसे में जुलाई से सितंबर तक का बकाया के साथ महंगाई भत्ता और वेतन बैंक अकाउंट में पहुंचेगा। केंद्र से मिली मंजूरी के बाद धनबाद रेल मंडल के वित्त विभाग ने इसकी सारी तैयारियां पूरी कर ली है। एक-एक कर्मचारी से लेकर अफसरों तक की तनख्वाह में डीए जुड़ जाएगा। यानी कुल मिलाकर रेलवे में इस बार पहले ज्यादा हैप्पी दिवाली होगी।

रेलवे में सेवा दे रहे कर्मचारियों के साथ-साथ उन कर्मचारियों को भी बढ़े डीए का लाभ मिलेगा जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं। पर शायद इस महीने उन्हें इसका लाभ नहीं मिल सकेगा। जानकारों का कहना है कि पेंशनर्स को मिलने वाली रकम हर महीने 28 तारीख तक उनके खाते में भेज दी जाती है। इस बार भी उन्हें पेंशन की राशि भेज दी गई है। लिहाजा, बढ़े डीए का लाभ चार महीने के बकाया के साथ अगले महीने उन्हें मिल जाएगा। तीन महीने के एरियर के साथ 31 फीसद डीए मिलने की खबर मिलते ही रेलवे कर्मचारियों में जश्न का माहौल है। धनबाद रेल मंडल के तकरीबन 22 हजार कर्मचारी इस दायरे में आएंगे। कर्मचारियों के साथ मान्यता यूनियन ईस्ट सेंट्रल रेलवे कर्मचारी यूनियन इसे अपनी बड़ी जीत मान रही है। यूनियन की हिल कालोनी शाखा-दो दफ्तर में डीए की घोषणा को लेकर बैठक भी हुई। यूनियन के मीडिया प्रभारी एनके खवास ने कहा कि आल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के राष्ट्रीय महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने दो सप्ताह पहले ही इसकी घोषणा कर दी थी।

लखीमपुर खीरी हिंसा कांड के मुय आरोपित आशीष मिश्रा मोनू की जमानत पर अब तीन को सुनवाई

लखनऊ। लखीमपुर खीरी में तीन अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में चार किसान सहित आठ लोगों की मौत के मामले के मुख्य आरोपित आशीष मिश्रा मोनू की जमानत अर्जी कोर्ट ने गुरुवार को स्वीकार कर ली है। केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा की इस याचिका पर अब तीन नवंबर को सुनवाई की जाएगी।

लखीमपुर खीरी हिंसा के कांड में चार किसानों के साथ तीन भाजपा कार्यकर्ता तथा एक पत्रकार की हत्या के मामले के मुख्य आरोपित आशीष मिश्र मोनू सहित 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस केस में क्रास एफआइआर पर भी पुलिस एक्शन में है। सुमित जायसवाल की ओर से दर्ज कराई गई एफआइआर पर दो प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। लखीमपुर खीरी जिले की बहुचर्चित हिंसा मामले में केंद्रीय मंत्री के पुत्र आशीष मिश्र की जमानत पर सुनवाई गुरुवार को जिला जज मुकेश मिश्र की अदालत में टल गई है। इस मामले में अगली सुनवाई तीन नवंबर को होगी। गुरुवार को जिला जज की अदालत में होने वाली आशीष मिश्र की जमानत पर सुनवाई इसलिए टाल दी गई है क्योंकि अभी इस पूरे मामले में केस डायरी ही अपूर्ण है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक अभी इस हिंसा से जुड़े कई सबूत और फॉरेंसिक रिपोर्ट ही केस डायरी में संलग्न नहीं हो पाई है। इसके साथ ही कई गवाहों के बयान भी अदालत में दर्ज नहीं हो पाए हैं। इसके पीछे जिले में अचानक आई बाढ़ की आपदा को भी माना जा रहा है। आरोपित आशीष मिश्र की मेडिकल रिपोर्ट भी अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। ऐसे एक दो नहीं कई बिंदु है जिनको केस डायरी में शामिल किए बिना जमानत पर सुनवाई संभव नहीं थी। जिसके चलते अभियोजन पक्ष ने जिला जज की अदालत में प्रार्थना पत्र दाखिल करते हुए अभी इस मामले में कुछ और समय मांगा। जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने तीन को इस याचिका पर सुनवाई का निर्णय किया। दीपावली से ठीक दिन पहले अदालत में यह तय हो जाएगा कि आशीष मिश्र की जमानत यहां से होगी या नहीं।

इस केस में आशीष मिश्रा मोनू से पहले गिरफ्तार आरोपित लवकुश राणा तथा आशीष पाण्डेय की जमानत अर्जी बुधवार को जिला जज की अदालत में दाखिल की गई। इसके बाद दोनों की जमानत पर सुनवाई के लिए तीन नवम्बर की तिथि नियत की गई है।

हिंसा से जुड़े एक दर्जन गवाहों के और बयान दर्ज- लखीमपुर खीरी के तिकुनिया हिंसा कांड कांड के मामले में न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बुधवार को एक दर्जन और गवाहों के बयान दर्ज किए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद विवेचक ने घटना के गवाहों के मजिस्ट्रेट के समझ 164 सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज कराने की कवायद शुरू कर दी थी। पहले दिन घटना के मामले में पांच गवाहों के बयान दर्ज हुए थे। 21 अक्टूबर को चार गवाही के बयान, 22 अक्टूबर को 12 गवाहों के बयान, 25 अक्टूबर को सात गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे। 26 अक्टूबर मंगलवार को तीन और गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज किए गए थे। 27 अक्टूबर बुधवार एक दर्जन गवाहों के बयान दर्ज किए गए। अब तक 42 गवाहों के बयान मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज कराए जा चुके हैं। माना जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई से पूर्व सभी गवाहों के बयान दर्ज कराने में एसआइटी ने कवायद शुरू कर दी है।

दिन में 12 बजे सोकर उठने वाला मुख्यमंत्री जनता के बारे में नहीं सोच पाएगा- योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बेहद गंभीर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भाजपा की हर कमजोर कड़ी को मजबूत करने में लगे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ लखनऊ में गुरुवार को तीन सामाजिक सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। उत्तर प्रदेश गन्ना संस्थान के हाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने सामाजिक प्रतिनिधि सम्मेलन में कहा कि पिछ्ली सरकारों के पास कोई सोच नहीं थी। अगर कहीं सोच भी लिया तो उस सोच को धरातल पर उतारने की फुरसत नहीं थी। जब प्रदेश का मुख्यमंत्री दोपहर 12 बजे सोकर उठेगा तो कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो जनता के बारे में सोच पाएगा। समाज की कोई जानकारी उसको नहीं होगी।

सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आपने 2014 के बाद बदलते हुए भारत को देखा है। आज भारत ना केवल वैश्विक मंच पर बल्कि अपनी परंपरा को बनाए रखने के लिए दुनिया के सामने एक ताकत के रूप में उभरा है। आपको याद होगा जब महामारी आई थी तब जितनी भी विपक्षी पार्टियां थीं, चाहे सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, सभी आइसोलेशन में थी। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आने लगे तो सब बाहर आ गए।

प्रदेश में 2012 में कोसीकलां से जो दंगों का सिलसिला शुरू हुआ था वह निरंतर चलता रहा। पहले की जो सरकार थी वो अपने लिए जीते थे। वह अपने परिवार के लिए जीते थे और उन्हें समाज और गरीब से कोई लेना-देना नहीं था। 2014 के पहले कांग्रेस नेतृत्व की सरकार देश के अंदर रोज एक घोटाला लेकर आती थी। दुनिया के अंदर भारत की छवि अत्यन्त धूमिल थी। भारत के नौजवानों के सामने पहचान का संकट खड़ा हुआ था और असुरक्षा का वातावरण था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस सम्मेलन में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह तथा प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी इस सम्मेलन को संबोधित किया।

राम मंदिर में लगेगा श्रीलंका के अशोक वाटिका का पत्थर, रामलला के दरबार में शिला लेकर पहुंचे श्रीलंका से राजनायिक

अयोध्या । मंदिर निर्माण के लिए अशोक वाटिका की शिला गुरुवार को अयोध्या पहुंची। श्रीलंका के उच्चायुक्त मिलिंद मोरा गोडा के नेतृत्व में श्रीलंका के एक प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को प्रथम बेला में रामलला का दर्शन किया। इस दौरान श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को अशोक वाटिका से लाई गई शिला भेंट की। यह शिला युगों पुराने अयोध्या और श्रीलंका के संबंधों की याद दिलाने वाली है। अपहरण के बाद रावण मात सीता को श्रीलंका की इसी अशोक वाटिका में रखा था और माता सीता की हनुमान जी से भेंट अशोक वाटिका में ही हुई थी। राम जन्मभूमि परिसर में श्री लंका के प्रतिनिधिमंडल का तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अलावा अयोध्या के साधु संतों ने स्वागत किया।

स्वागत करने वालों में मणिराम दास जी की छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास जगद्गुरु रामानंदाचार्य स्वामी रामदिनेशाचार्य उदासीन ऋषि आश्रम के महंत डा भरत दास अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता महंत गौरी शंकर दास आचार्य मिथिलेश नंदिनी शरण राम कचहरी मंदिर के महंत शशिकांत दास महंत हरसिद्धि शरण कृपालु राम भूषण दास राम कुमार दास महंत छविरामदास पार्षद एवं हनुमानगढ़ी के पुजारी रमेश दास आदि प्रमुख रहे। इन संतो ने अशोक वाटिका की शिला को हृदयस्पर्शी बताया और कहा इसका अयोध्या आना श्री राम और मां सीता के अनुरागी समूह के लिए अत्यंत गौरवपूर्ण है और इसे पूरे सम्मान के साथ राम मंदिर में संरक्षित प्रतिष्ठित किया जाएगा।

तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने भी स्वीकार किया कि इस शिला के प्रति पूरा सम्मान अर्पित किया जाएगा। हालांकि अभी यह नहीं तय किया जा सका है कि राम मंदिर में अशोक वाटिका से आई शिला का किस रूप में प्रयोग होगा।

शिला समर्पित करने के बाद श्रीलंका के प्रतिनिधिमंडल ने अयोध्या राज्य परिवार के प्रासाद राज सदन में पत्रकारों से वार्ता की। श्रीलंका के उप उच्चायुक्त नीलूका कदरगमआ ने बताया कि श्रीलंका में रामायण राम कथा और अयोध्या के बारे में सभी जानते हैं। 20 वर्ष पूर्व से श्रीलंका में रामायण यात्रा नाम की एक परियोजना संचालित है।

श्रीलंका की रामायण यात्रा में बहुत से भारतीय भी शामिल होते हैं और वे श्रीलंका में रामायण कालीन अवशेषों का दर्शन करते हैं। इस मौके पर राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य एवं अयोध्या राज परिवार के मुखिया विमलेंद्र मोहन मिश्र तीर्थ क्षेत्र के एक अन्य सदस्य डॉ अनिल मिश्र एवं विहिप के प्रांतीय प्रवक्ता शरद शर्मा प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

बिहार के सिवान में बड़ी वारदात, गोली मार हत्या के बाद भाग रहे अपराधी को पीट-पीटकर मार डाला

सिवान । बिहार के सिवान जिले में मॉब लिंचिंग की बड़ी वारदात हुई है। गोली मारकर हत्या के बाद भाग रहे आरोपित को लोगों ने पीट-पीटकर मार डाला। मॉब लिंचिंग का शिकार कुख्यात ओम प्रकाश गोंड है। उसपर शराब तस्तकरी समेत हत्या के दो मामले दर्ज हैं। वह कुछ माह पहले ही जेल से जमानत पर बाहर आया था। ओम प्रकाश गुरुवार की सुबह सत्यदेव गोंड की गोली मारकर हत्या करने के बाद भागने के दौरान ग्रामीणों के हत्थे चढ़ गया। गांव के लोग काफी आक्रोशित हैं। घटना सिवान के आंदर थाना क्षेत्र की कुशहरा पंचायत के मीरपुर गांव में हुई।

बताया जाता है कि सत्यदेव गोंड और ओम प्रकाश गोंड आपस में पट्टीदार हैं। ओम प्रकाश रिश्ते में सत्यदेव का भतीजा था। मीरपुर गांव में रघुनाथपुर के राष्ट्रीय जनता दल विधायक हरिशंकर यादव के घर के सामने ही सत्यदेव का घर है। आज सुबह पैसे को लेकर कोई विवाद हुआ इसके बाद ओमप्रकाश ने सत्यदेव गोंड की सीने में गोली मार दी। हत्या के बाद वह भागने लगा। इस बीच हत्या से गुस्साए गांव के लोगों ने उसे घेर लिया तथा लाठी-डंडे से पीटकर मौत के घाट उतार दिया।

यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो फिर बांटेंगे लैपटाप, आजमगढ़ में बोले अखिलेश यादव

आजमगढ़। जिस समय हाईस्कूल और इंटर का रिजल्ट आया तो मुझे लगा कि सरकार मेधावी बच्चों का सम्मान करेगी, क्योंकि भाजपा के संकल्प पत्र में लिखा है कि सरकार बनने पर बच्चों को लैपटाप के साथ डेटा भी फ्री देंगे, लेकिन साढ़े चार साल बीतने के बाद भी नहीं दिया। ऐसे में हमने सरकार को याद दिलाने के लिए कुछ बच्चों को लैपटाप देने का फैसला लिया।सरकार बनी तो मेधावी बच्चों को फिर लैपटाप बांटेंगे। यह बातें पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गुरुवार को सेहदा स्थित श्री दुर्गा जी इंटर कालेज में छात्र-छात्राओं के सम्मान समारोह में कही।

उन्होंने कहा कि अब सुना हूं कि सरकार टैबलेट बांटने जा रही है, लेकिन उनसे पूछना चाहता हूं कि साढ़े चार साल में आपने इतने दिनों तक कौन सी टैबलेट इन बच्चों को दी।कहा कि नई पीढ़ी नई तरीके से पढ़ाई करना चाहती है। इसीलिए हमने मेधावी बच्चों को लैपटाप देने का फैसला किया था। कोरोना काल में वही लैपटाप बच्चों के पढ़ाई के काम आया।

अखिलेश ने कहा कि हमारे इस फैसले से बाबा सोच में पड़ गए हैं कि कौन आ रहा है तो कहना चाहूंगा कि हमारा लैपटाप खोल लें, पता चल जाएगा, जिसमें हम और नेताजी ही दिखाई देंगे। प्रदेश की 24 करोड़ लोग भाजपा का सफाया कर देंगे, लेकिन वह चलाना ही नहीं जानते, चलाना जानते तो बांटा होता।

पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सरकार में गांव में बैठे लोगों को इलाज उपलब्ध कराने के लिए 102 और 108 नंबर की एंबुलेंस चलाई गई।100 नंबर पुलिस की व्यवस्था की, ताकि लोगों को तुरंत पुलिस पहुंच जाए। भाजपा सरकार ने उस नंबर को 112 कर दिया, लेकिन पुलिस तो अब भी पहुंच रही है।सरकार केवल नाम बदलना जानती है, शिलान्यास का शिलान्यास और उद्घाटन का उद्घाटन कर रही है।पूर्व सीएम ने कहा कि हमारी सरकार होती, तो पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे देश की सबसे अच्छी सड़क होती, लेकिन भाजपा सरकार ने सड़क को खराब कर दी। इस पर सफर करने वालों को पेट और कमर में दर्द हो जाएगा।यही नहीं मेरी सरकार होती, तो अब तक इसका लोकार्पण हो गया होता। दावा किया कि जिस तरह से हमने आगरा की सड़क पर जहाज उतारा था उसी तरह से सरकार बनने पर पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर जहाज उतारने के बाद ही इसका लोकार्पण होगा।उन्होंने किसानों, बेरोजगारों, नौजवानों की समस्याओं के साथ महंगाई पर भी विस्तार से चर्चा की।

खूंटी में 550 ग्राम अफीम के साथ दो धराए

खूंटी। अड़की थाना क्षेत्र के मदहातु व तिनतिला के आसपास जंगल क्षेत्र में नक्सलियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस ने दो युवकों को 550 ग्राम अफीम और छह लाख चार हजार 70 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्तों में अड़की थाना क्षेत्र के मारंगबुरू टोला माईलचिगी के रहने वाले 28 वर्षीय रौकन मुंडा और बगड़ी टोला गिरजाटोली के रहने वाले 35 वर्षीय लक्ष्मण स्वांसी शामिल हैं। इसकी जानकारी खूंटी जिला के पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर ने दी। उन्होंने बताया कि नक्सली गतिविधियों के सूचना के आलोक में मारंगहादा स्थित सीआरपीएफ 133 बटालियन के अधिकारी व जवानों के साथ अड़की थाना की पुलिस टीम द्वारा अड़की थाना क्षेत्र के मदहातु व तिनतिला के आसपास जंगल इलाका में नक्सलियों के विरूद्ध अभियान चलाया जा रहा था।

वाराणसी में अन्नपूर्णा मंदिर में चार दिन होगा स्वर्णमयी रूप का होगा दर्शन

वाराणसी । प्रत्येक वर्ष धनतेरस से शुरू होने वाली स्वर्णमयी अन्नपूर्णा का दर्शन इस वर्ष 2 नवंबर से (धनतेरस पर्व) से शुरू होगा जो 5 नवंबर अन्नकूट पर्व तक चलेगा। दर्शन-पूजन और आयोजन के संदर्भ में गुरुवार को बांसफाटक स्थित श्रीकाशी अन्नपूर्णा अन्नक्षेत्र ट्रस्ट के दूसरी शाखा के सभागार में एक पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। जिसमें महंत शंकरपुरी ने बताया कि इस वर्ष भी पूरा विश्व कोरोना महामारी लड़ रहा। बाबा विश्वनाथ और मां भगवती के आशीर्वाद व्यवस्थाएं धीरे-धीरे पटरी पर आ गई है। हालांकि खतरा अभी टला नहीं है। उन्हीने बताया कि धनतेरस दिन 2 नवंबर से शुरू हो रहे स्वर्णमयी अन्नपूर्णा के दर्शन के दौरान कोविड-19 के बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करवाते हुए भक्तों को दरबार में प्रवेश दिया जाएगा।

भक्त मन्दिर के प्रथम तल पर स्थित माता के दर्शन करेंगे। गेट पर ही माता का खजाना और लावा वितरण भक्तों में किया जाएगा। केवल प्रथम दिन ही भक्त पीछे के रास्ते से राम मंदिर परिसर होते कालिका गली से निकास दिया जाएगा। मन्दिर प्रबन्धक काशी मिश्रा ने बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से मंदिर में जगह-जगह वालेंटियर तैनात किए जाएंगे। थर्मल स्कैनिंग और हैंड सेनेटाइजेशन के बाद भक्तों को माता के दरबार में प्रवेश दिया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। सुरक्षा की दृष्टी से मन्दिर परिसर में दो दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। मेडिकल की व्यवस्था की भी रहेगी। स्वर्णमयी मां अन्नपूर्णा का छोटी दीपावली से अन्नकूट पर्व तक के दर्शन भोर में 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक होगा। वीआइपी समय शाम 5 से 7 रहेगा। वृद्ध और दिव्यांगों के लिए दर्शन की सुगम व्यवस्था रहेगी। प्रेसवार्ता के दौरान प्रो रामनरायण द्विवेदी समेत मन्दिर परिवार सदस्य मौजूद रहे ।

देवाधिदेव महादेव के आंगन में सजे मां अन्नपूर्णेश्वरी के दरबार की प्रतिष्ठा का अंदाजा इससे ही लगा सकते हैं कि इसमें बाबा स्वयं याचक रूप में खड़े हैं। मान्यता है बाबा अपनी नगरी के पोषण के लिए मां की कृपा पर आश्रित हैं। उपलब्ध इतिहास पर गौर करें तो बाबा विश्वनाथ के यहां वास से पहले ही देवी अन्नपूर्णा विराजमान हो चुकी थीं। वर्ष 1775 में जब बाबा विश्वनाथ मंदिर का निर्माण शुरू हुआ तब पार्श्?व भाग में देवी अन्नपूर्णा का मंदिर मौजूद था। माता की स्वर्ण प्रतिमा अपने आप में अनूठी है। रजत शिल्प में ढले शिव बाबा की झोली में अन्नदान करती अन्न दात्री की कमलासन पर ठोस सोने की मूर्ति व दायीं ओर मां लक्ष्मी और वाम भाग में भूदेवी की भी स्वर्ण प्रतिमा विराजमान है। साल में चार दिन दर्शन उत्सव के दौरान धान का लावे, बताशा संग मां का खजाना (सिक्का) वितरण की परंपरा है। अन्य दिनों में मंदिर गर्भगृह में स्थापित सामान्य प्रतिमा की दैनिक पूजा की जाती है।

सीतापुर के नैमिषारण्य पहुंचे छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डा रमन, कहा- यूपी में चौथे-पांचवें नंबर के लिए लड़ेगी कांग्रेस

सीतापुर । भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह गुरुवार को नैमिषारण्य आए। पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर तीखे शब्दबाण छोड़े। कहा कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से छत्तीसगढ़ तो संभल नहीं रहा है। उन्हें छत्तीसगढ़ की चिंता भी नहीं है। मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ से आकर लखीमपुर में 50-50 लाख रुपये बांट रहे हैं। उन्होंने आरोप मढ़ा कि छत्तीसगढ़ में पुलिस की गोली से आदिवासियों की मौत होती है, लेकिन मुख्यमंत्री को वहां जाने की फुर्सत नहीं मिलती है। यूपी में कांग्रेस के लैपटाप और स्कूटी देने के वादे पर भी पूर्व मुख्यमंत्री ने छत्तीसगढ़ के सीएम पर चुटकी ली।

कहा कि जिस तरह से वह उप्र में मदद बांट रहे हैं, उससे यही लगता है कि अगला चुनाव यहीं से लड़ने वाले हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में विकास रुक गया है, लेकिन उप्र आकर वह बड़ी-बड़ी बातें करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि भूपेश बघेल जहां भी प्रभारी बनकर जाते हैं, वहां चुनाव हारते हैं। असम के प्रभारी थे, वहां चुनाव हारे। कहा, यूपी में तो कांग्रेस की लड़ाई चौथे और पांचवें नंबर की है। विकास के सवाल पर छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रशंसा की। कहा कि सीएम जिस तरह से विकास कर रहे हैं, उससे एक दिन नैमिषारण्य भी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में सफल होगा। चक्रतीर्थ और मां ललिता देवी के किए दर्शन ~र्व मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह नैमिषारण्य आकर सबसे पहले अतिथि गृह पहुंचे।

केवल नाम का रह गया हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, महेशखूंट में एक भी दिन नहीं आते हैं डाक्टर

महेशखूंट (खगडिया)। अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र महेशखूंट को हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर का दर्जा मिल चुका है। लेकिन इस अस्पताल का 'हेल्थ' नहीं सुधरा है। अपितु दिनोंदिन व्यवस्था बिगड़ती ही जा रही है। जबकि इससे महेशखूंट समेत आसपास के कई पंचायतें जुड़ी हुई है।

यहां समस्याओं का अंबार है। अस्पताल एनएच 31 के किनारे हैं। परंतु, संपर्क पथ जर्जर है। अतिक्रमण के कारण अस्पताल परिसर से होकर आम रास्ता है। परिसर में पशु बांधे जाते हैं। दबंगों के डर से कोई रोकने-टोकने वाला नहीं हैं। सफाई कर्मचारी दिन भर यहां सूप बुनते रहते हैं। जिससे अस्पताल परिसर में बांस की कमानी व कचरा पसरा रहता है।

यहां कर्मियों की घोर कमी है। महेशखूंट चौक से कुछेक सौ मीटर पूरब एनएच 31 के किनारे अवस्थित यह अस्पताल अतिक्रमण की चपेट में है। चारों ओर गंदगी का आलम है। यहां पेयजल तक की सुविधा नहीं है। विभागीय नियम के तहत सरकारी अस्पताल के दो सौ गज के दायरे में कोई निजी नर्सिंग होम नहीं रहना चाहिए।

लेकिन लगभग 50 मीटर की दूरी पर नर्सिंग होम संचालित है। इस ओर विभागीय अधिकारियों का ध्यान नहीं है। मालूम हो कि महेशखूंट में फर्जी नर्सिंग होम, क्लिनिक और जांचघर का कारोबार खूब फल-फूल रहा है। सूत्रों के अनुसार विभागीय अधिकारी अस्पताल विजिट के क्रम में सब देखते हैं, मगर चुप्पी साधे हुए रहते हैं।

चारदीवारी नहीं रहने से अस्पताल होकर आम रास्ता है। चिकित्सकों के लिए बने क्वार्टर दो दशक से जर्जर है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. गुफरान ने कहा कि समय- समय पर तमाम जानकारियां वरीय अधिकारियों को दी जाती रही है।

अस्पताल में तीन चिकित्सक पदस्थापित हैं। जिसमें प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डा. गुफरान प्रत्येक दिन आते हैं। जबकि स्थानीय लोगों के अनुसार दो चिकित्सकों के दर्शन दुर्लभ हैं। कहने का मतलब एक चिकित्सक के भरोसे यह अस्पताल चल रहा है। एक मात्र प्रयोगशाला प्रावैद्यिकी उमेश कुमार झा का भी ताबादला सदर अस्पताल हो गया है।

अब यह पद भी रिक्त है। यहां पर क्लर्क, फार्मासिस्ट, कंपाउंडर, सामान्य प्रयोगशाला प्रावैद्यिकी, निबंधक, दवा वितरक, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी तक नहीं है। भगवान भरोसे अस्पताल चल रहा है।

आउट सोर्सिंग के चिरंजीवि कुमार रोगियों का निबंधन से लेकर दवा तक का वितरण करते हैं। महेशखूंट थानाध्यक्ष नीरज कुमार ठाकुर ने कहा कि एनएच-31, एनएच-107 और महेशखूंट-अगुवानी पथ महेशखूंट होकर गुजरती है। बराबर दुर्घटना घटती रहती है। लेकिन महेशखूंट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में समुचित सुविधा नहीं रहने के कारण दुर्घटना में घायल व्यक्ति को यहां से आठ किलोमीटर दूर रेफरल अस्पताल गोगरी भेजना पड़ता है। समय पर इलाज नहीं होने के कारण कई बार घायल व्यक्ति की स्थिति गंभीर हो जाती है।

संक्षिप्त समाचार

हर बूथ पर होगी हमारी टीम की नजर : भूपेंद्र सिंह

भोपाल, (एजेंसी)। भाजपा की चुनाव प्रबंध समिति के संयोजक भूपेंद्र सिंह ने कहा कि प्रबंध समिति के हर सदस्य को उपचुनाव वाली एक-एक विधानसभा की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो हर बूथ अध्यक्षों से तैयारियों की जानकारी लेंगे। श्री सिंह ने गुरुवार को यहां मीडिया से चर्चा में कहा कि कांग्रेसी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में शराब और पैसा न बांट पाएं इस पर हमारी नजर रहेगी। हमारी लीगल टीम एक-एक मिनट की जानकारी लेकर किसी भी गड़बड़ी की शिकायत निर्वाचन आयोग से करेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी किसी तरह की गड़बड़ न कर पाएं इसको लेकर हमारी टीम तैनात रहेगी। प्रत्येक बूथ पर हमारे कार्यकर्ता 'आओ मिलकर दीप जलाएं, घर घर जाकर कमल खिलाएं' स्लोगन के साथ जनसंपर्क करेंगे और लोगों से मतदान की अपील करेंगे। कांग्रेस के सदस्यता अभियान की शर्तों पर श्री सिंह ने तंज कसते हुए कहा कि सदस्यता करने वाला कोई नहीं बचेगा, जो नशा न किया हो। जो पार्टी एक परिवार पर चलने वाली कंपनी है। उस पार्टी के लिए इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है।

डॉ. मिश्रा ने किया सांसद तुलसी के बयान पर पलटवार

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने राज्यसभा सांसद तुलसी के बयान पर कड़ा पलटवार किया है। मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राज्यसभा सांसद का बयान बेतुका है और कांग्रेसी नेता अभी नशे में है वह युवाओं को नशे की तरफ भेजने की बात कर रहे हैं। डॉ. मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस नेताओं द्वारा पीढ़ी को बर्बाद करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेसी नेताओं को वकालत करने की आदत हो गई है। बता दें कि देश के जाने-माने कानूनविद और राज्यसभा सांसद केटीएस तुलसी ने ड्रग्स को गुटका शराब सिगरेट की तरह छूट दिए जाने की वकालत की है। तुलसी का बयान उस समय आया है जब ड्रग्स के आरोप में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान जेल में है।

बड़वाह के एसडीओपी मानसिंह ठाकुर को हटाया

भोपाल । चुनाव आयोग द्वारा गुरुवार को बड़वाह जिला खरगौन के एसडीओपी मानसिंह ठाकुर को हटाने के निर्देश के बाद गृह विभाग ने उन्हें डीएसपी पुलिस मुख्यालय भोपाल भेज दिया है। वहीं विनोद दीक्षित कार्यवाहक डीएसपी जिला विशेष शाखा इंदौर को एसडीओपी बड़वाह जिला खरगौन पदस्थ किया है।

अवधेश प्रताप सिंह राठौर भाजपा से निष्कासित

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश भाजपा ने निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते प्रदेश कार्यसमिति के पूर्व सदस्य अवधेश प्रताप सिंह राठौर को गुरुवार को पार्टी से निष्कासित कर दिया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए श्री राठौर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निष्कासित कर दिया। श्री राठौर पर आरोप हैं कि उनके द्वारा पृथ्वीपुर से भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी के विरुद्ध निरंतर पार्टी विरोधी गतिविधियां की जा रहीं थीं। इसको लेकर भाजपा नेतृत्व द्वारा उन्हें आगाह भी किया गया था। श्री राठौर के इस कृत्य से पार्टी की छवि धूमिल हो रही थी, जो अनुशासनहीनता की श्रेणी में आती है।

जो वीर होते हैं वो घोषणाएं नहीं बल्कि काम करते हैं

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा उपचुनाव के दौरान अपने भाषणों में जो वीर होते हैं वही घोषणाएं करते हैं, पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कमलनाथ ने पलटवार किया है। कमलनाथ ने ट्वीट करते हुए कहा है कि शिवराज जी आपको तो सिर्फ मैं ही नहीं, आपकी पार्टी के नेता भी घोषणावीर कहते हैं। और वैसे भी जो वीर होते हैं वो कभी घोषणाएं नहीं करते हैं बल्कि काम करते हैं, घोषणाएं कर जनता को गुमराह करने का काम तो हमेशा कमजोर और झूठे व्यक्ति करते हैं। आपने 17 वर्ष में किया क्या, सिर्फ झूठ बोलना, झूठे सपने दिखाना, झूठी घोषणाएं करना। याद रखना दो नवंबर से प्रदेश से आपकी उल्टी गिनती चालू हो जाएगी और जनता आपको वापस जमीन पर ले आएगी, जैसे वर्ष 2018 में लाई थी, दमोह उपचुनाव में लाई थी।

नकुलनाथ आज करेंगे किसान आंदोलन की शुरुआत

भोपाल । कांग्रेस सांसद नकुल नाथ 29 अक्टूबर को छिंदवाड़ा में दोपहर 12.30 बजे किसान आंदोलन की शुरुआत करेंगे। इस दौरान वे किसानों की समस्याएं उठाएंगे। किसान आंदोलन में नकुल नाथ प्रदेश के किसानों के सामने आ रही खाद और बीज की समस्या, डीजल के बड़े हुए दाम, किसानों को सही ढंग से बिजली नहीं मिलने के बारे में किसानों की मांगों को प्रमुखता से उठाएंगे। इस विशाल जनसभा में कांग्रेस के विधायक हैं और स्थानीय नेता गण तथा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में शामिल होंगे। किसानों की समस्या के अलावा मोदी सरकार और शिवराज सिंह सरकार द्वारा जनता पर लगातार थोपी जा रही महंगाई के विषय पर भी कांग्रेस सांसद जनता की आवाज को उठाएंगे।

भाजपा ने की चुनाव आयोग से शिकायत

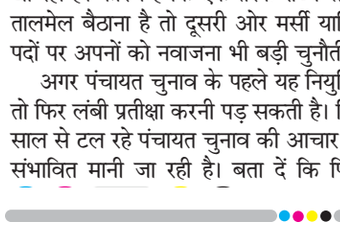

भोपाल । रैगांव से भाजपा की दलित महिला उम्मीदवार प्रतिमा बागरी के विरुद्ध विपक्षी पार्टी द्वारा स्थानीय समाचार पत्रों में बेहद आपत्तिजनक, अमर्यादित और शर्मनाक समाचारों का प्रकाशन कराए जाने को लेकर गया भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष सीमा सिंह एवं महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज की। महिला नेत्रियों के प्रतिनिधिमंडल ने शिकायत में कहा कि विपक्षी पार्टी के इशारे पर समाचार पत्र सेमरिया एक्सप्रेस द्वारा रैगांव से पार्टी प्रत्याशी प्रतिमा बागरी के संबंध में अशोभनीय और तथ्यहीन समाचार प्रकाशित किए गए। यह संपूर्ण नारी जाति एवं दलित महिला का अपमान है। चुनाव आयोग में शिकायत करते हुए महिला नेत्रियों ने दलित महिला के प्रताड़ना के विरुद्ध उचित प्रावधानों में एफआईआर दर्ज कर यशोचित कार्रवाई करने की मांग की है।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने केंद्रीय उर्वरक मंत्री मंडाविया से की फोन पर चर्चा

प्रदेश के लिए तत्काल मांगा यूरिया

प्रदेश में कल तक पहुंचेंगे 32 अतिरिक्त रैक

भोपाल (एजेंसी)। प्रदेश में यूरिया सहित अन्य उर्वरक की कमी अब 25 से अधिक जिलों में हो गई है। उर्वरक संकट के चलते किसानों का आक्रोश लगातार बढ़ रहा है। कुछ जिलों में कानून-व्यवस्था की स्थिति से निपटने के लिए पुलिस और प्रशासन को सतर्क कर दिया गया है।

इस बीच प्रदेश में उर्वरक संकट के चलते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को केंद्रीय उर्वरक और रसायन मंत्री मनसुख मंडाविया से फोन पर चर्चा की और प्रदेश के लिए तत्काल रैक उपलब्ध कराने का आग्रह किया। बाद में मुख्यमंत्री ने खाद की स्थिति को लेकर आला अफसरों को मुख्यमंत्री निवास में तलब किया और स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा

कि प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार डीएपी, यूरिया, एनपीके की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाएगी, किसान भाई परेशान न हों। खाद की कमी की मानसिकता छोड़ें, चिंता न करें, समय-समय पर आवश्यक मात्रा में खाद उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के विभिन्न स्थान पर 32 अतिरिक्त रैक 30 अक्टूबर तक पहुंचेंगे। यह यूरिया किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। नवंबर में खाद की आपूर्ति के लिए भारत सरकार से चर्चा की है। प्रदेश की आवश्यकता के अनुसार हमें खाद निश्चित रूप से मिलेगी।

किसी भी स्थिति में नहीं हो खाद की कालाबाजारी

चौहान ने कहा कि पिछले वर्ष अक्टूबर के अंत तक 3 लाख 48 हजार मीट्रिक टन यूरिया किसान भाई-बहनों द्वारा उठाया गया था। इस साल 3 लाख 18 हजार मीट्रिक टन उठा लिया गया है। बाकी शेष बची मात्रा भी इस माह के अंत तक उपलब्ध करा दी जाएगी। गत वर्ष अक्टूबर माह के अंत तक 2 लाख 78 हजार मीट्रिक टन यूरिया किसान द्वारा खरीदा गया था। इस साल 2 लाख 31 हजार मीट्रिक टन यूरिया किसान भाई-बहन खरीद चुके हैं और बची हुई शेष मात्रा भी उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एनपीके भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। चौहान ने किसान भाइयों से आवश्यकता पड़ने पर एनपीके और सुपर फास्फेट का उपयोग करने की अपील भी की। मुख्यमंत्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिलों में किसी भी स्थिति में खाद की कालाबाजारी न हो तथा न्यायपूर्ण वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

दिवाली बाद लग सकती है पंचायत चुनावों के लिए आचार संहिता

भोपाल, (एजेंसी)। प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में घोषित होने की पूरी उम्मीद है। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसकी पूरी तैयारी कर ली है और अब औपचारिक घोषणा होना बाकी है। मिली जानकारी के अनुसार पंचायत चुनाव नवंबर के दूसरे सप्ताह में घोषित हो जाएंगे और 31 दिसंबर तक चुनावी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग पहले ही सभी जिलों के कलेक्टरों को चुनावी तैयारी पूरी करने के लिए कह चुका है। सरकार के स्तर पर भी अब जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की प्रक्रिया शेष रह गई है जिससे किसी भी दिन पूरा किया जा सकता है। दीपावली के तुरंत बाद राज्य निर्वाचन आयोग इन चुनावों की किसी भी दिन घोषणा करेगा और उसके साथ ही चुनाव का पूरा शेड्यूल घोषित हो जाएगा। दरअसल पंचायतों के चुनाव जल्द कराने की वजह यह भी है कि यदि यह चुनाव अगले साल के लिए टलते हैं तो फिर नई मतदाता सूची के आधार पर होंगे और उसमें लंबा वक्त लग जाएगा।

प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने मुद्रा योजना का दायरा बढ़ाया

भोपाल (एजेंसी)। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की युवाओं को रोजगार देने के लिए मुद्रा योजना का दायरा व्यापक किए जाने की मंशा अनुरूप प्रदेश में जिला स्तर पर क्रेडिट आउटरीच अभियान में अधिक से अधिक हितग्राहियों को मुद्रा लोन दिए जाने के निर्देश सभी जिला उद्योग कार्यालयों को उद्योग आयुक्त पी.नरहरि ने दिए हैं।

उद्योग आयुक्त नरहरि ने बताया कि इसमें युवा वर्ग को स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य है। युवा वर्ग ऋण लेकर सूक्ष्म उद्योगों के माध्यम से न केवल आजीविका कमाता है वरन् रोजगार प्रदाता बनता है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों को गति मिलती है और क्षेत्र का विकास होता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना केंद्र सरकार की लोकप्रिय और व्यापक स्वरोजगार योजना है। जिसमें गैर कार्पोरेट कारोबार से आय के लिए लोगों को विनिर्माण, व्यापार और सेवा गतिविधियों के लिए 50 हजार से 10 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। इस योजना में वाणिज्यिक बैंक, आरआरबी, एमएफआई,एनबीएफसी और लघु वित्त बैंकों द्वारा मुद्रा ऋण दिए जाते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार कर जिला, ब्लॉक स्तर पर बैंकों द्वारा 16 अक्टूबर से 15 नवंबर तक क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रमों में मुद्रा ऋण के प्रकरण बनाए जाएंगे।

10 लाख रुपए तक का ऋण मिलेगा योजना के तहत

जिलों में लगेंगे जागरूकता शिविर

सभी प्रमुख जिला, ब्लॉक स्तर के कार्यालयों में योजना की जानकारी का बैनर, होर्डिंग प्रदर्शित किए जाएंगे। योजना के प्रचार-प्रसार के लिए अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा बैंकों के समन्वय से जिला, ब्लॉक स्तर पर प्रतिमाह कम में कम एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाएगा। जिला स्तर के विभिन्न शासकीय कार्यक्रमों, समारोह आदि में मुद्रा योजना का विशेष रूप से प्रचार-प्रसार किया जाएगा और मुख्य अतिथि, जन-प्रतिनिधि से हितग्राहियों को ऋण वितरण कराया जाएगा। योजना की संपूर्ण मॉनीटरिंग जिला कलेक्टर द्वारा की जाएगी।

ग्राम सभाओं में हो पंचायतों के कार्यों की मॉनीटरिंग : कुमार

दो दिवसीय कार्यशाला में वीसी के माध्यम से पंचायती राज मंत्रालय के सचिव ने कहा

भोपाल (एजेंसी)। ग्रामों के सतत संवहनीय एवं समावेशी विकास के लिए उनका वाइब्रेंट जीवंत होना आवश्यक है। केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों के साथ मिलकर इस संबंध में पहल की है। हर ग्राम, जनपद एवं जिला पंचायत के विकास की योजनाएं बनाई जा रही हैं। ग्राम पंचायतें अपनी विकास योजना बनाने के दौरान संकल्प लें कि वे अपने गांवों में कौन-कौन से कार्य करना चाहती हैं। साथ ही गत वर्ष लिए गए संकल्पों की पूर्ति की समीक्षा करें। विभिन्न शासकीय विभाग योजनाओं का क्रियान्वयन करें तथा ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायतों द्वारा कार्यों की मॉनिटरिंग हो।

गुरुवार को भोपाल में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती रेखा यादव ने किया।

भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय के सचिव सुनील कुमार ने गुरुवार को सबकी योजना-सबका विकास जन-अभियान वर्ष 2021-22 में मप्र सहित छह राज्य के पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा अन्य संबंधित विभागों के पदाधिकारियों की दो-दिवसीय कार्यशाला में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से यह बात कही। कार्यशाला का आयोजन प्रशासन अकादमी, भोपाल में केंद्रीय, पंचायती राज मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान, हैदराबाद द्वारा किया गया है।

अधिकारी ग्राम सभाओं में समुचित प्रस्तुतिकरण दें: सुनील कुमार ने कहा कि विभिन्न विभागों के अधिकारी ग्राम सभाओं में अनिवार्य रूप से उपस्थित हों तथा विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का समुचित प्रस्तुतिकरण दें। गत दो अक्टूबर से देश में 14 हजार ग्राम सभाएं आयोजित की गई, उनमें अधिकारियों की उपस्थिति संतोषजनक नहीं थी। केवल 42 फीसदी ग्राम सभाओं में ही कृषि विभाग के अधिकारी उपस्थित हुए। इस संबंध में राज्य सरकारों को पत्र भी लिखा जा रहा है।

ई-ग्राम स्वराज पोर्टल

भारत सरकार द्वारा ई-ग्राम स्वराज पोर्टल प्रारंभ किया गया है। इस पर शासन की विभिन्न योजनाओं की जानकारी संक्षिप्त रूप में दर्ज की जा रही है। कार्यशाला में मप्र पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा तैयार की गई सहभागी ग्राम विकास नियोजन प्रक्रिया के संबंध में ट्रेनिंग मैन्युअल का विमोचन एवं ग्राम पंचायत विकास योजना संबंधी लघु फिल्म का प्रदर्शन भी किया गया। शुभारंभ-सत्र में भारत सरकार पंचायती राज मंत्रालय की संयुक्त सचिव श्रीमती रेखा यादव, एनआईआरडीपीआर हैदराबाद के एसोसिएट प्रोफेसर डॉ. केथेरिसन, संचालक पंचायत श्री आलोक कुमार सिंह उपस्थित थे। कार्यशाला में पंचायती राज संस्थानों को सौंपे गए 29 विषयों के संबंध में 18 लियन विभागों के मध्यप्रदेश, पश्चिम बंगाल, पंजाब, उत्तरप्रदेश, हरियाणा तथा बिहार राज्यों के अधिकारी एवं पंचायत पदाधिकारी शामिल हुए।

बेघर परिवारों के लिए वरदान साबित होगी मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना

भोपाल । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आवासीय भू अधिकार योजना लागू करने और ग्रामीण क्षेत्रों में आवासीय भूमि के आवंटन के लिए जिला कलेक्टरों को निर्देश देने को लेकर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस योजना को उन परिवारों के लिए वरदान साबित होना बताया है, जिनके पास घर बनाने के जमीन नहीं है। इस योजना के अंतर्गत ऐसे परिवारों को न सिर्फप्लाट मिलेगा, बल्कि वे उसके आधार पर वे लोन एवं अन्य योजनाओं का लाभ भी ले सकेंगे। प्रदेश अध्यक्ष ने मुख्यमंत्री आवासीय भू अधिकार योजना लागू होने पर मुख्यमंत्री चौहान के प्रति आभार जताया है। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई यह योजना गरीब वर्ग का जीवनस्तर ऊपर उठाने के प्रदेश सरकार के प्रयासों में अगली कड़ी है। श्री शर्मा ने इस योजना के लागू होने पर प्रदेश के नागरिकों को बधाई दी है।

विकास के लिए ग्रामीणों को भी आगे आना होगा

साइकिल यात्रा के पांचवें दिन विधानसभा अध्यक्ष ने ग्रामीणों से कहा

भोपाल (एजेंसी)। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम अपने पांचवें दिन के जनसंपर्क साइकिल यात्रा के दौरान अमिरती, कैछुआ, बहुती एवं सुमेदाकला में ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीणों को भी आगे आना होगा।

गौतम ने इस दौरान कहा कि 31 अक्टूबर को देवतालाब में आयोजित जनकुंभ में सभी ग्रामीण आएं और अपने क्षेत्र की विकास की बाते रखें। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि नईगढ़ी में शीघ्र ही गौ-अभयारण्य, कृषि उपज मंडी और तीन हजार एकड़ क्षेत्र में सोलर पावर प्लांट स्थापित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आमजन एवं ग्रामीणों की समस्याओं का निराकरण करने तथा उनसे सीधा संवाद करने के लिए वे साइकिल यात्रा कर रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष ने अपने पांचवें दिन के जनसंपर्क साइकिल यात्रा के दौरान जोरौट, पहरखा, करही, खटखरी, अमिरती, कैछुआ, बहुती, सुमेदाकला, पथरौड़ा एवं लालगंज में आमजन से सीधा संवाद किया। उन्होंने पांचवें दिन के साइकिल यात्रा के दौरान जोरौट की उचित मूल्य की दुकान का निरीक्षण किया। उन्होंने हितग्राहियों को मिलने वाले खाद्यान्न की मात्रा की तौल अपने सामने करायी तथा आमजन से खाद्यान्न उपलब्धता की जानकारी ली। उपस्थित लोगों ने विधानसभा अध्यक्ष को बताया कि सही समय पर महीने में नियत मात्रा में खाद्यान्न मिल रहा है। गौतम ने पूर्व माध्यमिक विद्यालय खटखरी में छात्रों से पठन-पाठन के विषय में पूछताछ की। उन्होंने ब्लैक बोर्ड के माध्यम से विद्यार्थियों को आवश्यक जानकारी दी तथा सामान्य अध्ययन के बारे में बताया। जोरौट में विधानसभा अध्यक्ष ने भजन मंडली के साथ सुमधुर स्वर में वाद्य बजाकर भजन गया। उन्होंने अमिरती ग्राम में साइकिल यात्रा के दौरान जनसभा में डॉ. अभयराज त्रिपाठी द्वारा बघेली में लिखी गयी किताब 'शहीद कई चिता' का विमोचन कर कहा कि शहीद केदारनाथ का नाम आज के नवयुवक भूल गए हैं, जबकि उनका स्वतंत्रता प्राप्ति में अतुलनीय योगदान था। उन्होंने कहा कि हमारा ध्यान दूसरी तरफ है इसलिए हमारे नवयुवक स्वतंत्रता संग्राम के शहीदों भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, खुदीराम बोस जैसे नायकों के नाम भूलते जा रहे हैं। इस पुस्तक के माध्यम से शहीद केदारनाथ का स्वतंत्रता प्राप्ति में योगदान की जानकारी मिलेगी। उन्होंने कहा कि अपने साइकिल यात्रा के दौरान गुरुवार को पांचवें दिन तक 55 हजार से अधिक लोगों से जीवंत संपर्क कर उनकी समस्याओं एवं कठिनाइयों से रूबरू हुआ और उन कठिनाइयों को दूर किया।

कांग्रेस ने चुनाव आयोग से भाजपा के नेता, मंत्रियों की शिकायत की

भोपाल (एजेंसी)। भाजपा नेताओं एवं मंत्रियों द्वारा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में अभी भी प्रचार करने को लेकर कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग से शिकायत दर्ज कराई है। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री और चुनाव आयोग कार्य प्रभारी जेपी धनोपिया के नेतृत्व में कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात कर भाजपा के नेता एवं मंत्रियों द्वारा खंडवा लोकसभा और रैगांव विधानसभा क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब और नोट बांटने के कृत्य की शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने शिकायत में कहा कि लोकसभा क्षेत्र खंडवा का उपचुनाव 30 अक्टूबर को होना है तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा आचार संहिता प्रभावशील है। खंडवा क्षेत्र के अंतर्गत बागली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के बाहरी नेता रूक कर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसी तरह प्रदेश शासन के मंत्री तुलसी सिलावट द्वारा खंडवा के नेपानगर में प्रचार कर रहे, जोबट क्षेत्र में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, ये सभी नेतागण उक्त क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। अतः उक्त नेताओं और मंत्रियों के विरुद्ध आचार संहिता के उल्लंघन का प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए तथा उन्हें तत्काल क्षेत्र से बाहर किया जाए। वहीं एक अन्य शिकायत में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि रैगांव विधानसभा में प्रचार थमने के बाद भी भाजपा नेता.मंत्री अभी भी चुनाव प्रचार में लगे हुए है, जबकि वे रैगांव विधानसभा क्षेत्र के मतदाता नहीं हैं। इसलिए उनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

शराब और नोट बांटने का लगाया आरोप

निगम मंडलों के अलावा विकास प्राधिकरण सहित अन्य संस्थाओं में नियुक्तियों की प्रतीक्षा

पंचायत चुनाव की आहट, निगम मंडलों में पद की प्रतीक्षा करते दावेदारों में घबराहट

भोपाल (एजेंसी)।

नवंबर में संभावित पंचायत चुनाव की आचार संहिता को लेकर भाग दौड़ शुरू

नवंबर में संभावित बहुप्रतीक्षित पंचायत चुनाव की आचार संहिता को लेकर अब सत्ताधारी दल के अंदर निगम मंडलों से लेकर अन्य संस्थाओं में राजनैतिक नियुक्तियों पाने हलचल तेज हुई है। विधानसभा उपचुनाव के बाद सरकार के समक्ष यह बड़ा चैलेंज भी माना जा रहा है। कारण है कि एक तरफ राज्य सरकार को वित्तीय तालमेल बैठाना है तो दूसरी ओर मर्सी यानि याचना के इन पदों पर अपनों को नवाजना भी बड़ी चुनौती है।

अगर पंचायत चुनाव के पहले यह नियुक्तियां नहीं हो पाई तो फिर लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है। पिछले करीब एक साल से टल रहे पंचायत चुनाव की आचार संहिता नवंबर में संभावित मानी जा रही है। बता दें कि पिछली कमलनाथ सरकार में पंचायत चुनाव कराने की बजाय सरपंचों का कार्यकाल यह कहकर बढ़ाया गया था कि इन्हें काम करने का मौका मिले और पंचायतों का सशक्तिकरण हो। जनवरी 2020 में सरपंचों का कार्यकाल बढ़ाया गया था। इसी दौरान कोरोना का जबरदस्त प्रकोप बढ़ने के कारण पंचायत चुनाव टलते रहे। बढ़े हुए कार्यकाल में मौजूदा सरपंच पंचायतों की व्यवस्था वर्तमान में यथावत देख रहे हैं। अब पंचायत चुनावों को कराने की तैयारी हुई तो निगम मंडलों से लेकर बोर्ड परिषद परिषद विकास प्राधिकरणों में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर भी हलचल का दौर शुरू हुआ है। वजह साफ भी है कि विधानसभा के मौजूदा उपचुनाव के बाद अगर इन संस्थाओं में नियुक्तियां नहीं हुई तो इंतजार की सीमा बढ़ सकती है।

कई संस्थाओं में नियुक्तियों की प्रतीक्षा

बता दें कि प्रदेश में निगम-मंडलों से लेकर विकास प्राधिकरण सहित अन्य संस्थाओं में राजनीतिक नियुक्तियों के लिए लंबे समय से सत्ताधारी भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा इंतजार किया जा रहा है। अगर निगम-मंडलों की बात करें तो नागरिक आपूर्ति, वेयर हाउसिंग और खनिज निगम के अलावा समस्त निगम मंडल खाली पड़े हुए हैं। इनमें पाठ्य पुस्तक निगम, ऊर्जा विकास, हस्तशिल्प, खादी ग्राम उद्योग, हाउसिंग बोर्ड, कुक्कुट विकास, मत्स्य पालन वन विकास, लघु उद्योग, एमपी एग्रो, मदरसा बोर्ड, अनुसूचित जाति वित्त निगम, जनजाति विकास, अंतर व्यवसायी, राज्य सहकारी आवास उपभोक्ता सहकारी संस्था, राज्य सहकारी संघ एवं दुग्ध महासंघ जैसे निगमों में चेयरमैन की नियुक्ति की जाना है। इनमें कुछ निगम ऐसे भी हैं जिनमें राजनीतिक तौर पर प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया जाता है। प्रदेश में 10 लाख से अधिक शासकीय सेवकों की समस्याएं सरकार के समक्ष रखने वाली शासन की मध्यप्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति में भी अध्यक्ष की नियुक्ति की दरकार है।

संस्थाओं में राजनीतिक नियुक्ति पाने के लिए एड़ी चोटी का जोर

जानकारों की मानें तो नवंबर में पंचायत चुनाव की आचार संहिता लगने की उम्मीदों को देखते हुए पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग दौड़ शुरू कर दी है। इसके अलावा पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री भी इन संस्थाओं में कहीं ना कहीं स्वयं या फिर अपने परिजनों एवं नज़दीकियों को बैठाने के लिए गोटियां फिट कर रहे हैं। उपचुनाव वाले क्षेत्रों में भी ऐसे लोगों की बड़ी भीड़ इसलिए भी देखी जा रही है ताकि वहां पर पहुंचते कद्दावर नेताओं के समक्ष अपने कार्य प्रदर्शन का पक्ष रखा जा सके। इनकी चिंता इस बात को लेकर भी है कि अगर पंचायत चुनाव आचार संहिता से पहले नियुक्तियां नहीं होती हैं तो आगे नगरीय निकाय एवं मंडियों के अलावा सहकारिता चुनाव की आचार संहिता लग सकती है। अगर ऐसा होता है तो फिर नियुक्तियों को लंबे समय तक टाला जा सकता है।

नियुक्तियों के बाद वित्तीय गणित संभालना भी सरकार के लिए चुनौती

अधिकारियों की मानें तो कोरोना पर कंट्रोल करने के बाद कमजोर वित्तीय हालातों के दौर से गुजरती राज्य सरकार अगर निगम मंडलों सहित अन्य संस्थाओं में राजनीतिक नियुक्तियां करती है तो उसके लिए राजकोष का गणित संभालना भी बड़ी चुनौती होगी। क्योंकि निगम के एक चेयरमैन की नियुक्ति पर मासिक करीब एक लाख रुपए खर्च होता है। इसमें चेयरमैन के वेतन से लेकर आवास, वाहन, टेलीफोन, बिजली सहित अन्य खर्च शामिल हैं। प्रदेश में तकरीबन एक दर्जन विकास प्राधिकरण एवं 40 ऐसे निगम मंडल हैं जिनमें राजनीतिक तौर पर चेयरमैन की नियुक्ति होती है। मौजूदा समय में प्रशासकीय व्यवस्था के तहत या तो संबंधित विभागों के आईएएस अधिकारी या फिर मंत्री निगम-मंडलों का नियंत्रण संभाल रहे हैं। इन पर सरकार को अतिरिक्त धनराशि का व्यय नहीं करना पड़ रहा है।

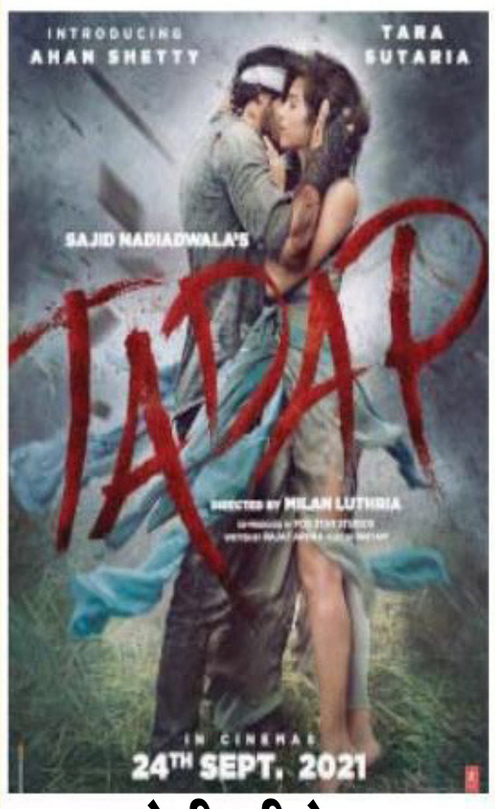

अहान शेट्टी की डेयू फिल्म 'तड़प' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज

फॉक्स स्टार स्टूडियोज़ द्वारा प्रस्तुत और सह-निर्मित साजिद नाडियाडवाला की 'तड़प' घोषणा के बाद से ही चर्चा में हैं। अहान शेट्टी के बड़े बॉलीवुड डेब्यू को चिह्नित करने के अलावा, यह प्रेम गाथा तेलुगु ब्लॉकबस्टर आरएक्स 100 का आधिकारिक हिन्दी रीमेक भी है और सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली पहली बड़ी कैनवास रोमांटिक ड्रामा होगी। रॉ, इंटेंस, पैशनेट और संगीत से भरपूर, फिल्म के ट्रेलर में दर्शकों को दिलचस्प सवारी की एक झलक देखने मिल रही है। मिलन लुथरिया द्वारा निर्देशित, अहान शेट्टी और तारा सुतारिया अभिनीत यह रोमांटिक एक्शन ड्रामा युवा सितारों के बीच इलेक्ट्रिक केमिस्ट्री से भरपूर है। रजत अरोड़ा द्वारा लिखित 'तड़प' आपकी टिपिकल कैंडी फ्लॉस, रन-ऑफ-द-मिल रोमांस की तरह है। यह सच में करैक्टर ड्राईवन है, एक ऐसा प्लॉट जो आपको आपकी सीटों से बांधकर रखेगा। एक तरफ जहां अहान अपनी पहली फिल्म में एक चुनौतीपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, वहीं तारा एक अनकन्वेंशनल करैक्टर निभा रही हैं जिसमें हमें उनका एक अलग पक्ष दिखने मिल रहा है। साथ ही, प्रीतम के सिग्नेचर म्यूजिक ने इस पेशकश को अधिक खूबसूरत बना दिया है। इस फिल्म में अहान इशाना का किरदार निभाएंगे जोकि मंसूरी उत्तराखंड से है। इशाना की मुलाकात रमीसा (तारा सुतारिया) से होती है जोकि विदेश से आई है। दोनों मिलते हैं और एक दूसरे से प्यार कर बैठते हैं। ट्रेलर से एक बात और साफ हो जाती है। फिल्म में अहान और तारा दो अलग अलग धर्मों से हैं और इसी वजह से उनका प्यार आसान नहीं। फिल्म के बारे में बात करते हुए, निर्देशक मिलन लुथरिया ने कहा, तड़प एक डार्क लव स्टोरी है और एक बेहद अनयूजयल डेब्यू फिल्म है। अहान शेट्टी और तारा सुतारिया की लेखक समर्थित भूमिकाएं हैं। उनकी केमिस्ट्री एक ऐसी कहानी में चमकती है जिसमें गहन रोमांस, एक्शन और भावपूर्ण संगीत है। तड़प एक ऑय ओपनर है जो हमारे दर्शकों के बदलते स्वाद को दर्शाता है। एक रोमांचक सवारी के लिए तैयार हो जाइए। निर्माता साजिद नाडियाडवाला कहते हैं, महामारी के बीच दर्शकों के लिए फिल्म के इस रत्न को लाने के लिए बहुत धैर्य और दृढ़ संकल्प की आवश्यकता थी। कहानी, परफॉर्मेंस, मुख्य जोड़ी के बीच केमिस्ट्री और म्यूजिक, सब कुछ 'तड़प' को एक ऐसी फिल्म बनाते है जिसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। फॉक्स स्टार स्टूडियोज द्वारा प्रस्तुत और सह-निर्मित, नाडियाडवाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन की 'तड़प' साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित और मिलन लुथरिया द्वारा निर्देशित है और 3 दिसंबर 2021 में सिनेमाघरों में रिलीज़ होने के लिए तैयार है।

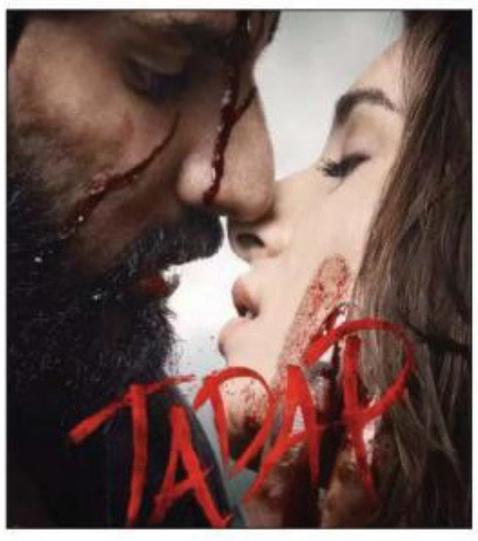

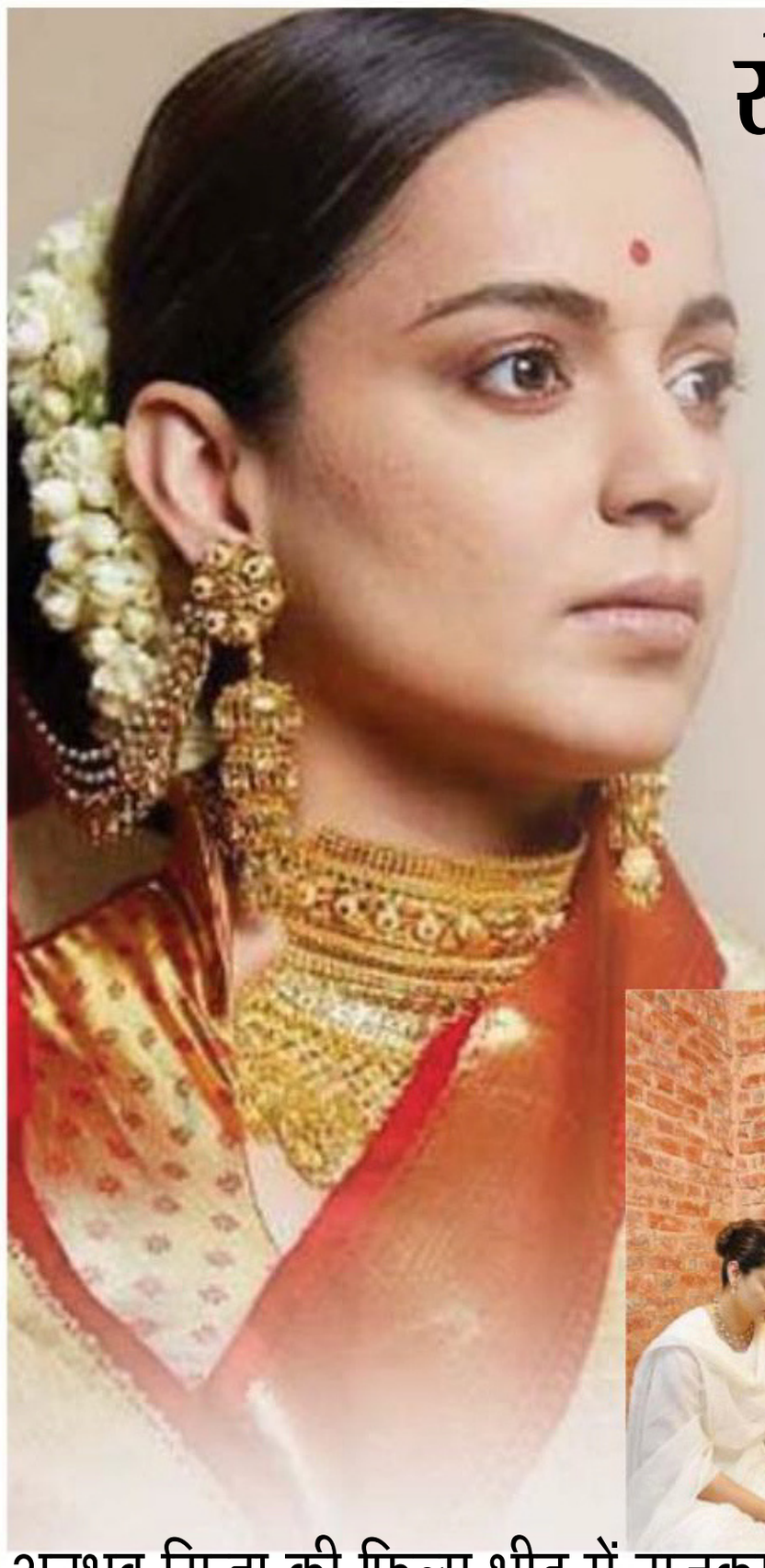

सेलुलर जेल पहुंचीं कंगना रनौट, वीर सावरकर को किया नमन

कंगना रनौट अपनी एक्टिंग के जरिए लाखों दिलों पर राज करती हैं। कंगना ने हाल ही में चौथी बार बेस्ट एक्ट्रेस का नेशनल अवॉर्ड अपने नाम किया है। इसके अलावा वह अपने बेबाक बयानों की वजह से भी चर्चा में रहती हैं। हाल ही में कंगना रनौट अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल पहुंचीं, जहां पर वीर सावरकर ने काला पानी की सजा काटी थी। यहां पर कंगना ने वीर सावरकर को नमन किया। उन्होंने कुछ तस्वीरें भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है। एक तस्वीर में कंगना रनौट वीर सावरकर की तस्वीर के आगे शीश झुकाती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एक अन्य में कंगना ने उस कक्ष की झलक दिखाई है जहां वीर सावरकर कैद थे। कंगना ने जेल की कुछ तस्वीरें और शेयर की है। इन तस्वीरों को शेयर करते हुए कंगना ने लिखा, मैंने अंडमान निकोबार के सेलुलर जेल में वीर सावरकर के कक्ष का दौरा किया। यह देख कर मैं अंदर तक हिल गई। जब अमानवीयता अपने चरम पर थी तब मानवता भी वीर सावरकर जी के रूप में चरम पर पहुंच गई थी। उन्होंने हर क्रूरता का प्रतिरोध किया और दृढ़ संकल्प के साथ सामना किया वे (अंग्रेज) उनसे कितने डरे हुए होंगे जिसकी वजह से उन्होंने वीर सावरकर जी को उन दिनों काला पानी में रखा था। समुद्र के बीच में इस छोटे से द्वीप से बचना असंभव है, फिर भी अंग्रेजों ने वीर सावरकर जी को जंजीरों में डाल दिया, एक मोटी दीवार वाली जेल बनाई और उन्हें एक छोटी काल कोठरी में बंद कर दिया। कंगना ने लिखा, कल्पना कीजिए उस डर का कि वो अनंत समंदर के बीच कहीं हवा में उड़ा ना जाएं। वो लोग कितने कायर थे। यह कोठरी आजादी का सच है, ना कि वो जो हमें किताबों में पढ़ाया जाता है। मैंने कोठरी में ध्यान लगाया और वीर सावरकर जी के प्रति अपनी कृतज्ञता और गहरा सम्मान जताया। स्वतंत्रता संग्राम के इस सच्चे नायक को मेरा कोटि-कोटि नमन। जय हिंद। वर्क फ्रंट की बात करें तो कंगना रनौट आखिरी बार फिल्म 'थलाइवी' में नजर आईं। इस फिल्म में उन्होंने जयललिता का किरदार निभाया है। कंगना जल्द ही तेजस, धाकड़, सीता और मणिकर्णिका रिटर्न्स जैसे फिल्मों में दिखेंगी। इसके अलावा वह 'टीकू वेड्स शेरू' फिल्म प्रोड्यूस कर रही हैं।

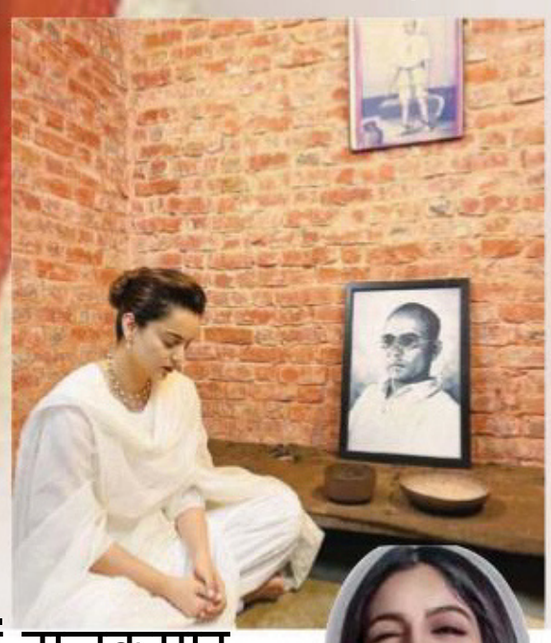

अनुभव सिन्हा की फिल्म भीड़ में राजकुमार राव के साथ नजर आएंगी भूमि पेडनेकर

अभिनेत्री भूमि पेडनेकर फिल्म निर्माता अनुभव सिन्हा की अगली फिल्म 'भीड़' में अभिनेता राजकुमार राव के साथ नजर आएंगी। यह फिल्म सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि पर होगी। इस फिल्म का निर्माण संयुक्त तौर पर सिन्हा और भूषण कुमार कर रहे हैं, जो पहले भी सिन्हा की फिल्म 'थप्पड़' के निर्माण में शामिल थे। सिन्हा 'मुल्क', 'आर्टिकल 15 'जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं। निर्देशक ने कहा ''' पेडनेकर 'भीड़'के किरदार के लिए बिल्कुल सही हैं क्योंकि वह एक ऐसी महिला हैं जिनकी अपनी एक समझ है और यही गुण इस किरदार में चाहिए। उनसे बेहतर कलाकार इसके लिए नहीं मिल सकता।'' पेडनेकर 'सांड की आंख', 'डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे', जैसी फिल्मों में काम कर चुकी हैं। उन्होंने कहा कि वह सिन्हा के साथ इस फिल्म से जुड़ कर सम्मानित महसूस कर रही हैं। इस फिल्म की शूटिंग लखनऊ में होगी, जहां सिन्हा ने हाल में शूटिंग के लिए जगहों की पहचान की है।

आलिया भट्ट और रणबीर कपूर की शादी की खबरों पर सोनी राजदान ने कही यह बात

रणबीर कपूर और आलिया भट्ट बॉलीवुड के फेवरेट कपल में से एक हैं। दोनों की शादी की खबरें भी अक्सर सुर्खियों में बनी रहती हैं। बीते दिनों रणबीर कपूर और आलिया भट्ट को जोधपुर में स्पॉट किया गया था। उनकी तस्वीरें सामने आने के बाद फैंस कयास लगा रहे थे कि दोनों अपनी शादी का वेन्यू देखने जोधपुर पहुंचे हैं। रणबीर कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया था कि वह पिछले साल शादी करने वाले थे, लेकिन लॉकडाउन की वजह से पोस्टपोन करना पड़ा। इस साल भी रणवीर और आलिया की शादी की खबरें छाई हुई है। वहीं अब आलिया की मां सोनी राजदान ने दोनों की शादी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। बॉलीवुड लाइफ को दिए इंटरव्यू में सोनी राजदान ने कहा कि वह खुद नहीं जानती कि दोनों कब शादी करेंगे। उन्होंने कहा, यह तो मुझे भी नहीं पता कि कब होने वाला है। मैं खुद जानकारी की तलाश में हूं। सोनी राजदान ने कहा, ऐसा होने में थोड़ा समय लगेगा, इसमें अभी वक्त है। ये कब होगा ये मुझे नहीं पता बल्कि आप इसके लिए आलिया के एजेंट से बात कर सकते हैं पर मुझे नहीं लगता कि उसे भी पता होगा। वर्क फ्रंट की बात करें तो रणबीर कपूर और आलिया भट्ट जल्द ही साथ में फिल्म 'ब्रह्मास्त्र' में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा आलिया गंगूबाई काठियावाड़ी, आरआरआर और डॉर्लिंग्स जैसी फिल्मों में दिखेंगी। वहीं रणबीर कपूर शमशेरा और एनिमल जैसी फिल्मों में नजर आएंगे।

दिसंबर में बजेगी विक्की कौशल और कैटरीना कैफ के घर शहनाई!

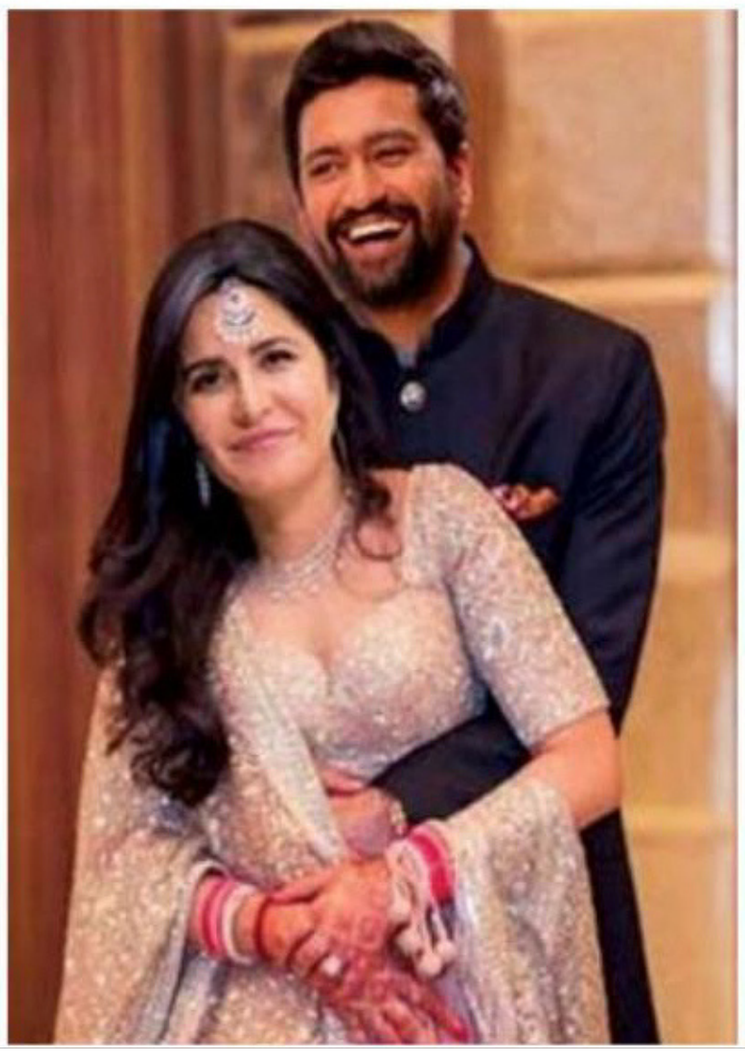

करण जौहर के शो 'कॉफ़ी विद करण' के एक एपिसोड में विक्की कौशल के को लेकर कैटरीना कैफ ने कहा था कि विक्की के साथ ऑन-स्क्रीन उनकी जोड़ी अच्छी दिखेगी। इस कमेंट पर विक्की को शो में बेहोश होने का नाटक करते देखा गया। दोनों की यह चिट-चैट काफी वायरल हुई। किसी ने नहीं सोचा था उस समय की दोनों की यह बातें सच भी होंगी क्योंकि सिनेमा की दुनिया में बहुत कम रिश्ते मुकाम पर पहुंच पाते हैं लेकिन तीन साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अब कैटरीना कैफ और विक्की कौशल शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। ETimes के अनुसार 18 अगस्त को दोनों का रोका हुआ था। अब सूत्रों ने खुलासा किया है कि लवबड्र्स अपने रिश्ते को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। वे जल्दी शादी के बंधन में बंधने वाले हैं! ETimes को पता चला है कि यह जोड़ी अपनी शादी की तैयारी में जुट गयी है। जानकारी के अनुसार शादी के प्रोग्राम नवंबर से शुरू होगे जो दिसंबर तक चलेंगे अभी शादी डेट का खुलासा नहीं हुआ है। उनके शादी के कपड़े सब्यसाची द्वारा डिजाइन किए जा रहे हैं। वे फिलहाल उसी के लिए कपड़े चुनने की प्रक्रिया में हैं। कैटरीना ने अपने पहनावे के लिए एक कच्चा रेशम का लंहगा चुना है। जब से उनके रिश्ते की अफवाहें फैलने लगी हैं, तब से विक्की और कैटरीना इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। उन्होंने एक साथ छुट्टियों पर जाने के बावजूद साथ में तस्वीरें शेयर नहीं की। विक्की को अक्सर कटरीना के घर से आते-जाते भी देखा गया है। हाल ही में दोनों ने विक्की की 'सरदार उधम' की स्क्रीनिंग के बाद सार्वजनिक रूप से एक-दूसरे को गला कर अपने रिश्ते की घोषणा की।

पाकिस्तानी आक्रमण के सामने होगी अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की परीक्षा

एजेंसी ■ दुबई

लगातार दो जीत से उत्साह से ओतप्रोत पाकिस्तान के मजबूत गेंदबाजी आक्रमण के सामने अफगानिस्तान के प्रभावशाली बल्लेबाजों के कौशल और परिपक्वता की टी20 विश्व कप के सुपर 12 के ग्रुप दो में शुक्रवार को यहां होने वाले मैच में कड़ी परीक्षा होगी। भारत और न्यूजीलैंड पर जीत से पाकिस्तान का मनोबल बढ़ा हुआ है लेकिन उसके प्रदर्शन में एकदम से बदलाव देखने को मिलता रहा है जिसका अफगानिस्तान फायदा उठा सकता है। बाबर आजम की अगुवाई वाली टीम निश्चित तौर पर मैच में जीत के दावेदार के रूप में शुरुआत करेगी लेकिन अफगानिस्तान की टीम को हल्के से नहीं लिया जा सकता है। करारे शॉट जमाने वाले बल्लेबाजों और विश्वस्तरीय स्पिनरों की मौजूदगी में वह किसी भी टीम को चुनौती देने में सक्षम है। अफगानिस्तान के बल्लेबाजों ने अपने ताकतवर शॉट के दम पर पिछले मैच में स्कॉटलैंड के गेंदबाजों पर दबदबा बनाया था लेकिन अब उसका सामना ऐसे आक्रमण से है जिसे प्रतियोगिता में सबसे खतरनाक माना जा रहा है। पाकिस्तान के गेंदबाजों के सामने अफगानिस्तान के बल्लेबाज आंख मूंदकर लप्पेबाजी नहीं कर सकते हैं और उन्हें संभलकर बल्लेबाजी करनी होगी। अगर हज़रतुल्लाह ज़ज़ई, रहमानुल्ला गुरबाज़ और नजीबुल्लाह जादरान मैदान के चारों तरफ शॉट जमाने में माहिर हैं तो राशिद खान और मुजीब-उर रहमान जैसे विश्वस्तरीय स्पिनर अफगानिस्तान को एक बेहद संतुलित टीम बनाते हैं। अफगानिस्तान के लिए टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना सबसे अच्छा विकल्प होगा क्योंकि राशिद और मुजीब विश्व के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों पर भी अंकुश लगाने की क्षमता रखते हैं। इसके बाद बल्लेबाज परिस्थितियों के अनुसार रणनीति बना सकते हैं। उनमें जज्बे की कमी नही है लेकिन उन्हें बड़े मैचों का दबाव झेलने का अनुभव नही है। जिस तरह से शाहीन शाह अफरीदी, हसन अली और हारिस रऊफ ने अब तक बल्लेबाजों को परेशान किया है उसे देखकर कहा जा सकता है कि पाकिस्तान की तेज गेंदबाजी की इस तिकड़ी के सामने अफगानिस्तान के बल्लेबाजों की कड़ी परीक्षा होगी। इसके अलावा पाकिस्तान के स्पिन विभाग में अनुभवी ऑफ स्पिनर मोहम्मद हफीज, इमाद वसीम और शादाब खान है जिससे अफगानिस्तान के लिए चुनौती बेहद कड़ी हो गई है। ऐसे में अफगानिस्तान को यदि मैच में जीत दर्ज करनी है तो उसके गेंदबाजों को पाकिस्तानी बल्लेबाजों पर दबाव बनाना होगा। पाकिस्तान के शीर्ष क्रम में कप्तान आजम और मोहम्मद रिजवान ने अब तक अच्छी भूमिका निभाई है। यदि ए दोनों नाकाम रहते हैं तो फखर जमां और मोहम्मद हफीज को जिम्मेदारी संभालनी होगी।

टीमें इस प्रकार हैं :

अफगानिस्तान: राशिद खान, रहमानुल्ला गुरबाज, हजरतुल्लाह जजई, उस्मान गनी, असगर अफगान, मोहम्मद नबी (कप्तान), नजीबुल्लाह जादरान, हशमतुल्ला शाहिदी, मोहम्मद शहजाद, मुजीब उर रहमान, करीम जनत, गुलबदीन नायब, नवीन-उल-हक, हामिद हसन, फरीद अहमद।

पाकिस्तान: बाबर आजम (कप्तान), मोहम्मद रिजवान, फखर जमां, मोहम्मद हफीज, शोएब मलिक, हसन अली, हारिस रउफ, शाहीन शाह अफरीदी, इमाद वसीम, शादाब खान, मोहम्मद नवाज, आसिफ अली, हैदर अली, सरफराज अहमद, मोहम्मद वसीम, सोहैब मकसूद।

मैच भारतीय समयानुसार शाम सात बजकर 30 मिनट पर शुरू होगा।

एक नजर

भारत महिला एशिया कप मे चीन, चीनी ताइपै और ईरान के साथ एक ग्रुप मे

कुआलालम्पुर। मेजबान भारत को 2022 में होने वाले एएफसी महिला एशियाई कप फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए गुरुवार को जारी किए गए ड्रा में चीन, चीनी ताइपै और ईरान जैसी मजबूत टीमों के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। फीफा की रैंकिंग में 57वें स्थान पर काबिज भारत इस ग्रुप में चीन (17वें), और चीनी ताइपै (40वें) के बाद तीसरे स्थान पर आता है। ईरान 72वें स्थान पर है। मलेशिया की राजधानी में एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) के मुख्यालय में ड्रा डाले गए।भारत को 20 जनवरी से छह फरवरी के बीच मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में इस टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है। भारत के मुख्य कोच थॉमस डेनरबाइ ने ड्रा के बाद कहा, यह रोमांचक ग्रुप है। हम अपनी विरोधी टीमों का सम्मान करते हैं। वे सभी मजबूत टीमें हैं जिन्होंने एएफसी एशियाई कप 2022 के लिए क्वालीफाई किया है लेकिन हम किसी भी टीम से खेलने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा, मैं किसी एक मैच को अपने लिए खास नही मानता। ग्रुप चरण के तीनों मैच हमारे लिए खास हैं।

रूबलेव, शापोवालोव सेंट पीटर्सबर्ग ओपन के क्वार्टर फाइनल मे

सेंट पीटर्सबर्ग। स्थानीय खिलाड़ी और मौजूदा चैंपियन आंद्रे रूबलेव और दूसरी वरीयता प्राप्त डेनिस शापोवालोव ने विपरीत अंदाज में जीत दर्ज करके सेंट पीटर्सबर्ग ओपन टेनिस टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। रूबलेव ने सभी सात ब्रेक प्वाइंट बचाकर बेलारूस के इलिया इवाश्का को सीधे सेटों में 6-4, 6-4 से हराया जबकि कनाडाई खिलाड़ी शापोवालोव को पाब्लो एंदुजार पर 2-6, 6-3, 6-0 से जीत के लिए तीन सेट तक जूझना पड़ा। शापोवालोव क्वार्टर फाइनल में जर्मनी के यान लेनार्ड स्ट्रफ से भिड़ेंगे जिन्होंने सातवीं वरीयता प्राप्त अलेक्सांद्र बुबलिक को 6-4, 6-3 से हराया। रूस के करेन खाचानोव और क्रोएशिया के मारिन सिलिच ने भी बुधवार को जीत दर्ज की।

संक्षिप्त खबर

भारत और पाकिस्तान फाइनल में दोबारा आमने-सामने होंगे तो यह शानदार होगा: सकलेन

एजेंसी ■ दुबई

पाकिस्तान के कोच सकलेन मुश्ताक ने गुरुवार को कहा कि उनकी टीम अगर टी20 विश्व कप के फाइनल में भारत से भिड़ेगी तो यह शानदार होगा। उन्होंने मौजूदा टूर्नामेंट के ग्रुप चरण के पहले मुकाबले में भाईचारे का संदेश देने के लिए दोनों टीमों की सराहना की। पाकिस्तान ने रविवार को भारत को 10 विकेट से हराया और सकलेन ने अनुसार दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने अपने खेल आचरण के साथ मानवता का ठोस संदेश दिया। यह पूछने पर कि क्या वह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट के फाइनल में अपने पारंपरिक प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ एक और मुकाबला खेलना चाहते हैं तो सकलेन ने कहा, अगर भारत फाइनल में जगह बनाता है, तो यह शनदार होगा क्योंकि मेरा मानना है कि उनकी टीम मजबूत है और सभी उन्हें प्रबल दावेदार मानते हैं, मैं ऐसा इसलिए नहीं कह रहा कि हमने उन्हें हराया है। उन्होंने कहा, दो मैच खेलेंगे तो रिश्ते और अच्छे हो जाएंगे। सकलेन ने कहा, पिछले मैच में जिस तरह विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी और यहां तक कि हमारे खिलाड़ियों ने आचरण किया, उससे ठोस संदेश जाता है कि हम सभी इंसान हैं, हम सभी एक दूसरे से प्यार करते हैं, यह सिर्फ एक मैच था। उन्होंने कहा, संदेश देने के लिए खिलाड़ियों को श्रेय जाता है। दोस्ती की जीत हो, दुश्मनी की हार हो। सकलेन से यह सवाल शुक्रवार को यहां अफगानिस्तान के खिलाफ होने वाले मैच से पूर्व प्रेस कांफ्रेंस के दौरान पूछा गया। सकलेन ने साथ ही कहा कि वह इंग्लैंड, आस्ट्रेलिया और दक्षिण अफ्रीका को मजबूत दावेदार मानते हैं। उन्होंने कहा, जब आप विश्व चैंपियन बनने आते हैं तो आप विरोधी को नहीं देखते, आप अपने खेल पर ध्यान लगाते हैं।

इंग्लैंड प्रबल दावेदार है, आस्ट्रेलिया कड़ी क्रिकेट खेलता है। दक्षिण अफ्रीका भी। मेरा मानना है कि प्रतिबद्धता, रवैया और प्रक्रिया आपके हाथ में है, नतीजा नहीं। सकलेन ने कहा, आपको अपनी योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में सक्षम होना चाहिए, फिर चाहे आप किसी के भी खिलाफ खेल रहे हों। अगर भारत फाइनल में जगह बनाता है तो आईसीसी खुश होगा, प्रशंसक खुश होंगे। भारत को सुपर 12 चरण के अपने दूसरे मैच में रविवार को न्यूजीलैंड से भिड़ना है।

डिकॉक ने घुटने के बल बैठने को लेकर हुए विवाद को पीछे छोड़ दिया: वाइसी

एजेंसी ■ अबुधाबी

नामीबिया के हरफनमौला खिलाड़ी डेविड वाइसी ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका के विकेटकीपर क्विंटन डिकॉक ने घुटने के बल बैठने के मुद्दे पर अपना रूख स्पष्ट कर विवाद को खत्म कर दिया है। उन्होंने हालांकि कहा कि ऐसे मुद्दों पर निर्णय लेते समय टीमों को एकजुट रहना चाहिए। डिकॉक ने गुरुवार को कहा कि उनके घुटने के बल बैठने से दूसरों को प्रेरित करने में मदद मिलती है तो उन्हें इसमें दिक्कत नहीं है। इससे पहले इस तरह बैठने से इनकार करने पर उन्हें नस्लवादी कहा गया जिससे उन्हें काफी पीड़ा पहुंची। वाइसी ने मीडिया से बातचीत में कहा, उन्होंने (डिकॉक) इसे (विवाद) खत्म कर दिया है और अब हर कोई जानता है कि उन्होंने जो किया उसका क्या कारण था। उन्होंने कारण बताते हुए अपना पक्ष रखा। यहां मौजूद हर व्यक्ति की अपनी मान्यता और किसी मुद्दे पर अपना रूख हो सकता है। उन्होंने कहा, मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जो भी करने का फैसला करते हैं, आप वह फैसला एक टीम के रूप में करते हैं। नामीबिया का प्रतिनिधित्व करने से पहले दक्षिण अफ्रीकी टीम में डिकॉक के साथी रहे वाइसी ने कहा , टीम में एकजुटता होनी चाहिए वह चाहे घुटने के बल बैठने के बारे में हो या पाकिस्तान की टीम के जैसा खड़े होकर दिल पर हाथ रखना हो।

महिला एशिया कप फुटबॉल में भारत को मिला कड़ा ड्रा

एजेंसी ■ कुआलालम्पुर

मेजबान भारत को 2022 में होने वाले एएफसी महिला एशियाई कप फुटबॉल प्रतियोगिता के लिए गुरुवार को जारी किए गए ड्रा में चीन, चीनी ताइपै और ईरान जैसी मजबूत टीमों के साथ ग्रुप ए में रखा गया है। फीफा की रैंकिंग में 57वें स्थान पर काबिज भारत इस ग्रुप में चीन (17वें), और चीनी ताइपै (40वें) के बाद तीसरे स्थान पर आता है। ईरान 72वें स्थान पर है। मलेशिया की राजधानी में एशियाई फुटबॉल परिसंघ (एएफसी) के मुख्यालय में ड्रा डाले गए। भारत को 20 जनवरी से छह फरवरी के बीच इस टूर्नामेंट की मेजबानी करनी है। महिलाओं के इस महत्वपूर्ण टूर्नामेंट के लिए क्वालीफायर्स से चीनी ताइपै, इंडोनेशिया, ईरान, कोरिया, म्यांमार, फिलीपींस, थाईलैंड और वियतनाम ने फाइनल्स में जगह बनाई।

ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 155 रन का लक्ष्य मिला

एजेंसी ■ दुबई

कुसल परेरा और चरिथ असलंका की 35-35 रन की पारियों के बाद आखिरी ओवरों में भानुका राजपक्षे (नाबाद 33) की आक्रामक बल्लेबाजी से श्रीलंका ने आईसीसी टी20 विश्व कप ग्रुप एक के मैच में गुरुवार को यहां ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए छह विकेट पर 154 रन बनाए। परेरा ने 25 गेंद तो वहीं असलंका ने 27 गेंद की पारी में एक समान चार चौके और एक छक्का जड़ा। राजपक्षे ने भी 26 गेंद की नाबाद पारी में चार चौके और एक छक्का लगाया। ऑस्ट्रेलिया के लिए एडम जम्पा, पैट कमिंस और मिशेल स्टार्क ने दो-दो विकेट लिए। इसमें जम्पा काफी किफायती रहे। उन्होंने चार ओवर में सिर्फ 12 रन खर्च किए। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला करने के बाद पैट कमिंस ने तीसरे ओवर में पाथुम निसांका (सात) को डेविड वार्नर के हाथों कैच कराकर श्रीलंका को पहला झटका दिया। शानदार लय में चल रहे चरिथ असलंका ने क्रीज पर कदम रखते ही इस ओवर में लगातार दो चौके लगाने के बाद अगले ओवर में ग्लेन मैक्सवेल का स्वागत छक्के से किया। उन्होंने इसके बाद एक और चौका जड़ा। मैक्सवेल के ओवर से श्रीलंका ने 16 रन जुटाए जिसमें पांच रन वाइड के भी थे। सलामी बल्लेबाज कुसल परेरा ने कमिंस के खिलाफ चौका जड़ा जिससे पावर प्ले में श्रीलंका का स्कोर एक विकेट पर 53 रन हो गया। परेरा ने नौवें ओवर में मार्कस स्टोइनिस के खिलाफ लगातार दो चौके लगाकर रन गति को तेज करने की कोशिश की लेकिन एडम जम्पा ने 10वें ओवर में अपनी फिरकी में असलंका को फंसा लिया। असलंका ने स्वीप करने की कोशिश में स्टीव स्मिथ को आसान कैच थमा दिया। उन्होंने परेरा के साथ दूसरे विकेट के लिए 63 रन की साझेदारी की। कप्तान फिंच ने 11वें ओवर में गेंद मिशेल स्टार्क को थमाई और परेरा ने उनकी दूसरी गेंद पर गगनचुंबी छक्का जड़ दिया लेकिन अगली गेंद पर बोल्ड हो गए।

जम्पा ने 12वें ओवर में अविष्का फर्नांडो (चार) और कमिंस ने 13वें ओवर में वानिंदु हसरंगा (चार) को चलता कर श्रीलंका को चौथा और पांचवां झटका दिया। सोलह रन के अंदर चार विकेट गंवाने के बाद श्रीलंका की रन गति पर अंकुश लगा लेकिन भानुका राजपक्षे ने स्टोइनिस के खिलाफ लगातार दो चौके और फिर छक्का जड़कर 17वें ओवर से 17 रन बटोरे। अगले ओवर में कप्तान दासुन शनाका ने पैट कमिंस के खिलाफ चौका लगाया लेकिन एक और बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेटकीपर मैथ्यू वेड को कैच थमा बैठे। उन्होंने 19 गेंद में 12 रन बनाए।

आखिरी क्षणो मे पेनल्टी गंवाने से यूएई से हारी भारतीय टीम

दुबई। भारत आखिरी क्षणों में पेनल्टी गंवाने के कारण यहां फुजैरा स्टेडियम में मेजबान यूएई के खिलाफ अपने दूसरे एएफसी अंडर-23 चैंपियनशिप क्वालीफायर फुटबॉल मैच में 0-1 से हार गया। दोनों टीमें जब गोलरहित ड्रा की तरफ बढ़ रही थी तब यूएई को 82वें मिनट में पेनल्टी मिली जिसे अब्दुल्ला इदरीस ने गोल में बदला। ग्रुप ई के बुधवार को खेले गए दोनों मैच के परिणाम एक जैसे रहे। ओमान ने भी आखिरी क्षणों की पेनल्टी के दम पर किर्गीज गणराज्य को हराया। भारतीय कोच इगोर स्टिमक ने ओमान के खिलाफ पिछले मैच में 2-1 से जीत दर्ज करने वाली टीम में केवल एक बदलाव किया तथा मध्य पंक्ति को मजबूत बनाने के लिए अनिकेत जाधव की जगह लालेंगमाविया को टीम में रखा। दोनों टीमों ने शुरू में रक्षात्मक रवैया अपनाया। भारत ने आधा घंटे का खेल होने से पहले लगातार हमले किए लेकिन यूएई की रक्षापंक्ति मजबूत थी। राहुल केपी ने आशीष के दाएं छोर से मिले क्रास पर गोल कर दिया था लेकिन भारतीय अभी जश्न मनाते कि रेफरी फु मिंग ने रहीम अली को ऑफ साइड करार दे दिया। यूएई ने दूसरे हॉफ में अधिक आक्रामक रवैया दिखाया। खेल के 49वें मिनट में मारवान फहद के पास गोल करने का मौका था लेकिन धीरज ने अच्छा बचाव किया।

अल्कराज ने में को हराया, क्वार्टर फाइनल में बेरेटिनी से होगा मुकाबला

एजेंसी ■ वियना

एंडी में का एरस्टे बैंक ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पिछले 10 मैचों से चला आ रहा विजय अभियान बुधवार को यहां स्पेन के किशोर खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज से हार के साथ थम गया। आस्ट्रिया के इस इंडोर टूर्नामेंट में में ने इससे पहले 2014 और 2016 में भाग लिया था और दोनों अवसरों पर उन्होंने खिताब जीता था। वह 2016 की जीत से एटीपी रैंकिंग में नंबर एक पर पहुंचे थे लेकिन इस बार उन्हें दूसरे दौर में ही अल्काराज से 6-3, 6-4 से शिकस्त झेलनी पड़ी। अल्काराज क्वार्टर फाइनल में मैटियो बेरेटिनी से भिड़ेंगे। इटली के तीसरी वरीयता प्राप्त बेरेटिनी ने पहला सेट गंवाने के बाद वापसी करके निकोलोज बेसिलशविली को 6-7 (5), 6-2, 6-3 से हराया। पहले दौर के के मैचों में सातवीं वरीयता प्राप्त यानिक सिनर ने अमेरिका के रेली ओपेल्का को 6-4, 6-2 से और आठवीं वरीयता प्राप्त डिएगो श्वार्ट्जमैन ने फैबियो फोगनिनी को 6-2, 7-5 से पराजित किया। पिछले साल फाइनल की अपनी राह में नोवाक जोकोविच को 6-2, 6-1 से हराने वाले लोरेंजो सोनेगो ने पहले दौर के मैच में जर्मनी के डोमिनिक कोफ़र को 6-4, 6-3 से और गेल मोनफिल्स ने इटली के लोरेंजो मुसेट्टी को 7-6 (2), 6-4 से हराया।

बायर्न म्यूनिख की जर्मन कप में सबसे बड़ी हार, ग्लैडबाक ने 5-0 से हराया

एजेंसी ■ बर्लिन

जर्मनी के शीर्ष फुटबॉल क्लब बायर्न म्यूनिख को जर्मन कप में अब तक की अपनी सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा जिससे उसका इस टूर्नामेंट में सफर भी समाप्त हो गया। बोरुसिया मोनचेंग्लैडबाक ने अपने प्रशंसकों के सामने बायर्न को 5-0 से करारी शिकस्त देकर बाहर का रास्ता दिखाया। यह बायर्न की इस प्रतियोगिता में सबसे बड़ी हार है। यह पिछले 43 वर्षों में किसी भी प्रतियोगिता में उसकी सबसे बड़ी हार है। इससे पहले नौ दिसंबर 1978 को बुंदेसलीगा में फोर्टुना डुसेलडोर्फ ने उसे 7-1 से हराया था। ग्लैडबाक ने शुरू में ही तीन गोल दाग दिए थे। उसके लिए कौआडियो कोन ने दूसरे मिनट में गोल करके खाता खोला। इसके बाद रेमी बेंसबैनी ने 15 वें मिनट में मैदानी गोल किया और फिर 21वें मिनट में पेनल्टी को गोल में बदला। ब्रील इम्बोलो ने 51वें मिनट में स्कोर 4-0 किया और फिर इसके छह मिनट बाद अपना दूसरा गोल किया। अन्य मैचों में दूसरे डिवीजन की टीम कार्लजूर एससी ने बायर लीवरकुसेन को 2-1 से हराकर बाहर का रास्ता दिखाया। यूनियन बर्लिन ने वाल्डहोफ मैनहीम पर 3-1 से जीत दर्ज की।

फुटबॉल फीफा विश्व कप के क्वालीफिकेशन के सपने की दिशा मे लंबी और कड़ी यात्रा की तरफ पहला कदम होगा।

एशियाई कप मे अच्छा खेलेंगे तो विश्व कप क्वालीफायर में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिलेगी: रेणु

एजेंसी ■ नई दिल्ली

भारतीय महिला फुटबॉल टीम की स्ट्राइकर रेणु का मानना है कि अगले साल होने वाले एएफसी एशियाई कप में सकारात्मक नतीजे फीफा विश्व कप के क्वालीफिकेशन के सपने की दिशा में लंबी और कड़ी यात्रा की तरफ पहला कदम होगा। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ (एआईएफएफ) के अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने पिछले साल कहा था कि उन्हें लगता है कि भारतीय महिला टीम विश्व कप के लिए पुरुष टीम से पहले क्वालीफाई कर लेगी जिससे देश की महिला खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ा है। रेणु ने बातचीत के दौरान कहा, इस तरह का बयान हमारे लिए काफी प्रेरणादाई है। विश्व कप के लिए क्वालीफाई करना हमारा सपना है। लेकिन अभी हमारा पूरा ध्यान एएफसी एशियाई कप पर है। अगर हम इसमें अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो इससे हमें विश्व कप क्वालीफायर में बेहतर प्रदर्शन करने में मदद मिल सकती है और हम फिर वहां से आगे की राह तय करेंगे। हमारा ध्यान दिन प्रतिदिन सुधार करने पर है। हरियाणा में जन्मी रेणु ने अप्रैल में बेलारूस के खिलाफ मैत्री मैच में।-2 की हार के दौरान स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में भारत की ओर से पदार्पण किया था। इससे पहले 2018 में एएफसी अंडर-19 चैंपियनशिप क्वालीफायर में उन्होंने स्थानापन्न खिलाड़ी के रूप में उतरते हुए पाकिस्तान के खिलाफ पांच गोल दागे थे। बहरीन में अपने से बेहतर रैंकिंग वाली चीनी ताइपे के खिलाफ मैत्री मैच में मनोबल बढ़ाने वाली जीत के दौरान भारत की ओर से रेणु ने एकमात्र गोल किया था। भारतीय महिला टीम ने यूएई और बहरीन के दो हफ्ते के दौरों पर दो-दो मैत्री मैच खेले थे। ए मैत्री मैच भारत में अगले साल जनवरी-फरवरी में होने वाले एएफसी महिला एशियाई कप की तैयारी का हिस्सा थे। हाल के मैचों के प्रदर्शन के बारे में पूछने पर रेणु ने कहा, नतीजों से अधिक हमारा ध्यान अपने प्रदर्शन पर था जो अच्छा रहा। हम इस दौरे से अधिक से अधिक अनुभव हासिल करना चाहते थे। अगला साल भारत में महिला फुटबॉल के लिए काफी महत्वपूर्ण है और देश को एशियाई कप के अलावा फीफा अंडर-17 विश्व कप की मेजबानी भी करनी है। रेणु ने कहा कि यह भारत के लिए अच्छा मौका है कि वह विश्व फुटबॉल में अगले स्तर पर पहुंचने का प्रयास करे।

गांगुली एटीके मोहन बागान के निदेशक मंडल से हटे: आईपीएल सूत्र

एजेंसी ■ नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष सौरव गांगुली संजीव गोयनका के स्वामित्व वाले इंडियन सुपर लीग (आईएसएल) फुटबॉल क्लब एटीके मोहन बागान के निदेशक मंडल से हट गए हैं क्योंकि इस उद्योगपति के इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) की लखनऊ फ्रेंचाइजी के लिए सफल बोली लगाने के बाद हितों के टकराव की स्थिति बन सकती थी। गांगुली 2014 में आईएसएल की शुरुआत के बाद से एटलेटिको-कोलकाता का हिस्सा थे। क्लब को बाद में ए टी के (आमार तोमार कोलकाता) नाम दिया और फिर बाद में दिग्गज क्लब मोहन बागान के साथ उसका विलय हो गया। गोयनका के आरपी-एसजी समूह ने सोमवार को आईपीएल की लखनऊ टीम 7090 करोड़ रुपए में खरीदी। आईसीसी के एक वरिष्ठ सूत्र ने गुरुवार को पीटीआई से कहा, हां, सौरव गांगुली पहले ही एटीके मोहन बागान प्रबंधन को पत्र भेज चुके हैं और उन्हें सूचित कर दिया है कि वह क्लब के निदेशक मंडल का हिस्सा नहीं बन पाएंगे क्योंकि आरपी-संजीव गोयनका समूह अब आईपीएल टीम के मालिक हैं और यह हितों के टकराव का मामला हो सकता है।